दैनिक

आज की जनधारा

सीधी और सच बात, साहस के साथ

डाक पंजीयन 29/2010-2012

वेब संस्करण
www.aajkijandhara.com
www.jandhara.in
Jandhara24x7
@AJandhara/Jandhara24/7
AajkiJandhara & Jandhara24x7
9981126516, 9425203900

तीन राज्यः नई दिल्ली ,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 5 संस्करणः नई दिल्ली ,भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर से एक साथ प्रकाशित

RNI.NO.MPHIN/ 25/A3544

वर्ष : 01, अंक : 245, भोपाल, मंगलवार 7 जुलाई 2026, पृष्ठः 12,मूल्यः 2/- | aajkijandhara.news | aajkijandhara | NewsAkj | अषाढ़ शुक्ल पक्ष-7, वि.सं. 2083

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

चंपतराय और अनिल का इस्तीफा मंजूर

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी प्रकरण में आठ लोगों की गिरफ्तारी और ट्रस्टियों पर गंभीर आरोपों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला किया है।ट्रस्ट ने महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने बताया कि ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक इस्तीफा देते ही वो स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। गोविंद देव गिरि ने कहा कि ट्रस्ट के नियमों में प्राविधान है कि अगर कोई ट्रस्टी इस्तीफा देता है तो उसे स्वतः ही मान्य माना जाता है। इसी कारण चंपतराय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है।

स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार हुआ और परासरन जी के दखल के बाद दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन राम संभालेंगे। 22 जुलाई को एक बार फिर हम बैठेंगे। हम उम्मीद करते हैं तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी।

उस बैठक में हम नए न्यासी की नियुक्ति भी करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद के बीच यह ट्रस्ट की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। बैठक में कई सदस्य संतों ने भारी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद इस्तीफे पर मुहर लगी। बिना बुलाए ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे गोपाल राव को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास ने की।

वो चढ़ावा दिखाया जिनकी चोरी का हुआ था दावा

बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी सामान के गायब होने की बात सही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट ने उन सभी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, जिनके चोरी होने या गायब होने के आरोप लगाए जा रहे थे। सोने की रामचरितमानस, भगवान राम के चरण चिन्ह, हार और काकभुशुंडि को कॉन्फ्रेंस में रखा गया।

भगवान राम भारत की आत्मा के स्रोत हैं

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और श्रीराम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि राम का मतलब राष्ट्र है। वह भारत की आत्मा के स्रोत हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज जो भव्य अयोध्या और श्रीराम मंदिर देश देख रहा है, वह अशोक सिंघल के संकल्प और सपने का परिणाम है। 1980 और 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान पूरे देश में एक ही नारा गूंजता था- रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।सीएम योगी ने कहा कि उस समय एक और नारा युवाओं में जोश भरता था कि मंदिर के काम न आए, ये जवानी बेकार है।

कृष्ण मोहन राम होंगे अंतरिम महासचिव

ट्रस्ट ने सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई के कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत अधिकारी हैं। उन्होंने भी राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर सहमति जताई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि जब तक नए महासचिव की नियुक्ति नहीं होती है तब तक मैं इस पद का निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से हुई चोरी में जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। इस प्रकरण में जो भी हुआ है उस से हम सभी लोग आहत हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां थी।

सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र भोपाल की विकास यात्रा में होगा मंदिर के समान : मुख्यमंत्री

हमारी सरकार खेत से कारखाने और उद्योग को बाजार से जोड़ने के लिए कर रही है कार्य

- सतगढ़ी क्षेत्र भोपाल के आस-पास नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम
- राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ रही है आगे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल को सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। यह इंडस्ट्रियल पार्क देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सतगढ़ी क्षेत्र औद्योगिक विकास की दिशा में एक मंदिर के समान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र हमारे किसानों के लिए भी समृद्धि का द्वार खोलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। गारमेंट इंडस्ट्री से कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार खेत से कारखाने और उद्योग को बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र का भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। समाज के हर वर्ग के लिए एक जैसा होना चाहिए कानून मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक देश - एक विधान - एक निशान - एक प्रधान' की बात कही थी। उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। समाज के हर वर्ग के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यूसीसी मध्यप्रदेश में लागू होगा।

दिल्ली-पंजाब से 6 और आतंकी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और पंजाब से छह और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार सभी आरोपी पाकिस्तान के गैंगस्टर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के एजेंट शहजाद भट्टी के मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं।

स्पेशल सेल ने कार्रवाई के दौरान इस नेटवर्क के दो अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इनमें एक मॉड्यूल आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई पिस्टल और पेट्रोल बम बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मॉड्यूल के सदस्य देश में आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने

पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले बगावत, चन्नी दिल्ली रवाना

- इंचार्ज बघेल की मीटिंग का बायकॉट, 1 सांसद-6 एमएलए का समर्थन, वड़िंग अकेले पड़े

लुधियाना। पंजाब कांग्रेस में खुली बगावत हो गई है। पूर्व सीएम व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी ने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल की मीटिंग का बायकॉट कर दिया है। चन्नी अपने समर्थक सांसदों, विधायकों व पूर्व विधायकों से मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। जहां वे हाईकमान से मिलेंगे। चन्नी समर्थकों ने बघेल को रिसीव तक नहीं किया। बघेल अब साइलेंट बैठे नेता विपक्ष प्रताप बाजवा के घर गए हैं। चन्नी को नया प्रधान बनने के लिए अब तक एक सांसद सुखजिंदर रंधावा और 6 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इसके अलावा नए वर्किंग प्रधान संगत सिंह गिलजियां भी उनके गुट में शामिल हो गए हैं। मौजूदा प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग के पक्ष में सिर्फ एक सांसद डॉ. अमर सिंह आए हैं। कोई भी विधायक उनके समर्थन में नहीं बोला है। चन्नी ने प्रभारी के आने से पहले ही मोहाली में अपने समर्थक नेताओं से मीटिंग की। जिसमें प्रभारी के बायकॉट का फैसला लिया गया। चन्नी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि यह मोरिंडा में हुई पहली मीटिंग की ही कड़ी है। कांग्रेस हाईकमान ने बगावत थामने के लिए बघेल को 5 दिन के लिए पंजाब भेजा है। वह चंडीगढ़ में दोनों गुटों से मीटिंग करने के लिए आए हैं। **सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने दी नसीहतः** वहीं पटियाला से कांग्रेस सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व छ्रूचरणजीत चन्नी को बिना नाम लिए नसीहत दी है।

ब्रीफ न्यूज

अमरनाथ में शिवलिंग 90फीसदी गायब

श्रीनगर। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार एक फीट रह गया है। सोमवार को एक फीट के बाबा बर्फानी की फोटो सामने आई। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। पिछले 3 दिनों में 56 हजार से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से 18.6फीसदी ज्यादा रहा।

लाल किला ब्लास्ट केस अवशेषों की रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किलाब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मृतकों के शरीर के अवशेषों से जुड़ी फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। विशेष एनआईए अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसकी जांच के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। साथ ही पेश किए गए नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

देशभर में 58 टेक्निकल कॉलेज बंद हुए

नई दिल्ली। 2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज फेज वाइज बंद कर दिए गए। इनमें मौजूदा छात्रों को डिग्री पूरी करने दी जाएगी। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में नए एडमिशन नहीं होंगे। यूपी और महाराष्ट्र में 12-12, मप्र में 8 कॉलेज बंद हुए हैं।

निजी कोचिंग सिस्टम खत्म हो

नई दिल्ली। निजी कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को स्कूल शिक्षा से जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोचिंग संस्थानों व डमी स्कूल मॉडल ने समानांतर शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है।

मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बनकर रह गया : राहुल

- राहुल गांधी जयपुर में बस-ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप पहुंचे

जयपुर। राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं। तकनीकी खराबी के कारण बसों में लगने वाली आग का दोष उन कारीगरों पर लगाया जा रहा है, जो केवल गाड़ी की बॉडी तैयार करते हैं। सोमवार को मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

राहुल बोले- छोटे उद्योग बंद होने से रोजगार खत्म हो रहाः राजस्थान के स्थानीय बस और ट्रक बॉडी-बिल्डर्स से मुलाकात के दौरान ऐसा भारत देखने को मिला, जो अपने दम पर रोजगार पैदा करता है। लोहे की चादरें, वेल्डिंग की चिंगारियां, हथौड़ों की आवाज इन सबके बीच कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। जयपुर की बस-ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप में ऐसा भारत दिखता है, जो अपने हाथों से रोजगार भी पैदा करता है और देश की रफ्तार भी तय करता है।

इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी, प्रोटोकॉल तोड़कर अगवानी करने पहुंचे सुबियांतो

जकार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3-देशों की यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां उनका असाधारण और भव्य स्वागत हुआ। इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया, जो कि पीएम मोदी के लिए विशेष सम्मान था। इसके उपरांत, जकार्ता एयरपोर्ट पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने स्वयं प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहने वाले हैं। इस दौरान वे भारतीय समुदाय से मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को चर्चा करने वाले है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यह प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया का चौथा दौरा है और मई 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें उच्च-स्तरीय दौरे, नियमित द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग में गहरा सहयोग शामिल है, इसका एक उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित बिक्री है। एक समुद्री पड़ोसी होने के नाते, दोनों देश 2018 में हिंद-प्रशांत में समुद्री सहयोग के साझा दृष्टिकोण पर सहमत हुए थे, और अब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशियन लाइजन ऑफिसर की तैनाती जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही रक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु इंडोनेशियन कैडेट्स के लिए स्लॉट भी तय किए जाएंगे।

एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी

- पहलगाम आतंकी हमला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को अपनी पूरक (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट में आरोपी बनाया है। एनआईए ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आतंकी साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी ने हमले की साजिश और आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी अतिरिक्त साक्ष्य अदालत में पेश किए हैं। **हाफिज सईद के खिलाफ क्या-क्या आरोप?:** जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने हाफिज सईद पर व्यक्तिगत तौर पर और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व उसके सक्रिय प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के चीफ के तौर पर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, हाफिज सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान से आतंकी साजिश चलाने का आरोप लगाया गया है।

ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 5 की मौके पर मौत

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सोमवार दोपहर आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर ग्राम मेना गोदी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग वाहन के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में निर्माण किया तो जेल, अफसर होंगे जिम्मेदार

राजेश व्यास

उज्जैन, सिंहस्थ-2028 के आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बड़े कानूनी बदलाव की तैयारी में है। सरकार अब मेला क्षेत्र में किसी भी तरह के स्थायी निर्माण को दंडनीय अपराध घोषित करने जा रही है। इसके लिए 1955 से लागू पुराने सिंहस्थ मेला अधिनियम की जगह नया और अधिक सख्त सिंहस्थ एक्ट लाया जाएगा। प्रस्तावित कानून में न केवल अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होगा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला उज्जैन का सिंहस्थ देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है, जहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में विशाल मेला क्षेत्र का सुव्यवस्थित संचालन प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती रहा है। पिछले आयोजनों के दौरान अतिक्रमण और अव्यवस्था की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने इस बार कानून को और अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया है। करीब साढ़े तीन से चार हजार हेक्टेयर में फैले सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अब बिना अनुमति कोई भी स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं, अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों पर होगी। यदि उनकी लापरवाही से अवैध निर्माण या अतिक्रमण होता है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पूरे तंत्र की निगरानी कलेक्टर करेंगे और समय-समय पर रिपोर्ट भी ली जाएगी। सरकार पुराने कानून में व्यापक बदलाव कर रही है। वर्ष 1955 के अधिनियम में जहां केवल 17 प्रावधान थे, वहीं नए सिंहस्थ एक्ट में 50 से अधिक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही वरिष्ठ सचिवों की समिति के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को मोहन कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किए जाने की तैयारी है। नए कानून के तहत मेला अधिकारी की शक्तियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। मेला क्षेत्र की भूमि का अस्थायी अधिग्रहण, व्यवस्थाओं का संचालन और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां मेला अधिकारी के पास होंगी। इस पद पर नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में यह जिम्मेदारी उज्जैन संभाग के आयुक्त निभा रहे हैं। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिग्रहित भूमि केवल सिंहस्थ आयोजन की अवधि तक ही सरकार के पास रहेगी और मेला समाप्त होने के बाद उसे उसके मूल स्वरूप में संबंधित मालिकों को वापस कर दिया जाएगा।प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए एक्ट में दो स्तर की समितियों का प्रावधान किया गया है। पहली केंद्रीय समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित मंत्री करेंगे और इसमें सिंहस्थ से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। दूसरी स्थानीय समिति होगी, जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस सहित विभिन्न विभागों के 15 से 20 अधिकारी सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित कर सकेगी। सरकार का मानना है कि नए सिंहस्थ एक्ट के लागू होने से मेला क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगेगी, प्रशासन की जवाबदेही तय होगी और सिंहस्थ-2028 का आयोजन अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराया जा सकेगा।

देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य

- एमपी पहला ऐसा राज्य, सरकार ने मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को मेंबर बनाया

भोपाल। देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्यप्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को सदस्य बनाया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार का दावा है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं। इससे पहले वक्फ अधिनियम-1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। हालांकि, कुछ सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। 2025 में कानून में संशोधन के बाद पहली बार यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम-से-कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे।

पानी की पाईप लाइन सुधारने के दौरान एक कर्मचारी के ऊपर गिरा सीसी का टुकड़ा

करैयाखेड़ा क्षेत्र का मामला, मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती

आज की जनधारा

विदिशा। नगर पालिका द्वारा नगर में सीवेज लाइन और जल सप्लाई की लाइन अभी कुछ वर्ष पहले ही डाली गई थी, लेकिन हर बार कहीं न कहीं चेंबर ओवर फ्लो होने और सीवेज लाइन चौक होने की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। जिसके कारण से लोगों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 34 का सामने आया है। जहां पर सीवेज लाइन चौक हो रही थी, उसे ठीक करने के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया तो जल सप्लाई की लाइन छूट गई और उसे ठीक करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी सोमवार को पहुंचे और सुधार कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान सीसी सड़क का एक बड़ा टुकड़ा

काम कर रहे मजदूर के ऊपर जा गिरा, जिससे वह उसमें दब गया और अफरा-तफरी मच गई।

यह नजारा देख रहे आसपास खड़े हुए वार्ड के लोगों द्वारा मजदूर को तुरंत ही बाहर निकाला गया। मजदूर को कमर और अन्य जगह चोटें आई है। जिसे इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वार्ड नंबर 34 के पार्षद प्रतिनिधि राजेश लोधी ने बताया कि पिछले कई दिनों से नगरपालिका में सीवेज लाइन को ठीक करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बारिश आते ही नगर पालिका द्वारा सीवेज लाइन ठीक करने के लिए कर्मचारियों को भेजा गया और इसकी खुदाई की गई, जिसके चलते जल सप्लाई की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और पानी बहने लगा। उसे ठीक करने के लिए सोमवार को सुबह नगर पालिका के कर्मचारी आए थे और वह सुधार कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान मोहर सिंह कुशवाह जतरापुरा निवासी नगर पालिका कर्मचारी सुधार कार्य कर रहे थे और वह गड्ढे में नीचे उतरकर उसमें जल सप्लाई की लाइन को ठीक कर रहे थे। इसी दौरान साइड में पानी का रिसाव होने के कारण सीसी का एक बड़ा टुकड़ा उनके ऊपर गिर गया। जिससे वह उसमें दब गए और चीख पुकार होने लगी।

कर्मचारी और आसपास खड़े हुए लोगों द्वारा कर्मचारी को बाहर निकाला गया और इस मामले की जानकारी पार्षद प्रतिनिधि को दी गई। पार्षद प्रतिनिधि द्वारा तुरंत ही नगर पालिका अधिकारी और इंजीनियर सहित अपने अन्य पार्षद प्रतिनिधि साथी संजय अग्रवाल के साथ मौके पर पहुंचे और मजदूर को तुरंत ही एंबुलेंस बुलाकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मजदूर को कितनी गंभीर चोटें आई हैं और कमर में आई चोट कितनी घातक है और उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह डॉक्टर के इलाज के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और गांवों में चलाया व्यापक साइबर जागरूकता अभियान, बताए बचाव के उपाय

आज की जनधारा

विदिशा। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के नेतृत्व में संचालित सेफ क्लिक 2.0 सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित जीवन अभियान के 13वें दिवस पर जिलेभर में व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, हाट-बाजारों, बस स्टैंड, मोहल्लों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक किया।

इसी क्रम में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विदिशा में आयोजित प्रसिद्ध जादूगर प्रिंस के कार्यक्रम स्थल पर भी बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों को सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट एवं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपाय की जानकारी भी दी गई।

अभियान के दौरान थाना कोतवाली द्वारा माधवगंज, पुरानी गल्ला मंडी एवं बस स्टैंड क्षेत्र में आमजन से संवाद स्थापित कर साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। थाना सिविल लाइन द्वारा डी-मार्ट परिसर में नागरिकों को जागरूक किया गया, जबकि थाना यातायात द्वारा विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर साइबर सुरक्षा विषय पर क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

ग्राम सायर में 17 वर्षीय किशोर को सर्प ने डंसा, इलाज के दौरान मौत

आज की जनधारा

विदिशा। करारिया थाना क्षेत्र के ग्राम सायर में दमोह से मजदूरी करने आए मजदूर परिवार के 17 वर्षीय किशोर कद्दू सिंह को रात में सोते वक्त सर्प ने डंस लिया। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन

आज की जनधारा

विदिशा। सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं उनके जीवन एवं कार्यों पर आधरित प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ।

जिला मीडिया प्रभारी डा. राहुल जैन ने बताया कि कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन जिलाध्यक्ष महाराज सिंह दांगी ने दिया। उन्होंने डा. साहब के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प दिलाया। कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार का गठन डा. मुखर्जी को सच्ची

श्रद्धांजलि है। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा ने कहा डा. मुखर्जी की कल्पना को साकार करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया है। विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि आक्रांताओं ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करने के प्रयास को उन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद की भावना से पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। बासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने कहा कि हमें डा. मुखर्जी के सिद्धांत पर आधारित केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प करना है। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे ऐसे दृढ़ निश्चयी डा. साहब की विचार धारा शिरोधार्य है। जिला भाजपा प्रभारी सीताराम यादव ने कहा उन्होंने युवावस्था से राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य प्रारंभ किया। वही संकल्प आज करोड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था।

कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, उसे देश कभी नहीं भूल सकता। आज उनकी 125वीं जयंती पर हमारा यह कर्तव्य है कि आगामी समय में बूथ स्तर तक डॉ. मुखर्जी के विचारों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री एवं प्रभारी रवि सोनी ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला मंत्री गायत्री रघुवंशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय किसान संघ विदिशा की कलेक्टर के साथ बैठक संपन्न

किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

आज की जनधारा

विदिशा। किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक विशेष पहल के तहत सोमवार को कलेक्टोरेट बेतवा सभा कक्ष में भारतीय किसान संघ विदिशा के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में लगभग 2 घंटे तक चली। जिला मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, बिजली विभाग, जल संसाधन, जिला सहकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्हें किसानों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश जारी किए गए।

किसान संघ के प्रतिनिधियों द्वारा तहसील वार अपने-अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। जिलाध्यक्ष प्रशांत जैन ने जिले की सामूहिक समस्याओं को विस्तार से रखा। जिनमें सीमांकन जरीब द्वारा किया जाए, सेटेलाइट रोवर मशीन द्वारा सीमांकन नालों, नदी या दूसरे गांव की सीमाओं के अंदर नपती पहुंच रही हैं एवं किसानों में आपसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है।

किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली के खंबों से खेतों में लटक रहे तारों को व्यवस्थित किया जाए। ई-टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली की समस्याओं को दूर किया जाए (जैसे आईडी पर पूरा रकबा दर्ज न होना और टोकन डिलीट न होना)। बीज प्रदाय योजना की सब्सिडी समय पर दिलाई जाए। जिला सहकारी बैंक में खाद के साथ अन्य सामग्री न देने और प्रबंधक समिति के मुख्यालय पर नहीं बैठने से हो रही परेशानियों को दूर किया जाए। वहीं शासकीय रास्तों पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाए। बेसहारा मवेशियों को गौशालाओं में शिफ्ट कराया जाए, जिससे किसानों की फसलें खराब होने से बच सकें आदि शामिल हैं।

कलेक्टर का अधिकारियों को निर्देश

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने किसान संघ द्वारा अवगत कराई गई इन सभी समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लिया।

उन्होंने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन सभी बिंदुओं पर शीघ्र अति शीघ्र निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं न आने पाए, यह हम सब का नैतिक दायित्व है।

इस दौरान प्रांत मंत्री दिनेश बाबूजी दुबे, प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख एवं विदिशा जिले के जिला प्रभारी राहुल धूत, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य पूरन सिंह यादव, जिला महिला संयोजिका मिथलेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष दीपक धाकड़, ललित पंथी, जिला मंत्री महेंद्र सिंह रघुवंशी, जिला कोषाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शर्मा, जिला युवा वाहिनी संयोजक लाखन सिंह बघेल, जिला जैविक प्रमुख चरण सिंह राजपूत, जिला सह जैविक प्रमुख वीर सिंह रघुवंशी, जिला कार्यकारिणी सदस्य प्राण सिंह रघुवंशी एवं शशि कान्त रिछारिया सहित सभी तहसीलों के अध्यक्ष और मंत्री भी उपस्थित थे।

जिला लोधी महासभा विदिशा ने सौंपा ज्ञापन

आज की जनधारा

विदिशा। सोमवार को लोधी महासभा जिला विदिशा के द्वारा स्वजातीय बंधुओं के साथ लोधी युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत सिंह की दो साल पुराने मामले में बांदरी (सागर पुलिस) द्वारा संदेहास्पद गिरफ्तारी के विरोध में डिप्टी कलेक्टर नितिन जैन को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कलेक्टर अंशुल गुप्ता से मिलकर इस विषय पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर लोधी समाज के जिलाध्यक्ष प्रकाश लोधी ने कहा कि बांदरी थाने के प्रभारी को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए ताकि दूसरी बार कोई ऐसी गलती न करें। इस अवसर पर प्रमुख

रूप से लोधी समाज खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह, प्रदेश सचिव मेहताब सिंह नरवरिया, प्रदेश प्रचार प्रचार मंत्री महेंद्र लोधी, जिला महामंत्री निरंजन सिंह लोधी, दीपू वर्मा, जिला उपाध्यक्ष उमेश लोधी, विष्णु सिंह लोधी, उमेश लोधी, सुरेंद्र लोधी, विकास लोधी, गोलू लोधी, सरपंच हुकुम सिंह लोधी, कोक सिंह लोधी, मुकेश लोधी, शिवराज लोधी, मोहित लोधी सहित अनेक स्वजातीय बन्धु उपस्थित थे।

दियाखेड़ा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी, ग्रामीणों में नाराजगी

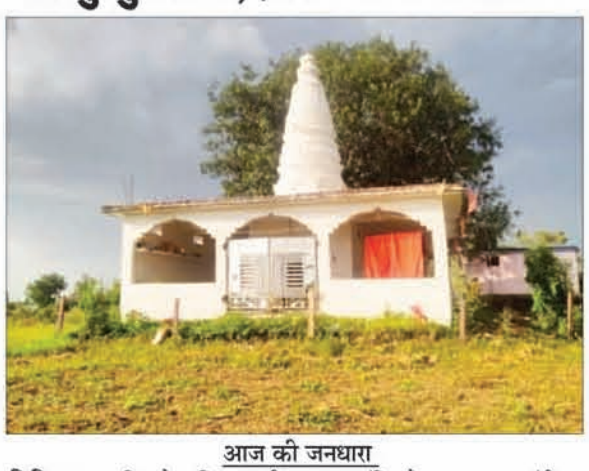

आज की जनधारा

विदिशा। ग्राम दियाखेड़ा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से भगवान का चांदी का मुकुट चोरी होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। पुलिस ने तीन दिन बाद सोमवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास के अन्य मंदिरों में भी चोरी की घटनाएं हुई हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम के बीच अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और भगवान का चांदी का मुकुट चुराकर फरार हो गए। चोरी हुए मुकुट की अनुमानित कीमत 28 हजार रुपये बताई गई है। ग्रामीणों ने आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और मुकुट बरामद करने की मांग की है। ग्राम गोरिया निवासी पुजारी तकलेश शुक्रवार को दिन में पूजा कर गांव चले गए थे। शाम को मंदिर लौटने पर उन्हें मुकुट गायब मिला। ग्राम दियाखेड़ा निवासी जिनेश जैन ने बताया कि थाना में एफआइआर दर्ज कराने के प्रयास किए गए, लेकिन तीन दिन बाद सोमवार को प्रकरण दर्ज हो सका। उन्होंने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी गोकुल प्रसाद अजनेरिया ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मंदिर परिसर या उसके आसपास सीसीटीवी कैमौत, मृत्यु नहीं लगे हैं, जिससे जांच में चुनौती आ रही है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

खेत पर काम कर रही महिला पर गिरी आकाशीय बिजली, इलाज के दौरान मौत

आज की जनधारा

विदिशा। रविवार को ग्राम दुपारिया में खेत पर काम करने के दौरान 40 वर्षीय अनीता कोल निवासी शहडोल के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। उसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

जनशिक्षकों ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, डीपीसी की शिकायत

आज की जनधारा

विदिशा। रविवार को केंद्रीय मंत्री एवं विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान से जिले के लगभग 140 जन शिक्षकों ने मुलाकात कर डीपीसी की कार्य प्रणाली, जन शिक्षकों के साथ किए जा रहे द्वेषपूर्ण व्यवहार, वेतन काटना, जिम्मेदारी न होते हुए उस कार्य का जिम्मेदार ठहराकर नोटिस जारी करना तथा विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जन शिक्षकों पर प्रत्येक कार्य में अनावश्यक एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का अत्यधिक दबाव बनाया जाता है। समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, छोटी-छोटी बातों पर वेतन काटने की चेतावनी दी जाती है तथा भय और दबाव का वातावरण बनाकर कार्य कराया जाता है। इससे जन शिक्षकों में व्यापक असंतोष एवं मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। जन शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजा भैया गुर्जर एवं संतोष द्विवेदी ने उनकी तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। इस अवसर पर कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे ने भी जन शिक्षकों का समर्थन करते हुए न्यायोचित समाधान की मांग की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात गंभीरता से सुनी तथा जन शिक्षकों को विश्वास दिलाया कि प्रस्तुत समस्याओं का परीक्षण कर शासन स्तर पर उचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक | स्कूलों में फर्नीचर व मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा

लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण पर कलेक्टर का जोर

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा शासन द्वारा संचालित अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिटर, सांसद, प्रभारी मंत्री एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त लंबित आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता और

जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाओं एवं अभियानों की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज हो। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, साइकिल, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित शासन द्वारा प्रदाय सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में निर्बाध बिजली आपूर्ति रहे तथा प्रत्येक कक्षा में पंखों की व्यवस्था हो, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

बैठक में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जिले के विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता संबंधी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार जिले के 1,829 विद्यालयों की 5,523 कक्षाओं का परीक्षण किया गया, जिनमें से 3,800 कक्षाओं में विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है, जबकि 1,723 कक्षाओं में अभी भी फर्नीचर की कमी बनी हुई है। वहीं 172 विद्यालयों से सत्यापित फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार विदिशा विकासखंड में सर्वाधिक 913 कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है। इसके बाद सिरोंज में 691, बासौदा में 545, नटेरन में 521 तथा कुरवाई में 508 कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। दूसरी ओर लटेरी विकासखंड की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक पाई गई, जहां 581 में से 369 कक्षाओं में फर्नीचर का अभाव है। सिरोंज में 541, विदिशा में 293, बासौदा में 271, नटेरन में 141 तथा कुरवाई में 108 कक्षाओं में भी फर्नीचर की कमी दर्ज की गई। ग्यारसपुर विकासखंड जिले का एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जहां सभी 410 कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध होने की जानकारी प्रस्तुत की गई।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में फर्नीचर एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में खाद्य, कृषि, उद्यानिकी, श्रम, सहकारिता, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग सहित नगरीय निकायों के कार्यों एवं योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वय बनाकर कार्य करने तथा जनहित के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बेतवा सभागार में संयुक्त कलेक्टरों के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तो वहीं बासौदा विकासखंड में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोडिया मौजूद रहे

माँ आर्यिका सेविका संघ का हुआ गठन

आज की जनधारा

विदिशा। जैन समाज में आर्यिका संघ की सेवा, वैयावृत्ति एवं धार्मिक व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित, अनुशासित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मां आर्यिका सेविका संघ विदिशा (म.प्र.) का विधिवत गठन किया गया। इस अवसर पर धर्मानुरागी महिलाओं की बैठक में सर्वसम्मति से संघ की नियमावली, शपथ-पत्र, सदस्यता प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को अनुमोदित किया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ की सदस्य बनने वाली प्रत्येक पुण्यार्जिका सर्वप्रथम देव, शास्त्र एवं गुरु को साक्षी मानकर शपथ-पत्र के माध्यम से सेवा एवं पुण्यार्जन का संकल्प लेगी। इसके पश्चात अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार आहार, विहार, निहार तथा रात्रिकालीन वैयावृत्ति, इन चार विभागों में से किसी एक अथवा एक से अधिक विभागों में

सेवा का दायित्व निभाएगी। संघ की सदस्यता उन महिलाओं को प्रदान की जाएगी जो जिन धर्म, गुरु एवं संघ के प्रति श्रद्धावान हों तथा संघ की मर्यादा, अनुशासन एवं नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। वार्षिक सदस्यता शुल्क 100 निर्धारित किया गया है। संघ का मूल मंत्र सेवा संस्कार समर्पण रखा गया है। बैठक में सर्वसम्मति से ममता जैन को मां आर्यिका सेविका संघ का अध्यक्ष चुना गया। सहयोगी के रूप में संगीता जयकुमार जैन, सीमा अनिल जैन एवं राखी संजीव जैन को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए।

संघ की नियमावली के अनुसार सभी सदस्य विनम्रता, मर्यादा एवं अनुशासन का पालन करेंगी, संघ के निर्णयों का सम्मान करेंगी तथा किसी भी प्रकार के विवाद, निंदा एवं अनुचित व्यवहार से दूर रहेंगी। आर्यिका माताजी एवं संघ की आवश्यक सेवाओं में निस्वार्थ भाव से सहयोग, समयपालन, शुचिता तथा धर्मभावना के साथ सेवा करना प्रत्येक सदस्य का दायित्व होगा। साथ ही जिनधर्म, जिनवाणी एवं संस्कारों की प्रभावना, धार्मिक जागरूकता तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी।

आज की जनधारा City Dhara

मंगलवार 7 जुलाई 2026. www.aajkijandhara.com

सारनी में मौत को दावत देती कर्मचारी कॉलोनी, टावर गिरने से खुली रखरखाव की पोल

पांच दशक पुरानी इमारतों की हालत खस्ताहाल, कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता से की तत्काल मरम्मत की मांग

भोपाल। सारनी स्थित मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की कर्मचारी आवासीय कॉलोनी की जर्जर हालत एक बार फिर सामने आई है। सोमवार सुबह नगर के जाकिर हुसैन वार्ड क्रमांक-4 स्थित सुपर डी कॉलोनी की एक बहुमंजिला इमारत का ऊपरी टावर अचानक भरभराकर गिर पड़ा। घटना के समय तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस समय टावर गिरा, उस दौरान भवन की सीढ़ियों या आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टावर का मलबा अचानक नीचे गिरने से लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों ने भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक मरम्मत और रखरखाव नहीं कराया गया तो

भविष्य में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। जानकारी के अनुसार यह कर्मचारी कॉलोनी लगभग पांच दशक पूर्व निर्मित की गई थी। लंबे समय से भवनों का समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण अधिकांश आवासों की

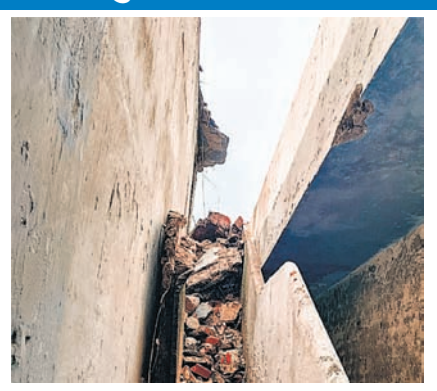

दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, छज्जों का प्लास्टर लगातार झड़ रहा है और कई स्थानों पर भवनों के हिस्से टूटकर गिर रहे हैं। अब टावर गिरने की घटना ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और सिविल विभाग के समक्ष कॉलोनी की मरम्मत कराने की मांग उठाई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। नियमित मेंटेनेंस के अभाव में भवनों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, जिससे यहां रहने वाले परिवार हर समय भय के साये में जीवन बिताने को मजबूर हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए मुख्य अभियंता से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जर्जर भवनों की तकनीकी जांच कराई जाए, आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू किया जाए तथा अत्यधिक क्षतिग्रस्त आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। कर्मचारियों का कहना है कि सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे की अनदेखी भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है।

अमरनाथ यात्रा के लिए बिना रजिस्ट्रेशन पहलगाम पहुंच गए हजारों श्रद्धालु

भोपाल। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के ही हजारों श्रद्धालु जम्मू और पहलगाम पहुंच गए हैं, जहां भारी अव्यवस्था हो रही है। हालात यह हैं कि वहां तत्काल हो रहे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय प्रशासन भी हजारों यात्रियों की भीड़ के सामने बेबस नजर आ रहा है। हालात यह हैं कि पहले टोकन लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुंचते हैं और वहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, लेकिन बताया जा रहा हैकि कई श्रद्धालु जानकारी के अभाव में पहलगाम तक पहुंचने लगे हैं, जिन्हें वापस रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जा

रहा है। जम्मू में राज्य सरकार ने जो पंजीयन केंद्र बनाया है, उसके लिए पहले टोकन लेना पड़ रहे हैं और टोकन में भी 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन की तारीख दी जा रही है। तब तक वहां जाने वाले श्रद्धालु कहीं स्टेशन तो कहीं धर्मशालाओं में रुकने को मजबूर हैं तो कुछ खुले आसमान के नीचे ही इंतजार करते रहते हैं। दरअसल हजारों यात्री इस आस में जम्मू पहुंच गए हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन वहीं हो जाएगा, लेकिन वहां रजिस्ट्रेशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा के 1,379 सवालों के जवाब गायब, अगले सत्र में सरकार से होगा हिसाब

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे गए सैकड़ों सवालों के जवाब वर्षों बाद भी नहीं मिलने का मुद्दा अब राजनीतिक विवाद का रूप लेने जा रहा है। विधानसभा में बार-बार जानकारी एकत्रित की जा रही है लिखकर जवाब देने वाले विभागों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए महत्वपूर्ण सवालों को लंबित रख रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में ऐसे सभी मामलों को दोबारा उठाया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस विधायक पुराने लंबित प्रश्नों की सूची तैयार कर रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विधानसभा में पूछे गए 1,379 प्रश्नों के जवाब अब तक लंबित हैं। इनमें 16वीं विधानसभा के करीब 585 प्रश्न और 15वीं विधानसभा के करीब 794 प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में संबंधित विभागों ने जानकारी एकत्रित की जा रही है या इसी प्रकार के जवाब देकर मामला लंबित रखा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि कई महत्वपूर्ण मामलों में वर्षों बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा के 1,379 प्रश्नों के जवाब आखिर कब मिलेंगे? जानकारी एकत्रित की जा रही है का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या विभाग जानबूझकर संवेदनशील जानकारियां रोक रहे हैं? अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद जवाब लंबित क्यों हैं? क्या आगामी सत्र में सरकार को इन सभी प्रश्नों का हिसाब देना पड़ेगा? आगामी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच बड़े टकराव का कारण बन सकता है। यदि कांग्रेस लंबित प्रश्नों की पूरी सूची के साथ सदन में उतरती है, तो सरकार को केवल जवाब ही नहीं, जवाबों में हुई देरी का कारण भी बताना पड़ सकता है। बजट सत्र में भी यही स्थिति गौरतलब है कि 11 दिवसीय बजट सत्र के दौरान भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा। सत्र के दौरान 79 प्रश्नों के जवाब में जानकारी एकत्रित की जा रही है लिखा गया। इसके अलावा कई प्रश्नों में अधूरी जानकारी दी गई। यह स्थिति महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, लोक निर्माण सहित लगभग 15 विभागों में देखने को मिली। ई-विधानसभा व्यवस्था पर भी सवाल विपक्ष का कहना है कि जब विधानसभा की कार्यप्रणाली डिजिटल हो चुकी है और ई-विधानसभा प्रणाली लागू है, तब भी समय पर जवाब उपलब्ध नहीं होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सरकार जनता से वोट मांगती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने से बचती दिखाई देती है। **मुख्य सचिव की समीक्षा बैठकों का असर नहीं-** हर विधानसभा सत्र से पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होती है, जिसमें संसदीय कार्य विभाग और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। इन बैठकों में लंबित और अपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रश्नों के उत्तर लंबित बने रहते हैं। नतीजतन, कई विभागों की ओर से एक ही पंक्ति दोहराई जाती है जानकारी एकत्रित की जा रही है। **अध्यक्ष के निर्देश भी नहीं करा पाए समाधान-** विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने फरवरी 2024 में व्यवस्था दी थी कि लंबित प्रश्नों के उत्तर संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने यह भी कहा था कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद भी अपूर्ण प्रश्नों के जवाब दिए जाने चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में बाद में जवाब उपलब्ध कराए गए, लेकिन बड़ी संख्या में प्रश्न अब भी लंबित बने हुए हैं। **फॉलोअप प्रश्नों से बढ़ेगा दबाव-** कांग्रेस विधायक अब उन मामलों को दोबारा उठाने की रणनीति बना रहे हैं जिनमें वर्षों से जवाब नहीं मिला है। विधायकों का मानना है कि कई बार एक ही विषय पर अलग-अलग सत्रों में अलग जवाब दिए जाते हैं। इसलिए आगामी सत्र में फॉलोअप प्रश्नों के जरिए विभागों को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

5 रुपये के नोट के बदले 35 लाख का झांसा, साइबर ठग गिरफ्तार 1.04 लाख नकद बरामद

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेशभर में संचालित 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर जागरूकता एवं अपराध नियंत्रण अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से लाखों रुपये का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से ठगी की पूरी राशि 1 लाख 4 हजार 927 रुपये नकद तथा वारदात में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अब मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के नेतृत्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी खिलचीपुर डी.वी.एस. नागर के निर्देशन में थाना माचलपुर पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पुलिस के अनुसार थाना माचलपुर क्षेत्र के ग्राम गौरियाखेड़ा निवासी 21 वर्षीय गोविंद सौंधिया ने

शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने इंस्टाग्राम पर एक वायरल वीडियो देखा, जिसमें दावा किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास पांच रुपये का वह विशेष नोट है, जिसके पीछे ट्रैक्टर चलाते किसान का चित्र बना है, तो उसके बदले 35 लाख 96 हजार रुपये दिए जाएंगे। वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के बाद आरोपी ने खुद को इस सौदे का संचालक बताते हुए विभिन्न प्रोसेसिंग शुल्क, रजिस्ट्रेशन, टैक्स और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग बहानों से भुगतान कराने की बात कही। आरोपी ने फरियादी को कई बार क्यूआर कोड भेजकर पहले 520 रुपये जमा कराए और उसके बाद अलग-अलग किश्तों में लगातार रकम ट्रांसफर कराता रहा। जब आरोपी ने और अधिक पैसे की मांग की तो फरियादी ने अपने चाचा के मोबाइल से भी यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर दिया। इस प्रकार आरोपी ने कुल 14 बार दो अलग-अलग क्यूआर कोड पर भुगतान करवाकर 1 लाख 4 हजार 927 रुपये की ठगी कर ली। जब फरियादी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने थाना माचलपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध

क्रमांक 192/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों, बैंकिंग लेन-देन और मोबाइल नंबरों की जानकारी के साथ मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के अलवर जिले के थाना नौगावा अंतर्गत ग्राम ओदाका निवासी 24 वर्षीय सिकंदर पिता जगदीश वाल्मिकी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से ठगी की पूरी नकद राशि बरामद कर ली गई। साथ ही वीवो और रेडमी कंपनी के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया गया था। पुलिस इन मोबाइलों की फोरेंसिक जांच करा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी बड़े साइबर गिरोह का हिस्सा है या नहीं तथा उसने अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है। इस सफल कार्रवाई में विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक आदित्य सोनी, साइबर प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र अजनारे, थाना माचलपुर पुलिस एवं साइबर टीम के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी में अलवर पुलिस एवं थाना नौगावा की टीम ने भी सराहनीय सहयोग प्रदान किया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले लालच भरे ऑफर, दुर्लभ नोट या सिक्कों के बदले लाखों रुपये मिलने जैसे दावों पर विश्वास न करें तथा किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर भुगतान करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें।

ई-अटेंडेंस के नए नियम पर बिजली कर्मचारियों का विरोध

65 लाख की बायोमीट्रिक मशीनें चालू करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में करीब 20 हजार कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मप्र. बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया है कि आइटी सेल ने बिना किसी लिखित आदेश के मौखिक निदेशों के जरिए अब केवल फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन वाले मोबाइल से ही हाजिरी लगाने की व्यवस्था लागू कर दी है। संगठन का कहना है कि जिन कर्मचारियों के पास ऐसे मोबाइल नहीं हैं, उनकी अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी, जिससे वेतन कटौती का खतरा पैदा हो गया है। संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने बताया कि एक वर्ष पहले एंड्रायड 9 और एंड्रायड 10 वर्जन के मोबाइल भी अमान्य कर दिए गए थे और अब नया नियम लागू किया जा रहा है।

65 लाख की बायोमैट्रिक मशीनें फिर चालू करने की मांग

संगठन ने आरोप लगाया कि कंपनी ने पहले लगभग 65 लाख रुपये खर्च कर सैकड़ों बायोमैट्रिक थंब और आइ-स्कैन डिवाइस खरीदी थीं। ये मशीनें वर्तमान में विभिन्न

कार्यालयों और उपकेंद्रों में उपयोग के बजाय धूल खा रही हैं। संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इन्हीं बायोमैट्रिक मशीनों का दोबारा उपयोग शुरू किया जाए।

आंदोलन की चेतावनी

संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने चेतावनी दी है कि यदि मोबाइल आधारित नई ई-अटेंडेंस व्यवस्था वापस नहीं ली गई तो कर्मचारी संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। उनका कहना है कि नए नियम से कर्मचारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

शहरभर में निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, ठेले-काउंटर जब्त, अवैध कब्जे हटाए

भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान जारी रखते हुए सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। सीएम हेल्पलाइन, महापौर हेल्पलाइन तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ नियमित अभियान के तहत सड़क, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान ठेले, काउंटर और प्लास्टिक टेबल जब्त किए गए। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कोलार, चूना भट्टी, ललिता नगर, नेहरू नगर, न्यू मार्केट, एमपी नगर, हमीदिया रोड, लालघाटी, गांधीनगर, पुष्पा नगर, अवधपुरी, संजय नगर सहित अनेक क्षेत्रों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर रखा सामान हटाया गया तथा संजय नगर में अवैध रूप से निर्मित एक दीवार को तोड़ा गया। निगम अमले ने पुष्पा नगर और अवधपुरी में नालियों पर रखी अवैध फर्शियां हटाईं। वहीं लालघाटी, प्रभात चौराहा और अन्य क्षेत्रों से आवागमन में बाधा बन रहे जनरेटर, चार पहिया एवं लोडिंग वाहनों को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान निगम ने 5 ठेले, 2 काउंटर और 2 प्लास्टिक टेबल जब्त किए। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करने वालों

के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर में यातायात सुगम रहे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस का हमला, हाई कोर्ट जाएंगी मीनाक्षी नटराजन

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में समझौता (कॉम्प्रोमाइज) हुआ है और कांग्रेस इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका (इलेक्शन पिटिशन) दायर करेगी। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पार्टी की लीगल टीम इस मामले पर काम कर रही है और परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर याचिका दायर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ना तो नामांकन पत्र में कोई गलती थी और ना ही हमारे किसी साथी से कोई चूक हुई। जब फार्म-16 में नोटिस के उल्लेख का कोई कॉलम ही नहीं है, तो उसके आधार पर नामांकन निरस्त करना यह साबित करता है कि यह एक षड्यंत्र था। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को हर स्तर पर लड़ेगी, क्योंकि यह मामला केवल एक सीट का नहीं, बल्कि पूरी चुनाव व्यवस्था की

निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि इसी तरह नामांकन निरस्त किए जाते रहे, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। पेपर लीक और राम मंदिर चंदा मामला पर बरसीं मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि देश और प्रदेश के सामने अभी तीन बड़े गहरे संकट हैं। जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ, वैसे ही भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पेपर लीक हो गए। छात्र और उनके अभिभावक वर्षों का संघर्ष करते हैं लेकिन जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसको लेकर कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

सरकारी से 8 गुना महंगा है निजी अस्पतालों में इलाज

भोपाल। बीमारी अब केवल स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि आर्थिक संकट की भी वजह बनती जा रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2025 की घरेलू सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य रिपोर्ट बताती है कि निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च इतना बढ़ चुका है कि आम और मध्यम वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार कराना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसके विपरीत, सरकारी अस्पताल आज भी कम खर्च में इलाज उपलब्ध कराकर लाखों परिवारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज को औसतन 50 हजार 508 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। वहीं सरकारी अस्पताल में

यही खर्च औसतन छह हजार 631 रुपये है। यानी निजी अस्पताल में इलाज सरकारी अस्पताल की तुलना में लगभग आठ गुना महंगा पड़ रहा है। वहीं देशभर में अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज का औसत आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च 34 हजार 064 रुपये है, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। भोपाल में भी यही तस्वीर राजधानी भोपाल में भी स्वास्थ्य सेवाओं की यही तस्वीर सामने आ रही है

मप्र के 24 जिलों पर सूखे का खतरा

कम बारिश के संकेत मिलते ही तैयार हुआ ड्रॉट एक्शन प्लान, फसल, बीज और सिंचाई की नई रणनीति लागू

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की धीमी रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी 55 जिलों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन बारिश का वितरण असमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान और अल नीनो जैसे वैश्विक मौसमी प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार ने 24 जिलों को संभावित सूखा प्रभावित क्षेत्र मानते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार कर ली है। सबसे अधिक चिंता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन को लेकर है, जहां सामान्य से सबसे कम वर्षा होने की आशंका जताई गई है। सरकार ने कृषि, राजस्व, जल संसाधन और पंचायत विभागों को संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव की रणनीति लागू करने के निर्देश दिए हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार

इस वर्ष मध्य प्रदेश में सामान्य वर्षा का केवल 90 से 94 प्रतिशत ही होने का अनुमान है। प्रदेश में 1 जून से 1 जुलाई के बीच जहां सामान्य वर्षा 139.7 मिमी होनी चाहिए थी, वहीं केवल 92.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। यानी लगभग 47 मिमी की कमी रही। कई जिलों में वर्षा का घाटा 20 से 40 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जुलाई और अगस्त में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार किसानों को कम अवधि और कम पानी वाली फसलें अपनाने की सलाह देगी। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ाने पर जोर रहेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, वैकल्पिक फसल चयन कराया जाएगा। रिज एंड फरो, रेज्ड बेड और डायरेक्ट सीडेड राइस जैसी वैज्ञानिक खेती तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कम पानी में भी उत्पादन प्रभावित न हो। सरकार का ड्रॉट एक्शन प्लान तैयार संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पहले ही व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने संभावित सूखे से पहले ही कृषि और राजस्व विभाग को संयुक्त कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 24 जिलों के लिए विशेष एडवाइजरी तैयार की गई है। सात जिलों में विस्तृत माइक्रो प्लानिंग होगी और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लगातार तकनीकी निगरानी की जाएगी। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह मोबाइल, सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों से दी जाएगी। जिला स्तर पर अधिकारियों को हालात की रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा संवेदनशील सरकारी आकलन के अनुसार उज्जैन संभाग में वर्षा की कमी सबसे अधिक रहने की संभावना है। इसी वजह से यहां वैकल्पिक फसल योजना, कम अवधि वाली किस्में, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, बीज वितरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कृषि विभाग किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलें अपनाने की सलाह देगा।

जंगल बचाने के लिए कोरकू समाज का महाआंदोलन

भोपाल। खंडवा और बुरहानपुर जिले के कोरकू समाज ने 13 जुलाई को खंडवा में महाआंदोलन करने का आह्वान किया है। आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार के साथ ही गांव-गांव में बैठकें ली जा रही हैं। उनके द्वारा जंगल क्षेत्र में बाहरी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वन विभाग की कार्रवाई के समर्थन में बड़ी संख्या में समाजजन जुटेंगे। आंदोलन 13 जुलाई को सुबह 10 बजे खंडवा में शुरू होगा और आंदोलन समाप्त होने तक जारी रहेगा। इसे कोरकू समाज, खंडवा-बुरहानपुर की ओर से आयोजित होना बताया गया है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए कोरकू समाज संगठन ने खंडवा और बुरहानपुर जिले के गांव-गांव में बैठकें शुरू कर दी हैं। समाज के पदाधिकारियों के अनुसार, बुरहानपुर जिले से भी बड़ी संख्या में समाजजन आंदोलन में शामिल होने के लिए खंडवा पहुंचेंगे। संगठन का दावा है कि करीब दो हजार समाजजन खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

न्यूज । ब्रीफ

किसान भाई जैविक एवं प्राकृतिक खेती कर मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण को बचाएं तथा मिनी किट का उपयोग बीज बनाने के लिए करें -सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी

दमोह। सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी के मुख्य आतिथ्य में बगिया परिसर हिंडोरिया में कृषक संवाद एवं निःशुल्क मिनी किट बीज वितरण का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा किसान बंधु जैविक एवं प्राकृतिक खेती कर मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण को बचाएं तथा मिनी किट का उपयोग बीज बनाने के लिए करें, रासायनिक खेती से कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं इस बारे में सभी किसान बंधुओ को चिंतन करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान गोपाल पटेल ने कहा जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध है, किसान बंधु किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें एवं मिनी किट का उपयोग बीज बनाने के लिए करें। इस अवसर पर उपसंचालक कृषि जे.एल. प्रजापति ने बताया आत्मनिर्भरता दलहन मिशन योजना अंतर्गत निशुल्क उड़द एवं अरहर के बीज के सबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में गोपाल पटेल, महाराज सिंह लोधी, नरेश पटेल, देवेंद्र सिंह ठाकुर, जगदीश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक गण, किसान बन्धु, अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद रहे।

साइबर अपराधों से बचाव के लिए जनजागरूकता मैराथन का शुभारंभ, एसपी बोले- जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच

कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक और परिवार को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने कहा डिजिटल इंडिया के दौर में पारंपरिक अपराधों की अपेक्षा साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले जहां चोरी, नकबजनी और अन्य सामान्य अपराध अधिक देखने को मिलते थे, वहीं अब अपराधी दूर बैठकर मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए आम नागरिकों को जागरूक करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से आयोजित मैराथन का शुभारंभ तहसील ग्राउंड से किया गया।

सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया

उन्होने नागरिकों से अपील की गई कि वे किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक अथवा फर्जी डिजिटल लेनदेन से सतर्क रहें, अपनी बैंकिंग एवं व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर अपराधों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर जागरूकता मैराथन को तहसील ग्राउंड से सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड एवं सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संजय यादव, गौरव पटेल, सुरेश पटेल, रमाकांत बाजपेई, वर्षा रैकवार, बृजेंद्र अहिरवार, रिंकू गोस्वामी, दीपक मिश्रा, सिकंदर खरारे, सृजन असाटी, संजय गौतम, एडवोकेट कमलेश भारद्वाज, डॉ. श्री संगतानी, शिवेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी, सम्मानीय मीडियाजन उपस्थित रहे।

सेफ क्लिक 2.0' अभियान का शुभारंभ, दमोह में साइबर जन-जागरूकता मैराथन आयोजित

साइबर ठगी से बचाव के लिए 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत करने की अपील

आज की जनधारा

दमोह। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में प्रारंभ किए गए 'सेफ क्लिक' अभियान के दूसरे चरण 'सेफ क्लिक 2.0' का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में दमोह पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन तहसील ग्राउंड से प्रारंभ होकर बेलाताल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट, स्टेडियम, किल्लाई नाका, बस स्टैंड और कीर्ति स्तंभ होते हुए पुनः तहसील ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम और नागरिकों को जागरूक करने के लिए लगातार नवाचार कर रही है। दमोह पुलिस द्वारा आयोजित यह मैराथन अभियान भी उसी दिशा में एक प्रभावी प्रयास है, जिससे समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। इस आशय के विचार दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने साइबर अपराधो के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील ग्राउंड में आयोजित सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन के दौरान व्यक्त किए। सांसद श्री लोधी ने कहा पुलिस विभाग ने नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध कराया है। यदि किसी भी व्यक्ति को साइबर अपराध या अन्य किसी प्रकार की पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, तो वह दिन हो या रात, किसी भी समय हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर संपर्क कर सकता है। मध्यप्रदेश पुलिस हर परिस्थिति में नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है, उन्होने सभी नागरिकों से अपील की कि वे साइबर अपराधों से सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें तथा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों में सक्रिय सहभागिता निभाकर सुरक्षित डिजिटल समाज के निर्माण में सहयोग करें। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने कहा वर्तमान समय में साइबर क्राइम और डिजिटल अपराध अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। इनके कारण अनेक सुखी एवं समृद्ध परिवार भी आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित होकर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम, जनजागरूकता बढ़ाने तथा लोगों को भयमुक्त करने के उद्देश्य से जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया है।

25 साल का इंतजार खत्म: पड़ाना स्वास्थ्य केंद्र को मिली पहली महिला एमबीबीएस डॉक्टर

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ाना में पहली बार महिला एमबीबीएस चिकित्सक की पदस्थापना होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लगभग 25 वर्ष बाद डॉ. अभिलाषा चौधरी ने मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह सिविल अस्पताल सारंगपुर में पदस्थ थीं। हाल ही में उन्होंने पड़ाना अस्पताल में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। महिला चिकित्सक के आगमन पर अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष शरीफ मंसूरी सहित प्रद्युम्न परमार, कैलाश टेलर, मुकेश जलोदिया, संतोष चतुर्वेदी, रघु परमार, दिनेश परमार और सतीश गोस्वामी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पड़ाना का छह बिस्तरों वाला शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 1998 में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ था। नगर सहित मगराना, रामपुरिया, साधनखेड़ी, मऊ, आसारेटा, पंवार, करौंदी, टीकोद सहित दर्जनों गांवों के करीब 50 हजार से अधिक लोग उपचार के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। इसके बावजूद यहां आज तक किसी महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी। इसका सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ता था, जिन्हें स्त्री रोग, प्रसव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सारंगपुर, शुजालपुर, शाजापुर अथवा निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। महिला डॉक्टर की नियुक्ति से अब ग्रामीण महिलाओं को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और किशोरियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। बच्चों के टीकाकरण और महिला स्वास्थ्य सेवाओं को भी इससे मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला चिकित्सक के अभाव में कई बार प्रसूताओं को समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता था। वर्ष 2020 में डिलीवरी के दौरान दो महिलाओं की मौत के मामलों ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद अधिकांश गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए बाहर के अस्पतालों का सहारा लेने लगी थीं। स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय तक प्रशिक्षित एएनएम लक्ष्मी जाट प्रसव सेवाओं की जिम्मेदारी संभाल रही थीं, लेकिन हाल ही में उनका तबादला टीकोद उपस्वास्थ्य केंद्र कर दिया गया। इसके बाद से एएनएम का पद रिक्त है। वर्तमान में अस्पताल में नर्स ज्योति पालीवाल, फार्मासिस्ट सीमा पाटीदार और लैब टेक्नीशियन पदस्थ हैं, जबकि बढ़ती आबादी के अनुपात में अन्य आवश्यक स्टाफ की कमी बनी हुई है। ग्रामीण नानासाहब परमार, नाहर सिंह गुर्जर, संतोष चतुर्वेदी, नारायण परमार, सौरभ परिहार, जितेंद्र खाती सहित अन्य लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि महिला डॉक्टर की नियुक्ति के साथ-साथ रिक्त एएनएम पद सहित अन्य आवश्यक स्टाफ की भी शीघ्र पूर्ति की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें। डॉ. मनीष चौहान, बीएमओ सारंगपुर ने बताया कि पड़ाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक डॉ. अभिलाषा चौधरी की पदस्थापना हो चुकी है। एएनएम की व्यवस्था के लिए भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, ताकि जल्द आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

राजगढ़ पुलिस का सम्मान समारोह, बोड़ा थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत को मिला प्रशस्ति-पत्र

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। राजगढ़ पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिले में अपराध नियंत्रण, प्रभावी विवेचना और बेहतर पुलिसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर बोड़ा थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत को पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण पुलिस की प्राथमिकता होना चाहिए। साथ ही चोरी और नकबजनी जैसी घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने तथा आमजन के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण, नियमित पुलिस चौपालों के आयोजन, यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, सेफ क्लिक 2.0 अभियान को गति देने तथा साइबर अपराधों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सम्मान प्राप्त करने के बाद थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत ने इसे पूरी बोड़ा थाना पुलिस टीम की मेहनत और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। उनके सम्मानित होने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों,

सामाजिक कार्यकताओं एवं नागरिकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

स्मार्ट मीटर विवाद गरमाया: कांग्रेस का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, एफआईआर वापस लेने की मांग

आज की जनधारा

पचोर /राजगढ़। स्मार्ट मीटर को लेकर जिले में चल रहा विवाद सोमवार को राजनीतिक रंग ले गया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नगर कांग्रेस अध्यक्ष नयन विजयवर्गीय के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को निराधार बताते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना था कि अनेक उपभोक्ताओं की शिकायत है कि नए मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों ने यह भी शिकायत की है कि कम या बिना उपयोग के बावजूद मीटर अधिक खपत दर्ज कर रहे हैं, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष नयन विजयवर्गीय जनता की

समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उन्हें ही झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया गया। उनका दावा था कि प्रदर्शन के दौरान हटाए गए स्मार्ट मीटर कुछ लोग स्वयं उनके पास लेकर पहुंचे थे और वे केवल उपभोक्ताओं के साथ विभागीय कार्यालय तक गए थे। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रियव्रत सिंह खींची ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध करने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप था कि जनहित के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस कार्यकताओं को प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए डराने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की कि नयन विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कर उसे निरस्त किया जाए तथा जिले में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की कार्यप्रणाली और उपभोक्ताओं की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और झूठे प्रकरण वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। प्रदर्शन में पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, बापू सिंह तंवर, रामप्रसाद दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र पंवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

डिजिटल प्रशिक्षण में पचोर मंडल ने रचा कीर्तिमान, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित सम्मानित

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रशिक्षण अभियान में पचोर मंडल ने जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्यकताओं को डिजिटल माध्यमों का प्रशिक्षण देकर पचोर मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिसके लिए मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानसिंह गुर्जर, सांसद रोडमल नागर, जिला प्रभारी ध्रुवनारायण सिंह, विधायक मोहन शर्मा, हजारीलाल मालवीय सहित जिला पदाधिकारी एवं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने पचोर मंडल की सक्रिय कार्यशैली की सराहना करते हुए इसे संगठन की बड़ी उपलब्धि बताया। सम्मान प्राप्त करने के बाद

मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित ने कहा कि डिजिटल प्रशिक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल की पूरी टीम ने बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि सभी पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों और कार्यकताओं के सामूहिक प्रयास एवं बेहतर समन्वय के कारण यह सफलता संभव हो सकी। उन्होंने इस उपलब्धि का

श्रेय विधानसभा प्रभारी घनश्याम नागर, मंडल प्रभारी जगदीश नागर, मंडल महामंत्री सुदर्शन कृष्ण सोनी, अमित गोस्वामी, अरुण खत्री, प्रशिक्षण प्रभारी सतीश राठौर, अरविंद नागर, होकम नागर, सुनील नागर, सभी शक्ति केंद्र संयोजकों, बूथ अध्यक्षों एवं सक्रिय कार्यकताओं को देते हुए उनके योगदान की सराहना की।

बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश की क्विज होगी आयोजित

आज की जनधारा

दमोह। जिले में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के मार्गदर्शन में 7 अगस्त को ₹बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश₹ की जिला स्तरीय क्विज का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। पर्यटन क्विज-2026 क्विज में पूछे जाने वाले प्रश्न मध्य प्रदेश के पर्यटन, कला, संस्कृति, धार्मिक, प्राकृतिक परिवेश और ऐतिहासिक संवर्धन पर आधारित होंगे। जिला स्तर पर प्रतियोगिता दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित शीर्ष 06 टीमों के मध्य द्वितीय चरण में 'ऑडियो-विजुअल मल्टीमीडिया' आधारित क्विज का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को पर्यटन के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले की प्रथम तीन विजेता टीमों को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की होटलों में 2 रात्रि एवं 3 दिवस के निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का कूपन प्रदान किया जाएगा। अगली तीन उपविजेता टीमों को 1 रात्रि एवं 2 दिवस के निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का कूपन दिया जाएगा। इन कूपनों के अंतर्गत विद्यार्थियों के आने-जाने, आवास, भोजन तथा स्थानीय भ्रमण का संपूर्ण व्यय मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विविधताओं, कला, प्राकृतिक संपदा और पर्यटन की असीम संभावनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 'पर्यटन क्विज-2026' का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 01 से 25 जुलाई 2026 तक शाम 5:30 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट **https:// www.mptourism.com/tourismquiz2026/schools/** के माध्यम से किया जा सकता है। इस क्विज में प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई एवं केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं के अध्ययनरत छात्र-छात्राएं सहभागिता कर सकते हैं।

रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह नए स्वरूप में प्रदेश स्तर का जिला स्तरीय प्रथम संग्रहालय होने की दशा में प्रगतिशील

आज की जनधारा

दमोह। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह मार्गदर्शक डॉ सुरेंद्र चौरसिया ने बताया 1 वर्ष पश्चात संपूर्ण कार्यों की पूर्णता उपरांत, रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह नए स्वरूप में प्रदेश स्तर का जिला स्तरीय प्रथम संग्रहालय होने की दशा में प्रगतिशील है। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के अधीन संचालित रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह विगत 3 दशक पूर्व 25 अगस्त 1989 को तत्कालीन गवर्नर सरला ग्रेवाल जी ने इसका प्रारंभ /सूत्रपात किया था तब से अनवरत दर्शक सुविधाओं तथा इतिहास पुरातत्व के विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिए विकास क्रम के नवाचार में रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के विकास एवं उन्नयन के कार्य विगत 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए थे आने वाले 1 वर्ष तक और यह विकास का क्रम संचालित होगा विस्तृत योजनावद्ध चरणों के माध्यम से नवीनतम एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करने में लगातार कार्य गतिशील हैं।

शिक्षा और पीएम पोषण योजना की समीक्षा, लापरवाही पर अधिकारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। जिले में शिक्षा व्यवस्था और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के प्रभावी संचालन को लेकर सोमवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. इच्छित गढ़पाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में शिक्षा विभाग के जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी, बीआरसी, जनशिक्षक तथा पीएम पोषण योजना के गुणवत्ता मॉनिटर शामिल हुए। समीक्षा के दौरान डॉ. गढ़पाले ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अप्रैल और जून माह का खाद्यान्न उठाव बिना किसी देरी के शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रतिदिन गर्म, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन का नमूना सुरक्षित रखने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और रसोई की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में माँ की बगिया को सक्रिय रखते हुए सब्जियों का

उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य का निरीक्षण स्वयं उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही विद्यालय परिसरों में अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों की मैपिंग, अपार आईडी निर्माण, प्रवेश अभियान, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा ड्रॉप बॉक्स से जुड़े लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी लंबित प्रकरण 12 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण किए जाएं तथा जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बनी है, उनकी कारण सहित सूची तत्काल प्रस्तुत की जाए। समीक्षा के दौरान राजगढ़, खिलचीपुर और जीरापुर विकासखंडों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित बीआरसी अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के साथ तीन दिवस का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कक्षा पहली, छठी और नौवीं में अपेक्षा से कम प्रवेश वाले जनशिक्षा केंद्रों के सीएसी के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अपार आईडी निर्माण में कमजोर प्रगति वाले प्रत्येक विकासखंड के तीन-तीन जनशिक्षा केंद्रों के सीएसी को भी नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। जीरापुर विकासखंड में कम नामांकन और अपार आईडी निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर बीआरसीसी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में डॉ. गढ़पाले ने दो टूक कहा कि शिक्षा विभाग एवं पीएम पोषण योजना से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

राम मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का पलटवार, बोले– 'राम विरोध की राजनीति ने कांग्रेस का नुकसान किया'

बुरहानपुर दौरे पर सांसद ने राम मंदिर, आरएसएस और चंदा चोरी प्रकरण पर विपक्ष को घेरा, कहा– दोषियों पर कार्रवाई हुई, सनातन पर सवाल बर्दाश्त नहीं

आज की जनधारा

बुरहानपुर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और श्रीराम की प्रतिमा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हालिया बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम और सनातन पर सवाल उठाने की राजनीति का परिणाम देश देख चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने हमेशा प्रभु श्रीराम की आस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाने का प्रयास किया, जिसका राजनीतिक नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा।

दिग्विजय सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया- सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले भी भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताते रहे हैं और रामसेतु के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। सांसद ने कहा कि प्रभु श्रीराम के प्रति लोगों की आस्था अटूट है और उस पर सवाल उठाने वालों को जनता समय-समय पर जवाब देती रही है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का मन हमेशा हिंदू समाज और उसकी आस्था पर उंगली उठाने में लगा रहता है। यही कारण है कि उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई है। सांसद ने कहा कि भगवान श्रीराम उन्हें सद्बुद्धि दें। आरएसएस पर टिप्पणी करने वालों को दी चेतावनी- सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एक पवित्र और राष्ट्रहित में कार्य करने वाली संस्था है। उस पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग आरएसएस और सनातन पर लगातार आरोप लगाकर समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वे गलत कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि देश की जनता सब देख रही है।

चंदा चोरी मामले पर भी दिया जवाब- राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की भूमिका सामने आई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले को बहाना बनाकर सीधे सनातन धर्म और आरएसएस को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।

राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया माहौल- सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के इस बयान के बाद जिले सहित प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। राम मंदिर, आरएसएस और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।

उज्जैन मंगलनाथ मंदिर रोड में उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संभालने वाले दो नव-आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया पुरस्कृत

आज की जनधारा

पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसी क्रम मंगलनाथ क्षेत्र में यातायात ड्यूटी के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले दो नव-आरक्षकों को 500-500 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ड्यूटी के दौरान दोनों नव-आरक्षक अपने निर्धारित प्वाइंट पर सतत उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं एवं आमजन के आवागमन को सुचारु बनाए रखने में सक्रिय रहे। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, सतर्कता एवं अनुशासित कार्यशैली के फलस्वरूप यातायात व्यवस्था प्रभावी एवं व्यवस्थित बनी रही। पुरस्कृत नव-आरक्षक– 1.नव-आरक्षक 517 सविता डावर (जिला श्योपुर, वर्तमान ड्यूटीझमंगलनाथ यातायात व्यवस्था) 2.नव-आरक्षक 518 अनुराग (जिला श्योपुर, वर्तमान ड्यूटीझमंगलनाथ यातायात व्यवस्था) पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों नव-आरक्षकों के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार निष्ठापूर्वक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 08 जुलाई को

उज्जैन। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन 08 जुलाई 2026 को किया जाएगा। यह बैठक सांसद श्री अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक प्रातः 10:30 बजे से सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में जिला विकास एवं निगरानी से संबंधित विभिन्न विभागीय विषयों पर समीक्षा की जाएगी।

पुल-पुलियाओं पर बैरिकेटिंग एवं संकेतक लगाए जाए- कलेक्टर सिंह

आज की जनधारा

उज्जैन। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों, जनसुरक्षा व्यवस्थाओं समायावधि पत्रों, सी.एम हेल्प लाईन एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वर्षा काल के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखों को दिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य से संबंधित सभी विभाग प्रमुख वर्षा ऋतु में जनसुरक्षा सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए आवश्यक सभी सावधानियां समय रहते अपनाई जाएं। वर्षा काल में पुल-पुलियाओं पर बैरिकेडिंग लगाने तथा आवश्यक स्थानों पर पुल-पुलियाओ पर बरसात का पानी होने की स्थिति में पार नहीं करने संबंधि चेतावनी संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए। नगर निगम को निर्देशित किया गया कि रास्तों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी घटना-दुर्घटना की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। रपटों पर संकेतक लगाकर स्पष्ट रूप से चेतावनी देने के निर्देश दिए गए कि पानी होने की स्थिति में पुल-पुलियाओं को पार न किया जाए। अति वर्षा की स्थिति की में पुल पुलियाओं पर शासकीय सेवकों की ड्यूटी भी लगाई जाए जो कि आमजन को समझाईश दें। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही समितिवार उर्वरक वितरण की समीक्षा कर किसानों को आवश्यकता अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत चिन्हित जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाने तथा आवश्यक निदेर्शों का पालन सुनिश्चित करने विभाग प्रमुखों को कहा गया। संबल योजना में सभी पात्र हितग्राहियों के पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांस कुमट, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, वनमंडलाधिकरी अनुराग तिवारी, एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर शाश्वत शर्मा, समस्त एसडीएम एवं संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

आज की जनधारा

उज्जैन। जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय द्वारा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्जिन मेरी स्कूल, सेठीनगर उज्जैन में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी श्री महेंद्र खत्री एवं जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री संजय शर्मा द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सभी समन्वयकों को प्रेरित करते हुए साक्षरता कार्य को गति देने का आह्वान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा असाक्षरों के सर्वे कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु निर्देश दिए गए, वहीं जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ने ह्लघर-घर साक्षरताह्व के लक्ष्य की जानकारी देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। डीपीसी श्री राहुल भार्गव द्वारा उज्जैन जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में ह्लजन-जन साक्षर करेंगेह्व के नारे के साथ प्रशिक्षण गतिविधियों की शुरूआत की गई। प्रशिक्षण के दौरान असाक्षरों का चिन्हांकन, ऑनलाइन पंजीयन, डोर-टू-डोर सर्वे, अक्षर साथियों का पंजीयन, अक्षर पोथी का वाचन, सफलता की कहानी लेखन तथा एनआईएलपी ऐप के उपयोग सहित विभिन्न तकनीकी एवं शैक्षणिक बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। विभिन्न ब्लॉकों के प्रशिक्षित सह-समन्वयकों द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर उज्जैन शहर की अक्षर साथी नीतू गोयल का सम्मान जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री कमलेश शर्मा द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन श्री आशीष उपाध्याय द्वारा माना गया।

उज्जैन जिला माहेश्वरी समाज के चुनाव संपन्न, सतीश मूंदड़ा बने जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित

आज की जनधारा

तराना। उज्जैन जिला माहेश्वरी समाज के निर्वाचन रविवार को माहेश्वरी भवन, तराना में सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुए। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी पदों पर सर्वसम्मति बनने से पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के सफल आयोजन के साथ ही समाज में उत्साह एवं हर्ष का माहौल रहा। निर्वाचन में सतीश मूंदड़ा (तराना) को उज्जैन जिला माहेश्वरी समाज का जिला अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसी प्रकार रमेश हेड़ा (उज्जैन) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, घनश्याम राठी (नागदा) को सचिव तथा संजय बल्दवा (तराना) को कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 17 प्रादेशिक मंडल सदस्यों एवं राष्ट्रीय महासभा के लिए 3 सदस्यों का भी निर्विरोध निर्वाचन किया गया। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का उपस्थित समाजजनों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं तथा समाज के विकास और संगठन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का विश्वास व्यक्त किया। निर्वाचन कार्यक्रम में उज्जैन जिले के विभिन्न नगरों से बड़ी संख्या में समाजजन एवं अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में तराना माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष दिलीप डोडिया ने सभी आगंतुक अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने समाज की एकजुटता और सर्वसम्मति से हुए निर्वाचन को समाज की परिपक्वता एवं संगठनात्मक शक्ति का परिचायक बताया। निर्वाचन के उपरांत नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि वे समाज के हित, संगठन की मजबूती, युवा पीढ़ी की सहभागिता तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति देने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे।

खरगोन पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही

आज की जनधारा

खरगोन। थाना बलवाड़ा पर अवैध शराब का परिवहन करने पर 02 आरोपी के विरुद्ध किया धारा 34(1), 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 116 लीटर अवैध देशी-विदेशी शराब कीमती लगभग 58,560/- रुपये को किया जप्त प्रकरण में आरोपी के कब्जे से शराब के परिवहन में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार कीमती लगभग 5,00,000/- रुपये को भी जप्त दोनों आरोपियों के है आपराधिक रिकार्ड बलवाड़ा पर पुलिस टीम ने 02 आरोपी को गिरफ्तार कर 116 लीटर देशी-विदेशी शराब कीमती लगभग 58,560/- रुपये को जप्त कर कार्यवाही की गई है। थाना बलवाड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, इंदौर तरफ से एक ब्रेजा कार में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बलवाड़ा निरीक्षक श्री रितेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया व मुखबिर की सूचना से पुलिस टीम को अवगत करवा कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया व थाने के सामने वाहन चैकिंग लगाई गई एवं रोड से निकालने वाले वाहनों पर नजर रखी गई । थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को मुखबिर के बताए अनुसार एक ब्रेजा कार इंदौर तरफ से आती दिखाई दी जिसे टीम ने तत्काल घेराबंदी कर रोका ।

रोकी गई कार में बैठे चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जय उर्फ जयु निवासी गणगौर घाट बड़वाह तथा ड्रायवर के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछते उसने अपना नाम मोईन उर्फ राजा निवासी दशहरा मैदान बड़वाह का होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा कार को चेक करने पर उसमें देशी शराब व मेजिक मोमेंट शराब की पेटियाँ रखी मिली जिसे परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज व लाइसेंस के बारे में पूछने पर कोई वैध दस्तावेज व लाइसेंस नहीं होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा आरोपी जय उर्फ जयु एवं मोईन उर्फ राजा के विरुद्ध थाना बलवाड़ा पर अपराध क्रमांक 100/26 धारा 34(1), 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण में कुल 116 लीटर अवैध देशी-विदेशी शराब कीमती लगभग 58,560/- रुपये व अवैध देशी-विदेशी शराब के परिवहन में प्रयुक्त ब्रेजा कार कीमती लगभग 5,00,000/- रुपये की को नियमानुसार विधिवत जप्त विवेचना में लिया गया।

पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचार से 13 माह का बच्चा गंभीर कुपोषण से मुक्त हुआ

आज की जनधारा

उज्जैन। सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि जिला चिकित्सालय, चरक भवन में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में निःशुल्क उपचार एवं समुचित देखभाल के माध्यम से 13 माह का बच्चा इमादुल्ला गंभीर कुपोषण से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी रहा है। जानकारी के अनुसार शहर के शिकारी गली निवासी इमादुल्ला, पुत्र अरीफा, को दस्त एवं डिहाइड्रेशन की शिकायत के चलते जिला चिकित्सालय लाया गया था। चिकित्सकों द्वारा परीक्षण में पाया गया कि बच्चे का वजन मात्र 6 किलो 20 ग्राम है, अत्यंत कम है तथा वह गंभीर कुपोषण से ग्रसित है। चिकित्सकों ने परिजनों को समझाइश देकर उसे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने की सलाह दी, जिस पर माता-पिता सहमत हुए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि एनआरसी में बच्चे को भर्ती कर आवश्यक जांच एवं उपचार प्रारंभ किया गया। लगभग 14 दिनों तक विशेषज्ञ चिकित्सकों, पोषण प्रशिक्षकों एवं स्टाफ की निगरानी में बच्चे को उपचार एवं पौष्टिक आहार प्रदान किया गया। उपचार के परिणामस्वरूप बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तथा उसका वजन बढ़कर 6 किलो 920 ग्राम हो गया, जिसके बाद उसे स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। उपचार के दौरान चिकित्सक डॉ. पूजा गेहलोत एवं पोषण प्रशिक्षक श्रीमती सोनल ठाकुर सहित केंद्र के स्टाफ द्वारा निरंतर देखरेख की गई।

'सेफ क्लिक 2.0' बना जनभागीदारी का प्रदेशव्यापी अभियान, स्कूलों से रेलवे स्टेशनों और गांवों से सोशल मीडिया तक पहुंचा साइबर सुरक्षा का संदेश

आज की जनधारा

उज्जैन। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान₹सेफ क्लिक 2.0₹के अंतर्गत प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों द्वारा निरंतर विविध एवं नवाचारपूर्ण गतिविधियों का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, शासकीय कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों एवं सामुदायिक आयोजनों में व्यापक जनसंपर्क स्थापित कर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी पुलिस इकाइयां अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रतिदिन जागरूकता पोस्ट, रील, वीडियो संदेश एवं जनहित अपील प्रसारित कर अभियान को डिजिटल स्तर पर भी जन-जन तक पहुंचा रही हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में स्थानीय परिस्थितियों एवं जनसमूह के अनुरूप विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 6 हजार से अधिक नागरिकों की सहभागिता के साथ विशाल साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित कर ₹सेफ क्लिक, सुरक्षित जीवन₹ का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा पुलिस अधिकारियों ने एक साथ भाग लेकर साइबर सुरक्षा को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। भोपाल कमिश्नरेट के थाना रातीबड़ द्वारा आरडी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में आयोजित साइबर जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 1,500 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फर्जी निवेश, यूपीआई एवं क्यूआर कोड फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग सहित विभिन्न साइबर अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपाय बताए गए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई तथा किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस प्रशिक्षण शाला, उज्जैन द्वारा शासकीय विद्यालय ताजपुर में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन ठगी से बचाव तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के उपयोग की जानकारी दी गई। वहीं विदिशा में आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीण नागरिकों, युवाओं एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया तथा ₹रुको... सोचो... एक्शन लो₹ का आह्वान किया गया। खंडवा पुलिस द्वारा अभियान के अंतर्गत जिलेभर के विद्यालयों, जनपद कार्यालयों, पंचायतों, स्वास्थ्य संस्थानों, लोक सेवा केन्द्रों एवं अन्य शासकीय कार्यालयों में एक साथ व्यापक जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं। इसी प्रकार राजगढ़ एवं अनूपपुर में शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर हाइजीन एवं डिजिटल सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। टीकमगढ़ पुलिस ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा संदेश पहुंचाया, जबकि भोपाल ग्रामीण पुलिस ने गांवों एवं विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों एवं ग्रामीण नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अपराधों तथा हेल्पलाइन 1930 के संबंध में जानकारी दी। रेल यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जीआरपी भोपाल द्वारा रेलवे स्टेशन खंडवा पर ध्वनि प्रसारण प्रणाली के माध्यम से साइबर सुरक्षा संदेश प्रसारित किए गए। वहीं जीआरपी जबलपुर एवं जीआरपी इंदौर द्वारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को डिजिटल अरेस्ट, एपीके फाइल, फर्जी लिंक एवं अन्य साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। कटनी पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं नागरिकों के बीच पोस्टर एवं पम्पलेट वितरण कर साइबर जागरूकता अभियान संचालित किया गया। भोपाल जोन-3 पुलिस द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की साइबर ठगी एवं उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। सिंगरौली में विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के व्यावहारिक उपाय बताए गए।

चोरी : क्या यह हमारे सिस्टम का चरित्र बनती जा रही है?

■ संपादकीय

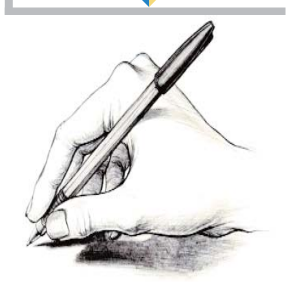

'चोरी' कभी अपराध मानी जाती थी, फिर वह आदत बनी, और अब ऐसा लगता है कि वह व्यवस्था का एक स्वीकृत व्यवहार बनती जा रही है। विडंबना यह है कि जिस दौर में देश डिजिटल क्रांति, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन निगरानी, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन सर्विलांस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, उसी दौर में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन की लूट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीक जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चोरी के तरीके भी उतनी ही तेजी से आधुनिक होते जा रहे हैं।

एक समय था जब भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की जाती थी। आज स्थिति कई बार ऐसी दिखाई देती है कि चोरी होती है और पकड़े जाने पर सीनाज़ोरी भी। 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' जैसे राजनीतिक संकल्पों और पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद यदि मंदिरों से लेकर मंत्रालयों तक, पंचायतों से लेकर परियोजनाओं तक और भर्ती परीक्षाओं से लेकर खनिज निधियों तक गड़बड़ियों की खबरें लगातार आती रहें, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर समस्या कहाँ है?

धार्मिक आस्था के केंद्र भी इससे अछूते नहीं रहे। देश के अनेक मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों में दान-पेटियों की राशि, चढ़ावे के आभूषणों और आय-व्यय के रिकॉर्ड को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आए हैं। कहीं सीसीटीवी कैमरों ने कर्मचारियों की करतूत उजागर की तो कहीं ऑडिट रिपोर्टों ने गड़बड़ियों की परतें खोलीं। यह स्थिति इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि यहां केवल धन की नहीं, जनता की आस्था की भी चोरी होती है।

शराब नीति से जुड़े विवादों ने भी देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है। विभिन्न राज्यों में आबकारी नीतियों, लाइसेंस वितरण और कथित कमीशनखोरी के आरोपों ने यह दिखाया कि नीति निर्माण और निजी हितों के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। कई मामलों में केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, अदालतों तक मामले पहुंचे, लेकिन इससे व्यवस्था की साख पर लगे प्रश्नचिन्ह समाप्त नहीं हुए।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) फंड का उद्देश्य उन गांवों तक विकास पहुंचाना था, जहां से देश की खनिज संपदा निकलती है। लेकिन, अनेक राज्यों में आरोप लगे कि अस्पताल, स्कूल, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च होने वाला पैसा कहीं और चला गया। जिन लोगों के नाम पर योजनाएं बनीं, वे आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं की स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। मनरेगा, आवास योजना, पंचायत निधि और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में फर्जी मस्टर रोल, कागजों पर बने तालाब, बिना निर्माण के भुगतान, मृत व्यक्तियों के नाम पर मजदूरी और एक ही काम के लिए कई बार भुगतान जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। यह केवल सरकारी धन की चोरी नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों की चोरी है।

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप दिखाई देता है। जब पुल उद्घाटन से पहले गिर जाएं, सड़कें कुछ महीनों में उखड़ जाएं और भवनों में दरारें पड़ जाएं, तब सवाल केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं रह जाता। यह सीधे नागरिकों की सुरक्षा और जीवन से जुड़ा मामला बन जाता है। बिहार सहित कई राज्यों में पुलों के गिरने की घटनाओं ने यह प्रश्न उठाया है कि आखिर भुगतान गुणवत्ता के लिए होता है या केवल कागजों के लिए?

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, फर्जी नियुक्तियां, छात्रवृत्ति घोटाले और कोविड काल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद से जुड़े विवाद बताते हैं कि जब व्यवस्था का नैतिक संतुलन बिगड़ता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर तकनीक होने के बावजूद चोरी रुक क्यों नहीं रही? ई-टेंडरिंग है, ऑनलाइन भुगतान है, आधार सत्यापन है, ड्रोन हैं, जीपीएस है, सीसीटीवी है, सोशल मीडिया है। फिर भी गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। इसका अर्थ साफ है कि समस्या केवल तकनीक की नहीं है। समस्या जवाबदेही की है, दंड प्रक्रिया की है, संस्थागत निगरानी की है और सबसे बढ़कर नैतिकता की है।

कानून का भय तब समाप्त हो जाता है जब दोषियों को यह विश्वास हो जाए कि जांच वर्षों चलेगी, मुकदमे दशकों तक लंबित रहेंगे और अंततः मामला किसी फाइल में दब जाएगा। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के अनेक मामले उजागर होने के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता।

फिर भी पूरे देश और पूरे सिस्टम को भ्रष्ट घोषित कर देना न्यायसंगत नहीं होगा। आज भी लाखों ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक संस्थाएं पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। व्यवस्था इन्हीं लोगों के कारण चल रही है। लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोगों की बेईमानी पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाती है।

असल सवाल यह नहीं है कि चोरी कहाँ-कहाँ हो रही है। सवाल यह है कि क्या हमने चोरी को एक सामान्य सामाजिक व्यवहार के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है? यदि सार्वजनिक धन की लूट, संसाधनों की बंदरबांट और अधिकारों की चोरी को हम केवल खबरों तक सीमित रखेंगे, तो यह धीरे-धीरे व्यवस्था का स्थायी चरित्र बन जाएगी। लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव नहीं, बल्कि जवाबदेही है। जब तक चोरी करने वालों को त्वरित और कठोर दंड नहीं मिलेगा, जब तक जांच निष्पक्ष और समयबद्ध नहीं होगी, और जब तक समाज ईमानदारी को सम्मान तथा भ्रष्टाचार को सामाजिक तिरस्कार नहीं देगा, तब तक तकनीक भी इस बीमारी का इलाज नहीं बन सकेगी।

कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते-लड़ते उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां चोरी अब अपवाद नहीं, बल्कि व्यवस्था का एक स्वीकार्य हिस्सा समझी जाने लगी है? यदि ऐसा है, तो यह किसी घोटाले से भी बड़ा राष्ट्रीय संकट है।

'भजनहा शैली' का परिष्कृत रूप है पंडवानी

-योग मिश्र

नारायण प्रसाद जी को लोग भजनहा (भजन गाने वाला) कहकर संबोधित करते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके समय तक पंडवानी शब्द प्रचलन में नहीं आ पाया था। पंडवानी शब्द बाद में प्रचलित हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद के पंडवानी गायकों को पंडवानी गायक के रूप में संबोधित किया जाता है, साथ ही इन्हें शाखाओं के साथ (वेदमति या कापालिक) जोड़कर चिन्हित किया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि पंडवानी गायन के साथ ही साथ इस विषय पर अब काफी काम हो चुका है, लेकिन जिस समय नारायण प्रसाद जी इस विधा को मंच पर प्रस्तुत करना आरंभ किये थे तब यह बाल्यावस्था में था। तब इसे भजन के रूप में देखा जाता था, और इसके गाने वाले को भजनहा अर्थात भजन गाने वाले के रूप में।

छत्तीसगढ़ी पंडवानी कथा गायन का जो रूप आज हम देखते हैं वह अपने मूल रूप से बहुत अलग है। देहाती आंगनों, चौपालों से निकलकर नगरीय मंचों तक पहुंचने की पंडवानी गायन की इस यात्रा का स्वरुप क्या है यह जानना भी रुचिकर है। यद्यपि नगण्य मात्रा में ही सही पर अपने मूल रूप में यह परम्परा कुछ गांवों में आज भी जारी है। सन 1945 के पहले के कालखंड में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उनका बहुत लेखा-जोखा आज हमें नहीं मिलता परन्तु इसके बाद के समय में क्या घटित हुआ उसके ब्यौरे उपलब्ध हैं। मुख्यधारा के हिन्दू समाज से बढ़ती निकटता और व्यवसायीकरण के प्रति बढ़ते झुकाव ने पंडवानी गायन की परम्परा को वर्तमान रूप तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निबाही। सन 1945 में पंडवानी के पितामह कहलाने वाले श्री झाड़ूराम देवांगन का उदय हो रहा था उनके उदय के साथ ही पंडवानी की प्रस्तुति और स्वरुप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

परधान बाना वाद्य बजाकर, देवार सारंगी बजाकर तथा भिम्मा तूमा बजाकर नृत्यगान करते हैं: यदि हम अतीत की ओर देखें तो पाते हैं कि समूचे

गोंडवाना क्षेत्र में गोंड जनजाति समृद्ध किसान और सामाजिक रूप से प्रभावशाली थी। इनके यहाँ कथागीतों के आयोजनों की परिपाटी भी थी। मान्यता है कि यह कथागीत आरम्भ में किसी गोंड द्वारा ही गए जाते थे, उन्ही कथागायकों के परिवार समूहों ने कालांतर में एक कथा वाचक जाति का रूप ले लिया। परधान, देवार और भिम्मा ऐसी ही जनजातियां हैं। परधान लोग बाना नामक वाद्य बजाकर, देवार लोग सारंगी बजाकर तथा भिम्मा लोग तूमा बाजा बजाकर नृत्यगान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में कथागायन की वाचिक परम्परा सदियों पुरानी: परधान कथावाचक सदियों से गोंडवानी, पंडवानी और रामायनी जैसे वाचिक आख्यानों का गायन करते रहे हैं। डॉक्टर सोनऊराम निर्मलकर जिन्होंने देवार समुदाय पर गहन शोध किया है के अनुसार देवार समुदाय के कथागायक भिक्षाटन के दौरान अनेक अन्य कथानकों के साथ महाभारत की छोटी-छोटी कथाएं (पंडवानी) भी गाते थे। प्रसिद्ध विद्वान् शेख गुलाब ने भिम्मा समुदाय पर लिखी अपनी पुस्तक में लिखा है कि भिम्मा समुदाय के कथागायक साल में एक बार अपने गोंड जजमानों के यहाँ वर्षा के देवता भीमसेन के कथागीत गाते हैं जिससे प्रसन्न होकर भीमसेन पानी बरसाते हैं।

नारायण लाल वर्मा प्रथम पंडवानी गायक हुए: पंडवानी के पितामह झाड़ूराम देवांगन के वरिष्ठ शिष्य चेतन देवांगन बताते हैं उन्होंने सुना है कि बहुत पहले शिवरीनारायण क्षेत्र के सतनामी समुदाय के लोग अपनी चौपालों में उनकी वाचिक परम्पराओं में प्रचलित घटोत्कच ब्याह, नकुल ब्याह एवं सहदेव ब्याह जैसे महाभारत कथा प्रसंग गाते थे। बाद में झाड़ूराम देवांगन से पहले अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ रावण-झीपन गांव के नारायण लाल वर्मा संभवतः पहले ज्ञात पंडवानी गायक हुए हैं। प्रतीत यह होता है कि पंडवानी के वर्तमान रूप का प्रचलन संभवतः नारायण लाल वर्मा द्वारा किया गया था।

भीमसेन ने अपना तूमा बाजा लमसेना को भेंट दिया था ऐसी किंवदंती है: पांडवों और विशेष तौर पर भीमसेन से गोंड आदिवासी विश्वासों का गहरा नाता है। गोंड उन्हें वर्षा लाने वाला देवता मानते हैं। श्री शेख गुलाब ने लिखा है, गोंड विश्वास के अनुसार किसी समय भीषण सूखा पड़ा। पानी नहीं बरसा, फसल नष्ट हो गयी।पशु-पक्षी सब भूखे मरने लगे। गोंड ठाकुर खेती के लिए पानी को तरसने लगे। पानी नहीं बरसेगा, खेती नहीं होगी तो लोग क्या खाएंगे।पानी के लिए सब सोच में पड़ गए, गुनिया और ओझाओं ने टोने-टोटके किये। देवताओं को प्रसाद चढ़ाया गया, बलि दी गई पर कुछ नहीं हुआ। गोंड ठाकुर जानते थे कि पानी बरसाने वाला भीमसेन हैं, उन्ही की कृपा से पानी बरसता है। वे बादलों में पानी भरकर लाते हैं तब जाकर पानी की वर्षा होती है। इस बार भीम सेन नाराज हो गए हैं, उनके प्रसन्न होने पर ही पानी बरसेगा। वे भीमसेन को खुश करने के उपाय सोचने लगे।

वर्षा के देव भीमा देव को मनाने समुदायगत आदिरूपों में गाई जाती थी पंडवानी: आज भी समूचे छत्तीसगढ़ के गावों में भीमा देव के देवस्थान होते हैं, लकड़ी का एक मोटा गोल-मटोल खम्बा अथवा प्रतिमा भीमा देव का प्रतिनिधित्व करती है। बस्तर क्षेत्र में भीमा वर्षा के देव के रूप में पूजे जाते हैं। प्रति वर्ष उनकी भीमा जात्रा भादों माह के शुक्रवार को गांव भर के लोग मिलकर मानते हैं। यदि वर्षा अच्छी तरह हो गयी तो नारियल, धूप बत्ती से सामान्य पूजा करते हैं परन्तु वर्षा न होने की दशा में भीमा जात्रा सारा गांव मिलकर बड़े स्तर पर आयोजित करता है । गोंड आदिवासी युवक-युवतियां इसमें बढ़-चढ़ कर नृत्य-गान करते हैं। भीमा देव का सिरहा बुलाया जाता है उस पर चढ़कर भीमा देव खेलता है। उसे मेंढा या भैंसा की बलि दी जाति है। वह प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा का आश्वासन देता है।

पंडवानी के नए अध्याय की जनक तीजनबाई: सन 1970 का दशक तक आते-आते पंडवानी गायन की स्थिति और भी बदल गयी थी। पारधी या बहेलिया जाति की तीजन बाई द्वारा पंडवानी गायन आरम्भ करने के साथ छत्तीसगढ़ी पंडवानी गायन की दुनियां में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ।

पंडवानी गाने पर तीजन की होती थी पिटाई : सन 1985 में श्री निरंजन महावर को दिए एक साक्षात्कार (चौमासा में प्रकाशित) में तीजनबाई ने कहा था, बचपन से मेरी आवाज़ अच्छी थी। मैं ऊँचे स्वर में ददरिया, करमा और सुवा गीत गया करती थी। एकबार पास के गांव की एक डोकरी (बूढी स्त्री) हमारे घर आई और उसने मुझे तम्बूरा दिखाकर कहा कि तू इस पर काम कर। मैंने तम्बूरा बजाना शुरू कर दिया। मेरे नाना ब्रिजलाल पंडवानी जानते थे, हमारे गांव में भी एक-दो बार पंडवानी गाने वाले आए थे, में उन्हें सुन-सुनकर पंडवानी याद करने लगी। जब कुछ याद हो गया तब एक बार तम्बूरा और खंजड़ी लेकर गांव वालों के सामने एक कार्यक्रम किया। पर मेरे पति को मेरा यह काम पसंद नहीं आया, उसने मंच पर ही मेरी पिटाई कर दी। मैं पढ़ी-लिखी नहीं थी, मुझे आधी-अधूरी कथा आती थी। तब मैंने उस समय के एक अनुभवी रागी उम्मेद सिंह से पंडवानी कथा सीखना आरंभ किया। उन्ही से मैंने विभिन्न पात्रों के अभिनय का अभ्यास किया। और अंततः पंडवानी गायन में अपना स्थान बनाया।

व्यंग्य

आलोचना

शरद जोशी

'लेखक विद्वान हो न हो, आलोचक सदैव विद्वान होता है। विद्वान प्रायः भौंडी बेतुकी बात कह बैठता है। ऐसी बातों से साहित्य में स्थापनाएँ होती हैं। उस स्थापना की सड़ांध से वातावरण बनता है जिसमें कविताएँ पनपती हैं। सो, कुछ भी कहो, आलोचक आदमी काम का है।' आज से आठ वर्ष पूर्व आलोचना पर अपने मित्रों के समूह में बोलते हुए यह विचार मैंने प्रकट किए थे। वे पत्थर की लकीर हैं। लेखक का साहित्य के विकास में महत्व है या नहीं है यह विवादास्पद विषय हो सकता है पर किसी साहित्यिक के विकास में किसी आलोचक का महत्व सर्वस्वीकृत है। साहित्य की वैतरणी तरना हो तो किसी आलोचक गैया की पूँछ पकड़ो, फिर सींग चलाने का काम उसका और यश बटोरने का काम कमलमुख का।

आलोचना के प्रति अपनी प्राइवेट राय जाहिर करने के पूर्व मैं आपको यह बताऊँ कि आलोचना है क्या? यह प्रश्न मुझसे अकसर पूछा जाता है। साहित्य रत्न की छात्राएँ चूँकि आलोचना समझने को सबसे ज्यादा उत्सुक दिखाई देती हैं इसलिए यह मानना गलत न होगा कि आलोचना साहित्य की सबसे टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर इसलिए कि मैं कभी इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाता। मैं मुस्कराकर उन लड़कियों को कनखियों से देखकर कह देता हूँ, 'यह किसी आलोचक से पूछिए, मैं तो कलाकार हूँ।'

खैर, विषय पर आ जाऊँ। आलोचना शब्द लुच् धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। लुच् धातु से ही बना है लुच्चा। आलोचक के स्थान पर आलुच्चा या सिर्फ लुच्चा शब्द हिंदी में खप सकता है। मैंने एक बार खपाने की कोशिश भी की थी, एक सुप्रसिद्ध आलोचक महोदय को सभा में परिचित कराते समय पिछली जनवरी में वातावरण बहुत बिगड़ा। मुझे इस शब्द के पक्ष में भयंकर संघर्ष करना पड़ा। आलोचक महोदय ने कहा कि आप शब्द वापस लीजिए। जनता ने भी मुझे चारों ओर से घेर लिया। मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि हिंदी भाषा में नया शब्द देना कितना खतरा मोल लेना है। मैंने कहा, मैं शब्द वापस लेता हूँ। पर आप यह भूलिए नहीं कि आलोचना शब्द 'लुच' धातु से बना है।

अस्तु, बात आई गई हो गई। मैंने इस विषय में सोचना और चर्चा करना बंद सा कर दिया। पर यह गुत्थी मन में हमेशा बनी रही कि आलोचक का दायित्व क्या है? वास्तव में साहित्य के विशाल गोदाम में घुसकर बेकार माल की छँटाई करना और अच्छे माल को शो-केस में रखवाना आलोचक का काम माना गया है, जिसे वह करता नहीं। वह इस चक्कर में रहता है कि अपने परिचितों और पंथ वालों का माल रहने दें, बाकी सबका फिंकवा दें। यह शुभ प्रवृत्ति है और आज नहीं तो कल इसके लाभ नजर आते हैं। कोशिश करते रहना समीक्षक का धर्म है। जैसे हिंदी में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि मैथिलीशरण गुप्त, निराला और कविवर कमलमुख में कौन सर्वश्रेष्ठ है। एक राष्ट्रकवि है। एक बहुप्रशंसित है और तीसरे से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

समीक्षकों के इस उत्तरदायित्वहीन मूड के बावजूद पिछला दशक हिंदी आलोचना का स्वर्णयुग था। जितनी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुईं उनसे अधिक आलोचकों को सादर भेंट प्राप्त हुई हैं। कुछ पुस्तकों का संपूर्ण संस्करण ही आलोचकों को सादर भेंट करने में समाप्त हो गया। समीक्षा की नई भाषा, नई शैली का विकास पिछले दशक में हुआ है। (दशक की ही चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आलोचक व्यक्तित्व का कँटीला विकास भी इसी दशक में हुआ है)। हिंदी का मैदान उस समय तक सूना था जब तक आलोचना की इस खंजर शब्दावली का जन्म नहीं हुआ था। इस शब्दावली के विशेषज्ञों का प्रकाशक की दुकान पर बड़ा स्वागत होते देखा है। प्रकाशक आलोचक पालते हैं और यदि इस क्षेत्र में मेरा जरा भी नाम हुआ तो विश्वास रखिए, किसी प्रकाशक से मेरा लाभ का सिलसिला जम जाएगा।

मैंने अपने आलोचक जीवन के शैशव काल में कतिपय प्रचलित शब्दावली, मुहावरावली और वाक्यावली का अनूठा संकलन किया था जिसे आज भी जब-तब उपयोग करता रहता हूँ। किसी पुस्तक के समर्थन तथा विरोध में किस प्रकार के वाक्य लिखे जाने चाहिए, उसके कतिपय थर्ड क्लास नमूने उदाहरणार्थ यहाँ दे रहा हूँ। अच्छे उदाहरण इस कारण नहीं दे रहा हूँ कि हमारे अनेक समीक्षक उसका उपयोग शुरू कर देंगे।

समर्थन की बातें

इस दृष्टि से रचना बेजोड़ है (दृष्टि कोई भी हो)। रचना में छुपा हुआ निष्कलुष वात्सल्य, निश्छल अभिव्यक्ति मन को छूती है। छपाई, सफाई विशेष आकर्षक है।

रूप और भावों के साथ जो विचारों के प्रतीक उभरते हैं, उससे कवि की शक्ति व संभावनाओं के प्रति आस्था बनती है।

कमलमुख की कलम चूम लेने को जी चाहता है। (दत्तू पानवाला की, यह मेरे विषय में व्यक्त राय देते हुए संकोच उत्पन्न हो रहा है परंतु उनके विशेष आग्रह को टाल भी तो नहीं सकता)।

मनोगुंफों की तहों में इतना गहरा घुसने वाला कलाकार हिंदी उपन्यास ने दूसरा पैदा नहीं किया।

कविता संसार

अरी बरखा तुम खूब बरसना

अशोक पटेल 'आशु'

बरखा आये घटा छाए,
प्रीत-प्रिया की याद सताए।
अरी बरखा तुम खूब बरसना
अंतरमन मेरा ये भीग जाए।

बर्षों से है मन मेरा प्यासा,
प्यास मेरी यह बुझ जाए।
रोम-रोम है मन मेरा आतुर
तुझसे मिलना हो जाये।

उमड़-घुमड़ के बरखा बरसे
बदरा बैरन बिजली चमके।
तुम बिन बरखा सुना लागे
धक-धक मेरा दिल ये धड़के।

अरी बरखा तुम भूल न जाना
नित-अहर्निश बारिश करना।
दर्द उठे जब इस दिल में मेरा
तन-मन को भीगा तुम जाना।

भूल न जाना दूर न जाना
ऐ बादल की तुम बरखा।
ऐसी बारिश हरदम करना
मुझसे प्रीत बनाये रखना।

मंदिर, राम सेतु और राजनीति: कैसे बदलते रहे नेताओं के सुर

-संजय सक्सेना

भारतीय राजनीति में भगवान राम का नाम दशकों से एक संवेदनशील और विवादित विषय रहा है। समय-समय पर अलग-अलग दलों और नेताओं के बयानों ने इस मुद्दे को गर्माया है, और हर बार यह बहस नए सिरे से शुरू हो जाती है कि कौन राम के प्रति कैसा नजरिया रखता है।2007 में केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सेतुसमुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इस हलफनामे में यह तर्क दिया गया था कि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माने जा सकते, और इसलिए राम सेतु के अस्तित्व को पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस हलफनामे पर देशभर में भारी विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा और तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। इस घटना को आज भी बीजेपी और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन कांग्रेस के खिलाफ एक प्रमुख राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम राम मंदिर आंदोलन के दौर से जुड़ा रहा है। 1990 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन आज भी उन्हें निशाना बनाते हैं। संसद और सार्वजनिक मंचों पर उनके कुछ बयानों को लेकर भी विवाद हुए, जिनमें अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक प्रमाणों पर सवाल उठाने की बात कही जाती रही है। हालांकि, सपा नेता इन आरोपों को अक्सर संदर्भ से काटकर पेश किए जाने की बात कहते रहे हैं। 'मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम' यह नारा 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा-बसपा गठबंधन के खिलाफ बीजेपी और उसके समर्थकों की ओर से गढ़ा गया था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि सपा-बसपा गठबंधन हिंदुत्व की राजनीति के विरोध में खड़ा है। यह नारा आज भी चुनावी भाषणों में सपा को घेरने के लिए इस्तेमाल होता है।आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद को 'हिंदू' बताते हुए मंदिरों में पूजा-अर्चना करते और जनेऊ पहनते नजर आते हैं। आलोचक इसे चुनावी रणनीति बताते हैं, जबकि सपा नेताओं का कहना है कि यह उनकी निजी आस्था है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती है कि उनकी पार्टी की राजनीति मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण पर आधारित है, और इस वजह से राम मंदिर जैसे मुद्दों पर उनका रुख हमेशा सतर्क और गोलमोल रहा है।

गगनयान के परीक्षणों में इसरो को मिली बड़ी सफलता

- महेन्द्र तिवारी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमता और दृढ़ संकल्प का लोहा मनवाया है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपने इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट और सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE) यानी सॉल्वे सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत अब अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की अत्यंत जटिल तकनीक में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग चार सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाना और तीन दिन के सफल मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस पूरे मिशन में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू अंतरिक्ष यात्रियों की पुख्ता सुरक्षा है और हाल ही में किए गए ये परीक्षण सीधे तौर पर इसी सुरक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

सॉल्वे सॉलिड मोटर का सफल परीक्षण क्रू एस्केप सिस्टम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। यह एक विशेष प्रकार

का रॉकेट है जिसे इसरो ने विशेष रूप से केवल गगनयान के क्रू मॉड्यूल के उड़ान परीक्षणों के लिए विकसित किया है। इस सॉलिड मोटर को पीएसएलवी रॉकेट के स्ट्रैप ऑन मोटर के आधार पर तैयार किया गया है लेकिन इसमें गगनयान मिशन की विशेष और सख्त आवश्यकताओं के अनुसार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें धीमी गति से जलने वाले प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया है ताकि यह आवश्यक समय तक लगातार और नियंत्रित ऊर्जा प्रदान कर सके। इसके साथ ही इसमें सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी अत्यधिक उन्नत तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक रॉकेट की दिशा को सटीक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है। इस मोटर का मुख्य काम उड़ान के दौरान किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को मुख्य रॉकेट से तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर खींच ले जाना है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया यह ग्राउंड टेस्ट यह साबित करता है कि मोटर का प्रदर्शन इसरो के कड़े मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है।

इसके साथ ही इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट भी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से अपना मिशन पूरा करके वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसकी गति अत्यधिक तीव्र होगी। इस भयंकर गति को कम करने और भारी क्रू मॉड्यूल को समुद्र की सतह पर बहुत ही सुरक्षित रूप से उतारने के लिए पैराशूट प्रणाली का बिना किसी चूक के काम करना आवश्यक है। इसरो ने इस रिकवरी प्रणाली में कुल दस पैराशूट्स का एक जटिल और अचूक नेटवर्क तैयार किया है। इस प्रणाली के तहत सबसे पहले एपेक्स कवर अलग होता है जिसके तुरंत बाद गति को कम करने के लिए दो ड्रोग पैराशूट खुलते हैं। जब मॉड्यूल की तेज गति कुछ हद तक नियंत्रित हो जाती है तो अंत में तीन विशाल मुख्य पैराशूट खुलते हैं जो क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के पानी में बेहद सुरक्षित और धीमी गति से लैंड कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्पलैशडाउन कहा जाता है। इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट की शानदार सफलता यह सुनिश्चित करती है कि पैराशूट खुलने की टाइमिंग और उनका तनाव सहने की क्षमता बिल्कुल सटीक है।

गगनयान मिशन भारत के लिए कई मायनों में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। इंसानों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजना केवल उपग्रह भेजने से बिल्कुल अलग और कहीं अधिक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए इसरो अपने सबसे भारी और भरोसेमंद रॉकेट एलवीएम थ्री का उपयोग कर रहा है जिसे मानव उड़ान के अनुकूल बनाने के लिए ह्यूमन रेटेड किया जा रहा है। ह्यूमन रेटिंग का सीधा अर्थ यह है कि रॉकेट का हर एक पुर्जा और हर एक प्रणाली शत प्रतिशत सुरक्षित और भरोसेमंद होनी चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मॉड्यूल के भीतर एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए इसरो एक विशेष पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार ऑक्सीजन प्रदान करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी को नियंत्रित रखेगी। यह उन्नत प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो भारतीय वैज्ञानिकों की असीमित बुद्धिमत्ता को दर्शाती है।

अंतरिक्ष से वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल को भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। जब यह मॉड्यूल वायुमंडल की घनी परतों से तेज गति से टकराता है तो घर्षण के कारण उसका बाहरी तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अत्यधिक और जानलेवा गर्मी से अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए क्रू मॉड्यूल के बाहरी हिस्से पर एक विशेष प्रकार का थर्मल हीट शील्ड लगाया गया है। यह शील्ड मॉड्यूल के भीतर के तापमान को बिल्कुल सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसरो ने इस हीट शील्ड का निर्माण भी स्वदेशी रूप से किया है और इसके कई सफल परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं।

खाट पर आम खाते हुए की चुनावी पंचायत

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर किया भोजन

लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने भाजपा व सहयोगी दलों के नेताओं के साथ यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर चर्चा की। वहीं, रविवार की दोपहर उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर भोजन किया और खाट (चारपाई) पर बैठकर पंचायत करते हुए आम के स्वाद के साथ 2027 चुनाव पर चर्चा की।

इस दौरान, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर भोजन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचे

विपक्षियों की चाल से बचने की सलाह दी

इसके पहले, शनिवार को लखनऊ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधियों को विपक्षी चाल से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष समाज को बांटने की साजिश रच रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्ष फिर जातियों का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की अपनी मूल विचारधारा भूलकर जातियों (ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, वैश्य) में बंट जाए।

नवीन ने कहा कि विपक्ष सोशल मीडिया और धारणा के जरिये सरकार की उपलब्धियों को दबाना चाहता है। केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिये उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। करोड़ों लाभार्थी सरकार के साथ सीधे जुड़े हैं। इसके बावजूद अगर हम मजबूत जनाधार को वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि जनता से हमारा संवाद कम है। विपक्ष इसका फायदा उठाने की ताक में है।

उन्होंने कहा कि सभी सांसद और विधायक दफ्तरों से निकलकर जनता के बीच जाएं। विकास कार्यों का स्वयं शिल्पकार बनकर श्रेय लें। संगठन की हर छोटी-बड़ी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अगले सात-आठ महीने की सामूहिक मेहनत से विपक्ष का सूपड़ा साफ होना तय है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए योगी सरकार ने दी 210 करोड़ रुपये की सब्सिडी

- 43 हजार से अधिक लोगों को मिला लाभ
- परिवहन विभाग की ईवी नीति का असर, प्रदेश में अब तक 96 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार के विजन के तहत परिवहन विभाग द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रय सब्सिडी योजना प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से हजारों उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। इसके तहत योगी सरकार ने 210 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी के रूप में वितरित किए।

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि खाड़ी देशों में गंभीर हालात और तेल संकट के बीच ईवी वाहनों की तरफ रुख करना ही बेहतर है। वहीं प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्रय सब्सिडी योजना इस दिशा में शानदार सहयोग दे रही है। इससे पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और बेहतर पर्यावरण से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रदेश सरकार ने इसी विजन के साथ 210 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी का भुगतान कर नया कीर्तिमान बनाया है।

43 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिली सब्सिडी

परिवहन विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 96,778 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से 43,218 लाभार्थियों को अंतिम रूप से ईवी क्रय सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना का लाभ बड़ी संख्या में आम नागरिकों तक पहुंचा है और लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं।

मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी मामले में CBI जाँच की माँग, याचिका खारिज

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी मामले में CBI जाँच की माँग वाली याचिका खारिज की याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने माँग की थी कि CBI जाँच का आदेश हो,सरकार की तरफ़ से AAG विनोद शाही और CSC शैलेंद्र सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अतः यहाँ कोई औचित्य नहीं है सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी।

KGMU यूरोलॉजी विभाग में दवा घोटाले जांच तेज

लखनऊ। जांच में नए खुलासे सामने आए, बंद अलमारियों से मरीजों के नाम की दवाएं बरामद, 115 मरीजों के नाम पर जारी दवाएं मिलीं, बरामद दवाओं की कीमत 3 लाख रुपये से ज्यादा, जांच समिति को 2-3 और अलमारियां खोलनी हैं, अलमारियों में अहम दस्तावेज होने की आशंका, मरीजों की और दवाएं मिलने की भी संभावना, विभाग से अलमारियों की चाबियां मांगी गईं, बरामद दवाओं का रिकॉर्ड से मिलान जारी, जांच पूरी होने पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी

नेहरू सरकार की तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ डॉ. मुखर्जी ने किया था शंखनाद: मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर निवेदित की श्रद्धा, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत माता का महान सपूत, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद् बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद-370 के खिलाफ नेहरू सरकार की तुष्टिकरण की वह नीति, जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रही थी, डॉ. मुखर्जी ने उसके खिलाफ शंखनाद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद-370 समाप्त कर डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार किया और कश्मीर में भी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित की। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन भी किया।

पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो उसमें डॉ. मुखर्जी की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी के आंदोलन में प्रमुखता से जुड़े। बंगाल को जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की चालें चली जा रही थीं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके खिलाफ खड़े हुए। पश्चिम बंगाल यदि भारत का हिस्सा है तो इसमें जिन महान नेताओं ने खुद को समर्पित कर आंदोलन का हिस्सा बनाया और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, उसमें डॉ. मुखर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के मंत्री के रूप में खाद्य नीति व उद्योग नीति को प्रमुखता से लागू किया।

1.37 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को झटका

गाजियाबाद। बिना पूर्व सूचना बढ़ाया गया स्वीकृत बिजली लोड, कई घरेलू कनेक्शनों का लोड 2 KW से बढ़ाकर 3 K W, जिले में 1,48,554 K W अतिरिक्त लोड जोड़ा गया, उपभोक्ताओं को SMS भेजकर दी गई जानकारी, अधिक बिजली खपत के आधार पर लोड संशोधित, बढ़े हुए लोड पर अब देना होगा ज्यादा फिक्स्ड चार्ज, प्रदेश में 46.79 लाख उपभोक्ताओं का लोड बदला गया, गाजियाबाद के 1,37,522 उपभोक्ता कार्रवाई से प्रभावित।

इंस्टाग्राम पर प्यार, फिर सड़क पर तकरार

सीतापुर। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, फिर सड़क पर तकरार, प्रेमिका ने प्रेमी का कॉलर पकड़ लगाई फटकार, प्रेमी युगल के बवाल का वीडियो हुआ वायरल होगया ,जहां मुंबई की सगुप्ता को रेउसा के तालिब से था प्यार, लखनऊ में लंबे समय तक साथ रहे थे दोनों बहाने से प्रेमिका को छोड़ भागा था प्रेमी तालिब तालिब की शादी का पता चलने पर प्रेमिका भड़क गई रेउसा पहुंच धोखेबाज़ प्रेमी को सबक सिखाते हुवे पुलिस के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला, रेउसा थाना के कस्बा क्षेत्र का है मामला

श्री गुरु हरगोबिंद साहिब का प्रकाश पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया

लखनऊ। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आलमबाग में आज छठे पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज का पावन प्रकाश पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय इस्त्री सत्संग सभा एवं दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया गया।

समागम के दौरान भाई जस्करण सिंह जी ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन, उपदेशों तथा सिख पंथ के लिए उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए संगत को बताया कि गुरु साहिब ने आध्यात्मिक शक्ति के साथ-साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश दिया। उन्होंने 'मीरी-पीरी' की परंपरा स्थापित कर धर्म और समाज की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया।

इस अवसर पर गुरु साहिब का पावन उपदेश 'भै काहू कउ देत नहि, नहि भै मानत आन॥' का भी स्मरण किया गया, जिसका अर्थ है कि सच्चा सिख न किसी को भय देता है और न ही किसी से भय स्वीकार करता है।

दीवान की समाप्ति पर संगत को मिस्सी पराठे एवं मट्ठे का प्रसाद वितरित किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निर्मल सिंह, रतपाल सिंह, हरजीत सिंह सरला, त्रिलोक सिंह, परमजीत सिंह, इकबाल सिंह, इंदर मोहन चावला, हरविंदर सिंह, मनमोहन सिंह सहित अन्य समिति सदस्य एवं बड़ी संख्या में संगत उपस्थित रही।

यूपी में विकास के लिए अखिलेश यादव को सीएम बनाएगी जनता: अरशद खान

- नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव मौलाना अनवार अहमद कासमी नें जौनपुर का मान बढ़ाया : मौलाना इकबाल कादरी

लखनऊ। सिपाह, जौनपुर स्थित मदरसा मोमिनात लिल बनात सिपाह में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव मौलाना अनवार अहमद कासमी के सम्मान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।

अपने संबोधन में मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश को विकसित उद्योग, विकसित कृषि, बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ाना है तो वर्ष 2027 में प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनानी होगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास का एक स्वर्णिम दौर देखा। उस अवधि में एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, आधारभूत संरचना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए, जिनकी आज भी व्यापक चर्चा होती है।

विक्रम राव पुनर्गठित समिति के नये अध्यक्ष व रूपेंद्र उपाध्याय को कोषाध्यक्ष का पद मिला

लखनऊ। आज सुबह विधान सभा प्रेस रूम में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) की पहली आम सभा की बैठक संयोजक प्रभात त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। महासचिव ज्ञानेश पाठक की मौजूदगी में सभी 17 निर्वाचित पदाधिकारियो ने भाग लिया। बैठक मे गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई कि पहले ऐतिहासिक निर्वाचन के बाद कुछ स्वार्थी तत्वो के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितयो पर जल्द महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुनर्गठित समिति के बर्खास्त अध्यक्ष और तीन कार्यकारिणी सदस्य और एक संयुक्त सचिव को अनुशासन हीनता के कारण (पुनर्गठित) समिति से हटा दिया था उसकी जगह नये अध्यक्ष के लिए पर्ची डालकर चयन कर लिया जाये। आज सभी 17 पदाधिकारियो ने आपसी सहमति से पर्ची डालकर पुनर्गठित समिति का नया अध्यक्ष चुना गया जिसमें सर्वाधिक 11 मत पाकर विक्रम राव पुनर्गठित समिति के नये अध्यक्ष बन गये है। विक्रम राव को 17 मतो में से सर्वाधिक 11 मत प्राप्त हुये। दूसरे स्थान पर

उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सिंह उपाध्यक्ष रहे जिन्हे मात्र 5 वोट मिले। तीसरे नम्बर पर कृष्ण कुमार सिंह (के के सिंह) उपाध्यक्ष रहे जिन्हे 1(एक) मात्र बोट मिला। विक्रम राव के अध्यक्ष चुनने के बाद उनके रिक्त स्थान कोषाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मत से रूपेंद्र उपाध्याय को पुनर्गठित समिति का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। समिति के प्रवक्ता पद पर भी सभी की सहमति से लक्ष्मीकांत तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने नये अध्यक्ष को बधाई देते हुए आशा ब्यक्ति की है कि वह समिति को सर्वोपरि रखते हुये पूरी टीम को एकजुट रखेगें और पूरी मेहनत से पत्रकारो की सेवा में काय? करेगें। महासचिव ज्ञानेश पाठक ने भी विक्रम राव को बधाई देते हुए कहा है कि अब समिति पूरी ताकत से पत्रकार के हितो के लिए काय? करेगी। आज की आम सभा की बैठक में उपाध्यक्ष अमन अग्रवाल . के के सिंह. जितेन्द्र कुमार सिंह संयुक्त सचिव राजू यादव.अर्चना गुप्ता. दीपक अवस्थी काय?कारिणी सदस्य सुरेंद्र कुमार दुवे.बलराम गुप्ता. शीतला प्रसाद. धंनजय सिंह. लक्ष्मीकांत तिवारी.सुभाष मिश्र. शियाराम यादव और विवेक शुक्ला मौजूद थे। आम सभा की बैठक के बाद नये अध्यक्ष विक्रम राव ने विधान सभा प्रेस रूम में संरक्षक और वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पंकज का पूरी टीम के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। बैठक के बाद विधान सभा परिसर का निरीक्षण कर रहे उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात कर समिति ने आशीर्वाद प्राप्त कर फोटो सूट कराया। अध्यक्ष सतीश महाना से संयोंजक प्रभात त्रिपाठी ने आग्रह किया है कि वह पूरी समिति को अपने यहां बुलाकर आशिर्वाद प्रदान करे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह जल्द पुनर्गठित समिति को मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे।

जब जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह भूलीं तारीख, तब हंसी का पात्र बना फरमान

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह की ओर से जारी एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। आदेश पर 31 जून की तारीख अंकित है, जबकि जून महीने में केवल 30 दिन होते हैं।

जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आदेश में दर्ज गलत तारीख को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होने वाला है। ऐसे में कार्यकाल के अंतिम चरण में जारी इस आदेश और उसमें दर्ज तारीख की त्रुटि को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

योगी बैठक में उच्च शिक्षा को बढ़ावा, तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी

- योगी सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा का हो रहा है विस्तार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें निजी क्षेत्र में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रसार और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी।

लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत मूल्यांकन के बाद तीन संस्थाओं को आशय पत्र (एलओपी) जारी करने और संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंचे, यह मुख्यमंत्री योगी जी का लक्ष्य है और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है।

प्रायोजक संस्था 'स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली' द्वारा कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर के ग्राम गदनपुर आहार में 51.739 एकड़ भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह कृषि आधारित विश्वविद्यालय होगा, जो प्रदेश में कृषि शिक्षा व अनुसंधान को नई दिशा देगा। इसके लिए उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया जाएगा।

प्रायोजक संस्था 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी, गाजियाबाद' द्वारा संचालित यह विश्वविद्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम डासना में 26.2656 एकड़ भूमि पर बनेगा। संस्था पहले से मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रही है। अब गाजियाबाद शहर में यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के नए अवसर देगा। इसके लिए उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित होगा।

प्रायोजक संस्था 'एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर' द्वारा फतेहपुर तहसील के कस्बा फतेहपुर दक्षिणी में 20.45 एकड़ भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। शहरी क्षेत्र के मानक के अनुरूप 20 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है। इसके लिए उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया जाएगा।

योगी कैबिनेट में सरकार की ओर से जनहित व विकास से जुड़े 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की? बैठक के बाद, सरकार की ओर से जनहित और विकास से जुड़े 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने की विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई।

सोमवार को कैबिनेट बैठक में प्रमुख और विशेष निर्णय लिए गएं, जिसमें जलालाबाद का नाम परिवर्तन किया गया है जिसमें शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई?

होमगार्डों के लिए कैशलेस इलाज

होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने का बड़ा फैसला लिया गया?

मेडिकल कॉलेजों का निर्माण

गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव पास हुआ है?

मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी

मदरसा शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के प्रस्ताव को नामंजूर (स्थगित) कर दिया गया है।

डॉ. मुखर्जी के आदर्श और बलिदान कार्यकताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है,डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन

आज की जनधारा

शहडोल। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा की जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा ने की। धनपुरी नगर के इंदौर स्टेडियम के सामने स्थित परिसर में आयोजित इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव रहे। जबकि विशिष्ट अतिथियों में भाजपा शहडोल संभाग प्रभारी गौरव सिरोठिया, विधायक जयसिंह मरावी, विधायक शरद कोल, पूर्व विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह, नगर परिषद बुढ़ार की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, मौसमी केवट, राजन गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रविंदर

कौर छाबड़ा, जिला उपाध्यक्ष संतोष लोहानी, गिरधर प्रताप सिंह, महामंत्री अमित मिश्रा व कविता सिंह मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि कैलाश जाटव ने कार्यकताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान का विरोध करते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने जिस अखंड भारत और सशक्त राष्ट्र का सपना देखा था,

वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। उन्होंने कार्यकताओं से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होने पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वर्ष के 365 दिन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से संगठन के लिए कार्य करता है। यही कारण है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर सर्वोच्च दायित्व तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में प्रत्येक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार जनहित में लगातार कार्य कर रही है। यदि किसी कार्य में समय लगता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए सभी कार्यकताओं को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना होगा।

कटनी हरदुआ आउटर पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, GRP ने शुरू की जांच

आज की जनधारा

कटनी। कटनी रेलवे स्टेशन के हरदुआ आउटर क्षेत्र में सोमवार तड़के एक अज्ञात युवक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी सुबह करीब 4:30 बजे स्टेशन मास्टर को मिली, जिसके बाद तत्काल रेलवे सुरक्षा बल (R P F) और शासकीय रेलवे पुलिस (G R P) को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही G R P और R P F की टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋफढ पुलिस ने अज्ञात मृतक का मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को मृतक के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह तत्काल G R P कटनी से संपर्क करे, ताकि उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी जा सके।

भाजपा पचोर मंडल की मासिक बैठक कल, अस्पताल में एटीएम मशीन का होगा शुभारंभ मंत्री, सांसद व जिलाध्यक्ष रहेंगे मौजूद

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। भारतीय जनता पार्टी मंडल पचोर द्वारा मंगलवार, 7 जुलाई को संगठनात्मक गतिविधियों के तहत मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक दोपहर 12 बजे स्वर्णकार धर्मशाला, पचोर में आयोजित होगी, जिसमें मंडल के सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकताओं, पदाधिकारियों तथा सक्रिय कार्यकताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान, सदस्यता विस्तार तथा विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक से पूर्व सुबह 11:30 बजे पचोर अस्पताल परिसर में नई एटीएम मशीन का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने से अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों तथा क्षेत्रवासियों को नकदी निकासी के लिए राहत मिलेगी और उन्हें अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री गौतम टेटवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानसिंह गुर्जर, सांसद रोडमल नागर तथा भाजपा मंडल प्रभारी जगदीश नागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सभी अतिथि कार्यकताओं को संबोधित करते हुए संगठन की भावी रणनीति, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा पार्टी की आगामी गतिविधियों को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित ने मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकताओं, पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से समय पर कार्यक्रम में उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाने का आग्रह किया है।

टीएल बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने दिए सख्त निर्देश

मूंग उपार्जन, जनकल्याण शिविर, सीएम हेल्पलाइन, स्वच्छता और जल संरक्षण कार्यों की विस्तार से हुई समीक्षा

आज की जनधारा

नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेंद्र नागेश सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जिले में मूंग उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केंद्रों पर सर्वेयर की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर यह विशेष ध्यान रखा जाए कि खरीदी की जाने वाली मूंग गीली न हो तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाए। विभिन्न योजनाओं के पात्र

हितग्राहियों की ई-केवायसी, समग्र ई-केवायसी एवं योजनाओं के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आयोजित किए जा रहे विशेष शिविरों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संबंधित विभागों का अमला शिविर स्थल पर समय पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शिविरों के आयोजन की जानकारी पूर्व से ही आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही शिविरों का लाभ ले सकें और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए। साथ ही सीएम मॉनिट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण कर तथ्यात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन लगने वाले हाट-बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख मार्गों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में नगरीय निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों, शासकीय भवनों एवं आम नागरिकों की सहभागिता से बड़ी संख्या में सोक पिट और अन्य लघु जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन छोटी-छोटी जल संरचनाओं से भू-जल रिचार्ज में व्यापक सुधार दिखाई देगा तथा भविष्य में जल संरक्षण को स्थायी मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन कार्यों का प्रभावी दस्तावेजीकरण किया जाए। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तथा संबंधित विभाग जल संरक्षण से जुड़े कार्यों का विस्तृत डेटा तैयार करें, ताकि जिले में हुए कार्यों एवं उनके सकारात्मक परिणामों का समुचित आकलन किया जा सके।

राहुल वासनिक ने संभाला सहायक संचालक नरसिंहपुर का पदभार

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारी श्री राहुल वासनिक ने सोमवार को सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय नरसिंहपुर के पद पर पदभार ग्रहण किया श्री वासनिक इससे पूर्व जिला जनसंपर्क कार्यालय मंडला में पदस्थ थे। विदित है कि श्री वासनिक नरसिंहपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्री वासनिक ने कहा कि जनसंपर्क विभाग शासन और आमजन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है। विभाग की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए शासन की जनहितैषी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों का समयबद्ध, तथ्यपरक और प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर जनसंपर्क गतिविधियों को और अधिक सशक्त एवं परिणाममुखी बनाया जाएगा।

स्कूल बाउंड्री वॉल गिरने पर संबंधित प्रधानाध्यापक एवं सब इंजीनियर को नोटिस जारी

- शहर में झूलते बिजली के तारों को व्यवस्थित करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

आज की जनधारा

कटनी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने बहोरीबंद विकासखंड के ग्राम केवलारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की बाउंड्री वॉल गिरने की घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने प्रधानाध्यापक कमल सिंह ठाकुर और उपयंत्री एस पी सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बारिश के मौसम को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में यत्र-तत्र

झूल रहे बिजली के तारों को तत्काल व्यवस्थित करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए। साथ ही समय-सीमा पत्रों, समग्र ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में बरते गंभीरता-कलेक्टर श्री तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए नगर निगम, एमएसएमई, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, राजस्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि सहित विभिन्न विभागों को इनके निराकरण में गंभीरता और संवेदनशीलता बरतने की हिदायत देते हुये कलेक्टर ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना से जुड़ी शिकायतों के विश्लेषण और समाधान के लिए राजस्व अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए।

सात महीने पहले ही बगीचों में पहुंचने लगे व्यापारी, विश्वास के आधार पर हो रहे अग्रिम सौदे

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। सारंगपुर-पचोर अंचल में इस वर्ष संतरे की बेहतर पैदावार की संभावना के चलते व्यापारिक गतिविधियां समय से पहले ही रफ्तार पकड़ने लगी हैं। फसल के बाजार में आने में अभी करीब सात माह का समय शेष है, लेकिन बगीचों में आए भरपूर फूलों ने किसानों और व्यापारियों दोनों की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। यही वजह है कि व्यापारी अभी से बगीचों का निरीक्षण कर अग्रिम सौदे करने में जुट गए हैं। क्षेत्र में इन दिनों पेड़ों पर आए फूलों और संभावित उत्पादन का आकलन कर किसानों के साथ आपसी विश्वास के आधार पर सौदे तय किए जा रहे हैं। व्यापारी फसल की गुणवत्ता और संभावित पैदावार को देखते हुए पहले से ही खरीद सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। संतरा व्यापारी रोशन खत्री ने बताया कि वर्तमान में संतरे के अग्रिम सौदे 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा और उत्पादन बेहतर हुआ तो इस बार किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ मिलने की संभावना है। संतरे की खेती इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी मानी जाती है। इससे जुड़े व्यापार के माध्यम से सैकड़ों व्यापारी कारोबार करते हैं, जबकि हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। यहां का मीठा और गुणवत्तायुक्त संतरा प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। पड़ाना निवासी किसान पप्पू खाती ने बताया कि उनके एक

हेक्टेयर के संतरे के बगीचे का पूर्व में लगभग दो लाख रुपये में सौदा हुआ था। इस वर्ष पेड़ों पर भरपूर फूल आए हैं, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। उनका मानना है कि उत्पादन बेहतर रहने पर इस बार संतरे के भाव भी पिछले सीजन की तुलना में अधिक मिल सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए व्यापारियों ने अभी से बगीचों में पहुंचकर अग्रिम सौदेबाजी शुरू कर दी है।

कटनी नदी पुल से नीचे गिरकर मसुरहा वार्ड निवासी बुजुर्ग की मौत, चांडक चौक से नीचे हुई घटना

आज की जनधारा

कटनी। कटनी नदी पुल से गिरने की वजह से मसुरहा वार्ड निवासी 71 वर्षीय नारायन दास गुप्ता की मौत हो गई। यह घटना कैसे हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र शहर के चांडक चौक में उस समय हड़कंप मच गया, जब लगभग 71 वर्षीय व्यक्ति 6 जुलाई की दोपहर कटनी नदी पुल से नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। 108 एंबुलेंस चालक के अनुसार उन्हें कॉल सेंटर से सूचना प्राप्त हुई थी, कि चांडक चौक ब्रिज के पास एक लगभग 71 वर्षीय पुरुष गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल लेकर आई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने परीक्षण के बाद व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मृतक की शिनाख्त नारायण दास गुप्ता पिता सुंदरलाल गुप्ता 71 वर्ष मसुरहा वार्ड निवासी के रूप में की गई है।

जर्जर प्राथमिक स्कूल बने हादसे का सबब, भय के साये में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल

- मेहरागाँव के बाजार मोहल्ला व ढोंगा मोहल्ला प्राथमिक शालाओं की बदहाल स्थिति, अभिभावकों ने जताई चिंता

आज की जनधारा

नरसिंहपुर। ग्राम पंचायत मेहरागाँव के अंतर्गत संचालित प्राथमिक शाला बाजार मोहल्ला एवं प्राथमिक शाला ढोंगा मोहल्ला की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। दोनों विद्यालयों के भवन अत्यधिक जर्जर हो चुके हैं, जिससे यहां

अध्ययनरत बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवनों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं तथा उनका झुकाव सड़क की ओर हो गया है। बरसात के दिनों में छत से लगातार पानी टपकता रहता है, जिससे कक्षाओं में पढ़ाई बाधित होती है और किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालयों में पर्याप्त कक्ष नहीं होने के कारण पहली से छठवीं तक की कक्षाएं एक ही कमरे के अलग-अलग कोनों में संचालित की जा रही हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय परिसर में खेल मैदान का अभाव है और शौचालयों की साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं है। विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण रात के समय असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे विद्यालय का वातावरण दूषित होने के साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। शिक्षकों द्वारा भी कई बार संबंधित अधिकारियों को भवनों की जर्जर स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि दोनों विद्यालयों के जर्जर भवनों का तत्काल निरीक्षण कर नए भवनों का निर्माण कराया जाए तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

चीतल को केला खिलाना पड़ गया भारी

आज की जनधारा

शहडोल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वन्य प्राणी ची तल को केला खिलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। वन विभाग ने इस व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए इसे कोर्ट में पेश किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा था कि एक व्यक्ति अपने कार से उतर कर समीप में खड़े शीतल को केला खिला रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उक्त वीडियो पचपेढी पर्यटन जोन से सफारी कर लौट रहे एक पर्यटक द्वारा बनाया गया था। 27 जून को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी गेट के सामने एक व्यक्ति के द्वारा चीतल को केला खिलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के संज्ञान में आया था। बांधवगढ़ प्रबंधन ने उक्त वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जांच प्रारम्भ की जिसके फलस्वरूप उक्त व्यक्ति को 06 जून को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संबंधित धाराओं को अधिरोपित करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि वन्य जीवों को कोई भी अखाद्य/खाद्य पदार्थ खिलाना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह

ऐसे किसी भी कृत्य को कदापि न करें। अनूप मिश्रा पिता रमाकांत मिश्रा ग्राम बेलिया बड़ी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर

सीवरेज कार्य की फिर खुली पोल! एस्सार टाउनशिप मार्ग पर धंसी सड़क, मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती?

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से चल रहे सीवरेज परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। गनियारीझएस्सार टाउनशिप मार्ग पर सड़क धंसने की घटना ने न केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, बल्कि सड़क बहाली के नाम पर किए जा रहे कार्यों की भी पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत और खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग ने समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय केवल मिट्टी और गिट्टी डालकर गड्ढा भर दिया, जिससे यह पूरा मामला सिर्फ खानापूर्ति और लीपापोती तक सीमित नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले गनियारीझएस्सार टाउनशिप मार्ग पर अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिससे बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। यह मार्ग क्षेत्र के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल है, जहां से प्रतिदिन भारी वाहनों के साथ बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। सड़क

धंसने के कारण दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई थी। स्थानीय लोगों ने समय रहते इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी और तत्काल स्थायी मरम्मत की मांग की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क धंसने की घटना के बाद नगर निगम और संबंधित एजेंसी सक्रिय तो हुई, लेकिन जिस प्रकार से मरम्मत का कार्य किया गया, उसने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया। आरोप है कि गड्ढे की वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से मरम्मत करने के बजाय उसमें केवल मिट्टी और गिट्टी डालकर उसे समतल कर दिया गया। लोगों का कहना है कि यह समाधान केवल कुछ दिनों का हो सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में मिट्टी बैठने के बाद सड़क दोबारा धंसने की पूरी संभावना बनी रहेगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क बहाली का कार्य निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप किया गया होता, तो पहली ही बारिश में सड़क धंसने जैसी स्थिति पैदा नहीं होती। उनका आरोप है कि कई स्थानों पर सीवरेज कार्य पूरा होने के बाद सड़क को पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं बनाया गया, जिसके कारण लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि करोड़ों रुपये की परियोजना में गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। यदि निर्माण कार्य के दौरान मानकों का पालन किया गया होता तो सड़क धंसने जैसी घटना नहीं होती। अब जब सड़क धंस चुकी है, तब भी यदि केवल अस्थायी मरम्मत कर मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है, तो भविष्य में इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। बारिश के मौसम में सड़क की मजबूती और टिकाऊपन सबसे बड़ी चुनौती होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि धंसी हुई सड़क की मरम्मत तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं की जाती, तो लगातार पानी भरने और भारी वाहनों के दबाव से सड़क फिर से धंस सकती है। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मौके की तस्वीरें भी मरम्मत कार्य की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरों में गड्ढे को केवल मिट्टी और गिट्टी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यह स्थायी समाधान कम और औपचारिक कार्रवाई अधिक प्रतीत होती है। नागरिकों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल शिकायतों का तत्काल जवाब देने के लिए दिखावटी मरम्मत करा रहे हैं, जबकि मूल समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त से पूरे सीवरेज कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल इस एक स्थान की नहीं, बल्कि जहां-जहां सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क बहाली की गई है, उन सभी स्थानों की गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए। यदि किसी स्तर पर निर्माण में लापरवाही, घटिया सामग्री का उपयोग या तकनीकी मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि सरकारी धन जनता की गाढ़ी कमाई से आता है, इसलिए विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनिज परिवहन करते तीन वाहन जब्त

आज की जनधारा

सिंगरौली। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त तीन वाहनों को जब्त किया। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिना वैध अभिवहन पास के गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर एक बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से बरगवां थाना परिसर में खड़ा कराया गया। इसी प्रकार, यूपी-64 बीटी-5171 क्रमांक का वाहन रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसे चितरंगी थाना में सुरक्षित खड़ा कराया गया। वहीं एमपी-66 जेडबी-4475 क्रमांक की ट्रैक्टर-ट्रॉली गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर उसे कोतवाली बैढ़न थाना परिसर में जब्त कर रखा गया। खनिज विभाग ने बताया कि जब्त किए गए सभी वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा की नई अलख: सर्वहित जनकल्याण सेवा समिति ने खोला नि:शुल्क शिक्षा केन्द्र-02

60 से अधिक बच्चों ने कराया पंजीयन, जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ बैग, ड्रेस, कॉपी, पेन एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री भी मिलेगी

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के ग्रामीण अंचल के गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सर्वहित जनकल्याण सेवा समिति, बड़ोखर ने एक और सराहनीय पहल करते हुए रविवार को बड़ोखर तिराहा स्थित रामप्रताप पाल के निवास पर निःशुल्क शिक्षा केन्द्र क्रमांक-02 का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में 60 से अधिक बच्चों ने पंजीयन कराया। बड़ी संख्या में अभिभावकों, ग्रामीणों एवं समाजसेवियों की उपस्थिति ने इस जनहितकारी अभियान को और उत्साहपूर्ण बना दिया। समिति द्वारा इससे पहले 1 जुलाई को अमराई टोला में निःशुल्क शिक्षा केन्द्र क्रमांक-01 की शुरूआत की गई थी। अब दूसरे केन्द्र के शुभारंभ के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का अभियान और तेज हो गया है। मुख्य

अतिथि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक प्रभु दयाल दहिया ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की नई मिसाल बन रहे हैं। समिति के अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में और भी निःशुल्क शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे। समिति के सचिव सोनू विश्वकर्मा ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा केन्द्र भेजने की अपील की। वहीं शिक्षक सुग्रीव प्रसाद साकेत एवं नवांकुर द्वारिका प्रसाद कुशवाहा ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और नियमित अध्ययन का महत्व बताया। समिति ने बच्चों को भविष्य में स्कूल बैग, ड्रेस, कॉपी, पेन सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने तथा समय-समय पर प्रोत्साहन स्वरूप उपहार देने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर धीरज वर्मा ने बच्चों के लिए कपड़े, किताबें एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समाज की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

पटवारी दिवस पर हल्का पटवारी क्षेत्र में रहें अनिवार्य रूप से उपस्थित, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश

लक्ष्य के अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण करें वृक्षारोपण कार्य : कलेक्टर गौरव बेनल

एनटीपीसी आवासों में अवैध रूप से रह रहे अधिकारियों की दो दिन में मांगी जानकारी, बलिया नाला के दूषित जल की जांच रिपोर्ट भी तलब

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर गौरव बेनल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सभी कार्य तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलों के हल्का पटवारी पटवारी दिवस पर अपने-अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराने को कहा, जो स्थानांतरण के बाद भी एनटीपीसी के आवासों में अवैध रूप से रह रहे हैं और अब तक आवास खाली नहीं किए हैं। वृक्षारोपण कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी विद्यालय नियमित समय पर संचालित हों तथा प्रवेश से वंचित बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कमिश्नर रीवा द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन अगली बैठक से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री, सीमांकन, बंटवारा, नक्शा तरमीम एवं विभिन्न विभागों को

भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़े किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए और आवश्यक कार्रवाई समय पर की जाए। बैठक में अधीक्षण यंत्री विद्युत को जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वहीं खाद एवं बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उप संचालक कृषि को किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उप संचालक पशु चिकित्सा को कामधेनु योजना के तहत स्वीकृत प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए 50 एवं 100 दिनों से लंबित शिकायतों के साथ-साथ जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वर्षा ऋतु में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग से बलिया नाला में प्रवाहित दूषित जल की जांच संबंधी जानकारी मांगी। संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल जांच रिपोर्ट एवं जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मानसून तैयारियों को लेकर नगर निगम सख्त, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जलभराव, स्वच्छता और सड़क सुधार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : देवेश पाण्डेय

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के नगर पालिक निगम सिंगरौली के अध्यक्ष देवेश पाण्डेय की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में मानसून तैयारियों, स्वच्छता व्यवस्था एवं नागरिक सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्षा ऋतु के दौरान आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि मानसून के दौरान नागरिकों को राहत उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर के सभी 45 वार्डों में जलभराव की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने और जहां भी पानी भरने की समस्या हो, वहां तत्काल जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था करने को कहा। बैठक में विशेष रूप से वार्ड क्रमांक-6 में लगातार सामने आ रही जलभराव की समस्या की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री पाण्डेय ने स्वच्छता विभाग को नियमित निरीक्षण करने तथा प्रत्येक वार्ड में समय पर कचरा उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई के बाद तुरंत कचरे का उठाव कराया जाए, ताकि दोबारा गंदगी और जलभराव की स्थिति न बने। इसके साथ ही मच्छरजनित बीमारियों की

रोकथाम के लिए सभी वार्डों में नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने के भी निर्देश दिए गए। नगर निगम अध्यक्ष ने शहर की आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर जोर देते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में सड़क और प्रकाश व्यवस्था बेहतर रहना नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैठक में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित समय पर सभी वार्डों और कॉलोनियों में पहुंचें तथा नियमित रूप से कचरा उठाव सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में प्रभावी और समयबद्ध कचरा प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 181 सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्पा सेंटरों के विरोध में सड़कों पर उतरे सामाजिक व धार्मिक संगठन, बंद कराने की मांग की

रिहायशी क्षेत्रों में संचालित स्पा सेंटरों को लेकर जताई चिंता, वैध लाइसेंस की भी उठी मांग

आज की जनधारा

सिंगरौली। शहर के रिहायशी क्षेत्रों और गली-मोहल्लों में संचालित स्पा सेंटरों को लेकर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को सनातन रक्षा मंच के कार्यकताओं ने शहर के विभिन्न स्पा सेंटरों का निरीक्षण कर प्रशासन से उनकी वैधता की जांच और नियमों के अनुरूप कार्रवाई की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि इनमें से कई सेंटर बिना वैध लाइसेंस के संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ सेंटरों में मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। निरीक्षण के दौरान कुछ सेंटर मिले बंद सनातन रक्षा मंच के कार्यकताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित स्पा सेंटरों का निरीक्षण किया।

संगठन का दावा है कि निरीक्षण की सूचना मिलने पर कुछ स्पा सेंटर संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। हालांकि, इस संबंध में संबंधित संचालकों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि शहर में संचालित अधिकांश स्पा सेंटरों के पास वैध लाइसेंस नहीं है। उनका दावा है कि कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा स्पा सेंटरों की जांच कर संचालकों को आवश्यक लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई सेंटर बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है। योजना के तहत धान, उड़द, मक्का, कोदो, अरहर सहित अन्य अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। कृषि विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट एवं रोग प्रकोप जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें खेती के

प्रति प्रोत्साहित करना है। ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक या पैक्स के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। वहीं गैर-ऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा, बी-1 अथवा पटवारी प्रतिवेदन) तथा आवश्यकतानुसार स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। कृषि विभाग एवं कृषि बीमा कंपनी ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए किसान अपने निकटतम कृषि विभाग, बैंक, पैक्स, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा कृषि बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। छोटा सा प्रीमियम, बड़ी सुरक्षा॰ के संदेश के साथ किसानों से अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने का आग्रह किया गया है।

कांग्रेस ने फर्जी मुकदमे का लगाया आरोप, एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन

रेनू शाह और राधिका प्रसाद शाह पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग

आज की जनधारा

सिंगरौली। सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि शाहवाल एवं जिला अध्यक्ष समेत कार्यकताओं पर दर्ज प्रकरणों को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं प्रकरण वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के उद्देश्य से राजनीतिक द्वेष के तहत झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2 जुलाई 2026 को पावर ग्रिड कंपनी के प्रबंधन एवं उसके ठेकेदार की कथित लापरवाही के कारण परसदेही निवासी जगदीश शाह की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजन न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेता का कहना है कि 3 जुलाई 2026 को पूर्व महापौर एवं पूर्व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी तथा कांग्रेस नेता ने शोक संतप्त परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मृतक के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इसके बावजूद रेनू शाह और राधिका प्रसाद शाह (पप्पू) के विरुद्ध शांति भंग करने, लोगों को जाम लगाने के लिए उकसाने तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ अभद्र व्यवहार एवं धमकी देने जैसे आरोपों में प्रकरण दर्ज कर

दिया गया। पार्टी का कहना है कि दोनों नेताओं ने न तो किसी शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और न ही किसी प्रकार का जाम लगाया। उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। कांग्रेस ने ज्ञापन में मांग की है कि पावर ग्रिड कंपनी के प्रबंधन और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध दोष तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा रेनू शाह एवं राधिका प्रसाद शाह (पप्पू) के खिलाफ दर्ज प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर उसे वापस लिया जाए। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच कर प्रकरण वापस नहीं लिया गया तो जिला कांग्रेस कमेटी जनहित और न्याय की मांग को लेकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में प्रसूता की मौत से बवाल, परिजनों ने इलाज में लापरवाही और रिश्वत मांगने का लगाए आरोप..

जहां जन्म की उम्मीद थी, वहां मातम पसर गया; जांच के आदेश, स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को बताया निराधार.

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद रविवार को जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही, कथित रूप से रिश्वत मांगने और अस्पताल स्टाफ के अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई और परिजन शव रखकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा समझाइश के बाद मामले को शांत कराया। मृतका की पहचान आरती ठाकुर, पति सूरज सिंह ठाकुर, निवासी दमोह के रूप में हुई है। बताया गया कि आरती अपने मायके झांसी (सिंगरौली क्षेत्र) आई हुई थीं। इसी दौरान प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का

आरोप है कि प्रसूता की हालत लगातार बिगड़ने के बावजूद समय पर ऑपरेशन नहीं किया गया। उनका यह भी आरोप है कि ऑपरेशन कराने के नाम पर पहले 30 हजार और बाद में 10 हजार की कथित मांग की गई। परिजनों के अनुसार रकम नहीं देने पर सामान्य प्रसव कराने का प्रयास किया गया, जिससे महिला की हालत और गंभीर हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रसव के दौरान महिला के पेट पर अत्यधिक दबाव डाला गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान हुई अफरा-तफरी और तोड़फोड़ में मृतका की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के अनुसार उसके हाथ की नस कट गई, जिससे काफी रक्तस्राव हुआ। उसे ट्रॉमा सेंटर के सर्जरी वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन बाद में चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल, रीवा रेफर कर दिया। इस घटना ने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता का दावा किया जाता है, तो गंभीर मरीजों को रीवा रेफर करने की नौबत क्यों आती है। उधर, अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। सिविल सर्जन ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है तथा प्रारंभिक स्तर पर तीन नर्सों की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पराज सिंह ने परिजनों द्वारा लगाए गए रिश्वत और लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि गर्भवती महिला की स्थिति अत्यंत गंभीर थी तथा चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली, प्रसूति सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों के प्रति व्यवहार को लेकर एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्रदेश की 34 लाख 45 हजार से अधिक पांडुलिपियों पन्नों का पंजीकरण, 12 लाख से अधिक पांडुलिपियों का हुआ सत्यापन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नई उपलब्धि! दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

ज्ञान भारतम ऐप पर मध्यप्रदेश ने अपलोड की सबसे अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ

आज की जनधारा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सांस्कृतिक अभ्युदय के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की धरती ने भारत की प्राचीन ज्ञान-संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के विषय में देश भर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की डिजिटल पहल 'ज्ञान भारतम् ऐप' के अनुसार, दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। यह सफलता राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक पटल पर पुनः स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश ने अब तक कुल 34 लाख 45 हजार 439 पांडुलिपियों पन्नों का पंजीकरण किया जा चुका है। 12 लाख 13 हजार 127 पांडुलिपियों का 'ज्ञान भारतम्' द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है शेष सत्यापन की प्रक्रिया में हैं, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में पांडुलिपियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान ज्ञान भारतम् अभियान के अंतर्गत पांडुलिपियों के पंजीकरण में मध्यप्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई तक के आकंड़ों के अनुसार इनमें भोपाल ने सबसे अधिक 24 लाख 26, हजार 172 पांडुलिपियों का पंजीकरण किया है। इसके बाद इंदौर में 3,99,477, रीवा में 2,68,763, बैतूल में 1,00,593 तथा छिंदवाड़ा में 77,094 पांडुलिपियां दर्ज की गईं। पन्ना से 64,257, सागर से 60,025, ग्वालियर से 29,870, उज्जैन से 20,995, रायसेन से 15,539, मंदसौर से 12,412, अनूपपुर से 11,829, नीमच से 8,950, मऊगंज से 8,406, खंडवा से 5,740, जबलपुर से 4,715, सतना से 4,061, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) से 4,049, गुना से 3,937, उमरिया से 3,824, दतिया से 3,179, विदिशा से 2,745, सीधी से 2,497, अशोकनगर से 1,908, बालाघाट से 1,741, शहडोल से 1,397, टीकमगढ़ से 1,290, मंडला से 957, शिवपुरी से 943, धार से 870, भिंड से 800, रतलाम से 731, मुरैना से 655, शाजापुर से 638, बड़वानी से 614, सीहोर से 607, सिवनी से 564, छतरपुर से 381, देवास से 330, श्योपुर से 310, नरसिंहपुर से 254, राजगढ़ से 198, निवाड़ी से 177, खरगोन से 171, मैहर से 146, दमोह से 133, बुरहानपुर से 120, हरदा से 84, कटनी से 83, आगर मालवा से 57, सिंगरौली से 33, झाबुआ से 17, अलीराजपुर से 8, पांढुर्ना से 3 तथा डिंडोरी से 1 पांडुलिपि का पंजीकरण किया गया।

10 feet long Janam patri have seen in Datia

लगभग 20 फुट लंबा प्राचीन पत्र

देश की प्राचीन मेधा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महायज्ञ- अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला

अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा सामान्य प्रशासन श्री शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पाण्डुलिपियाँ हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण, डिजिटलीकरण और पुनर्प्रसार भारत की प्राचीन ज्ञान-संपदा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इसी के साथ भारत अपनी ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करते हुए 'विश्व गुरु' की अपनी गौरवशाली पहचान को सशक्त बना रहा है। मध्यप्रदेश के जिलों के उत्कृष्ट प्रयासों ने न केवल प्रदेश की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संरक्षण को नई दिशा दी है, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर को संरक्षित करने के राष्ट्रीय अभियान को भी मजबूती प्रदान की है।

मध्यप्रदेश भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बना रहा है विशेष पहचान : श्रीराम तिवारी

मध्यप्रदेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार एवं वीरभारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश पूरी प्रतिबद्धता और जनभागीदारी के साथ साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'ज्ञान भारतम्' ऐप के माध्यम से प्रदेश से अब तक 34 लाख 45 हजार 439 दुर्लभ पांडुलिपियों का पंजीकरण होना और इस अभियान में मध्यप्रदेश का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ज्ञान परंपरा के संरक्षण का गौरवपूर्ण प्रमाण है। यह उपलब्धि केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि भारत की अमूल्य पांडुलिपि विरासत को सुरक्षित कर भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने के राष्ट्रीय संकल्प की सशक्त अभिव्यक्ति है। तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में जनसहभागिता के साथ इस अभियान को निरंतर गति दे रही है। प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और दस्तावेजीकरण न केवल भारत की ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा, बल्कि मध्यप्रदेश भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित एवं पहचान स्थापित करेगा। यह उपलब्धि प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक विरासत और ज्ञान-संपदा के संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

कांग्रेस ने शिक्षा, किसान, भूमि और आस्था से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा

मीनाक्षी नटराजन बोलीं— शिक्षा व्यवस्था, किसानों के अधिकार और प्रदेश की भूमि संकट में

आज की जनधारा

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद एवं तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा सरकार पर शिक्षा, किसानों, प्रदेश की भूमि और देश की आस्था के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर जनता की आवाज बनकर संघर्ष करेगी। पत्रकार वार्ता की शुरूआत करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और उज्जैन भूमि घोटाले जैसे गंभीर जनहित के मुद्दों को लेकर यह संवाद आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता खत्म हो रही है तथा लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं कृषि लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिल रही है। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य संकट में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। नीट और आरजीपीवी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वन नेशन, वन एग्जाम व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई है और परीक्षा केंद्रों पर व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान चला रही है। इसके तहत 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी तथा 9 अगस्त को चलो दिल्ली अभियान आयोजित किया जाएगा। किसानों की बढ़ती लागत और एमएसपी का मुद्दा कांग्रेस नेता ने कहा कि डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की कीमतों में लगातार वृद्धि से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही है। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों और कृषि टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के सीमित कोटे और सोयाबीन व डेयरी उत्पादों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की। उज्जैन भूमि घोटाले की जांच की मांग मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार का नया अध्याय उज्जैन भूमि घोटाले के रूप में सामने आया है। उन्होंने एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बिना पारदर्शिता के भूमि स्वामित्व में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।

मेट्रो स्टेशन से एमवीएम खेल मैदान को बचाने पूर्व छात्र मैदान में उतरे,प्रदर्शन किया

आज की जनधारा

भोपाल । राजधानी के शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान की कुछ भूमि मेट्रो स्टेशन के लिए दिए जाने के विरोध में आज मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों ने खेल मैदान में प्रदर्शन किया। शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन में पूर्व छात्रों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान को बचाने की गुहार की. हाथों में बैनर खेल mvm मैदान की गुहार...मेट्रो, मेलों, पार्किंग से मुक्त रखों श्रीमान लिए पूर्व छात्रों ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के लिए अगर भूमि अधिग्रहित की जाती है तो यहां निश्चित रूप से पार्किंग भी बनेगी, जिससे खेल मैदान तहस - नहस हो जाएगा। खेल मैदान के अलावा मेट्रो स्टेशन के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान कॉलेज के समीप ही उपलब्ध है, जहां से भूमि मेट्रो स्टेशन

के लिए ली जा सकती है। पूर्व छात्रों ने यह भी बताया कि एमवीएम के इस खेल मैदान से अनेक खेल प्रतिभाएं उभरकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रदर्शन कर चुकी हैं। कॉलेज के खिलाड़ियों व विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से यहां खेल अभ्यास किया जाता है. प्रदर्शन के बाद पूर्व विद्यार्थियो ने बैनर हाथों में लेकर मैदान का चक्कर लगाया और नारेबाजी की. इस अवसर पर एमवीएम एलुमिनी के उपाध्यक्ष डॉ. संतोष कटियार एवं प्रलय श्रीवास्तव, महासचिव सुभाष व्यास, कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र तौमर, धर्मेन्द्र खन्डेलवाल, आलोक श्रीवास्तव, सत्येन्द्र चौरसिया, अभिषेक द्विवेदी, अन्य पूर्व छात्र अरविंद गुप्ता, चंद्रशेखर धाकड़ (खेल अधिकारी), वसीम खान, राजीव दिवाकर, आरएस रघुवंशी, महेश नेमा, डीएस निगम, लोकेन्द्र रोहित, अनूप दांगी, मंगल सिंह, सिद्धांत जैन, मोहन सिंह ,सुधान्शु भाटी, फिरोज खान, फैजान सहित अनेक पूर्व छात्र मौजूद थे।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने एसजीएसयू के फामेर्सी विद्यार्थियों को दिए सफल करियर के मंत्र

वास्तविक उद्योग अनुभव और रोजगारपरक कौशल पर केंद्रित रहा विशेषज्ञ व्याख्यान

आज की जनधारा

भोपाल। स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी (एसजीएसयू) के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज द्वारा विद्यार्थियों को उद्योग जगत की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। ₹रियल वर्ल्ड स्किल्स के माध्यम से फामेर्सी विद्यार्थियों को सशक्त बनाना₹ विषय पर आयोजित इस सत्र में फार्मा करियर ब्रिज के संस्थापक एवं निदेशक श्री कृष्णेंदु मिश्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया। विशेषज्ञ व्याख्यान के दौरान श्री कृष्णेंदु मिश्रा ने फार्मास्युटिकल उद्योग में तेजी से बदलते परिदृश्य, रोजगार के नए अवसरों, उद्योग की अपेक्षाओं तथा करियर निर्माण के

लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को उद्योग की कार्यप्रणाली, तकनीकी दक्षता, संवाद कौशल और व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करना भी आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करने तथा निरंतर सीखने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विशेषज्ञ से विभिन्न करियर विकल्पों, फार्मा उद्योग में रोजगार की संभावनाओं, उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास से जुड़े विषयों पर संवाद किया। संवादात्मक सत्र में विद्यार्थियों को उद्योग के वास्तविक अनुभवों से सीखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर मिला।

उज्जैन मूक-बधिर एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी भाटपचलाना पुलिस की हिरासत में

पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई में एक घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

आज की जनधारा

उज्जैन। जिले में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरौद श्रीमती आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी भाटपचलाना सतेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना भाटपचलाना पर दर्ज अपराध क्रमांक 292/2026, धारा 333, 75(1) बी.एन.एस. के प्रकरण में मूक-बधिर एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के मात्र एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल निरुद्ध किया गया। 05.07.2026 को फरियादी सुनील पिता मुन्नालाल, निवासी ग्राम बालोदा लख्खा ने थाना भाटपचलाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 21 वर्षीय बहन घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान ग्राम बालोदा लख्खा निवासी मांगीलाल पिता बगदीराम अनाधिकृत रूप से घर में

घुस आया तथा युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना भाटपचलाना पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विशेष टीम का गठन किया। टीम ने बिना विलंब कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश प्रारंभ की तथा तकनीकी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके निवास स्थान से घटना के मात्र एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

उज्जैन माधवनगर पुलिस की सफलता झ सस्ते दाम पर सोना दिलाने के नाम पर लगभग 9.80 लाख की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया

उज्जैन। फरियादी द्वारा थाना माधवनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान राज उर्फ सुरेश से हुई, जिसने स्वयं को सोना-चांदी का व्यापारी बताते हुए बाजार मूल्य से कम कीमत पर सोना उपलब्ध कराने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर आरोपी ने अलग-अलग खातों एवं माध्यमों से बयाना एवं अन्य खर्च के नाम पर राशि प्राप्त की तथा अपने साथी रोहित उर्फ अंकुर जोशी को उज्जैन भेजकर फरियादी से7.62 लाख नगद भी प्राप्त करवा लिए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अलग-अलग बहाने बनाकर कुल लगभग 9.80 लाख की धोखाधड़ी की तथा रुपए वापस मांगने पर फरियादी को झूठे प्रकरण में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी। 18.05.2026 को आरोपियों ने पुनः फरियादी को पीजीव्हीटी ग्राउंड, उज्जैन बुलाकर सोना देने का झांसा दिया। फरियादी द्वारा तत्काल थाना माधवनगर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित उर्फ अंकुर जोशी को मौके से गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ राज मौके से फरार हो गया था। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी- प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए फरार मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ राज पिता कांतिलाल जोशी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम दादका, जिला पाटन (गुजरात) की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया। थाना माधवनगर पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित कर गुजरात रवाना की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, मुखबिर सूचना एवं स्थानीय स्तर पर लगातार जानकारी एकत्रित करते हुए आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को उसके निवास स्थान ग्राम दादका, जिला पाटन (गुजरात) से विधिवत गिरफ्तार किया।

संघर्ष, संकल्प और सफलता की मिसाल थे प्रकाशचंद गुप्ता

बुरहानपुर से मुंबई तक का सफर, कठिन परिस्थितियों में भी नहीं मानी हार; परिवार, शिक्षा और संस्कारों को बनाया जीवन का आधार

आज की जनधारा

बुरहानपुर। जीवन में सफलता केवल साधनों से नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। इसी सत्य को अपने जीवन से चरितार्थ करने वाले स्वर्गीय श्री प्रकाशचंद गुप्ता ने संघर्षों के बीच सफलता की ऐसी कहानी लिखी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनका जीवन सादगी, मेहनत, परिवार के प्रति समर्पण और दूरदर्शिता का अद्भुत उदाहरण रहा। बुरहानपुर में हुआ जन्म, संघर्षों के बीच पूरी की शिक्षा श्री प्रकाशचंद गुप्ता का जन्म 21 फरवरी 1948 को बुरहानपुर में श्री गंगाराम गुप्ता के परिवार में हुआ। प्रारंभिक जीवन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और विज्ञान विषय से बीएससी की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण शुरू से ही उन्हें अन्य लोगों से अलग पहचान दिलाता था। रोजगार की तलाश में पहुंचे मुंबई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में मायानगरी मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने अपने करियर की शुरूआत एक कंपनी एनसंस में ड्राफ्ट्समैन के रूप में की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा। विवाह और पारिवारिक जीवन की शुरूआत वर्ष 1974 में उनका विवाह धनाग्र परिवार के श्री बाबूलाल टीकमदास दलाल की सुपुत्री श्रीमती हंसाबेन के साथ संपन्न हुआ। यह दांपत्य जीवन प्रेम, विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की मजबूत नींव पर आधारित रहा। परिवार में वर्ष 1976 में प्रथम पुत्र मनीष (नरेंद्र) गुप्ता का जन्म हुआ। इसके बाद वर्ष 1978 में दूसरे पुत्र हरीश गुप्ता और वर्ष 1980 में तीसरे पुत्र अश्विन गुप्ता ने जन्म लिया। परिवार के बढ़ते दायित्वों के बीच भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। मुश्किल दौर में भी नहीं हारी हिम्मत वर्ष 1980 में कंपनी में हुई लंबी हड़ताल के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। यह उनके जीवन का चुनौतीपूर्ण दौर था, लेकिन उन्होंने

परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय नए अवसर तलाशे। वर्ष 1982 में वे महाराष्ट्र के अक्कलकोट क्षेत्र पहुंचे और वहां मोटर पंप एवं इलेक्ट्रिक व्यवसाय की शुरूआत की। साथ ही कुछ मित्रों के सहयोग से खेती-किसानी का कार्य भी प्रारंभ किया। कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच के बल पर उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बच्चों की शिक्षा को बनाया सर्वोच्च प्राथमिकता श्री प्रकाशचंद गुप्ता का मानना था कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे वर्ष 1992 में पुनः मुंबई लौट आए। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वर्ष 1997 में बड़े पुत्र मनीष गुप्ता ने स्नातक शिक्षा के साथ कंप्यूटर क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की। दूसरे पुत्र हरीश गुप्ता ने वर्ष 2000 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की उपाधि हासिल की। वहीं तीसरे पुत्र अश्विन गुप्ता ने कॉमर्स क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2002 में ऑडिटिंग के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई। शेयर बाजार में भी बनाई पहचान मुंबई लौटने के बाद उन्होंने शेयर बाजार के क्षेत्र में भी अपनी सूझबूझ और अनुभव का परिचय दिया। अपनी समझ और दूरदर्शिता के बल पर उन्होंने इस क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। उनका मानना था कि निरंतर सीखते रहने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। परिवार को सफल होते देख मिली सबसे बड़ी खुशी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को स्थापित होते देखा। सभी पुत्रों के विवाह संपन्न हुए और परिवार खुशहाली की ओर अग्रसर हुआ। अपने संघर्षों का फल अपने परिवार की सफलता के रूप में देखकर उन्हें सबसे अधिक संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होती थी। मुस्कुराते हुए कहा जीवन को अलविदा जीवन के अंतिम समय में उन्हें हृदय संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। उपचार के दौरान हृदय में स्टेंट भी डाला गया, लेकिन स्वास्थ्य लगातार चुनौती बना रहा। अंततः उन्होंने होराइजन प्राइम हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। परिवारजन बताते हैं कि वे अंतिम समय तक सकारात्मक सोच और मुस्कुराहट के साथ जीवन जीते रहे। उन्होंने अपने पीछे ऐसा परिवार, संस्कार और प्रेरणादायक जीवन यात्रा छोड़ी, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन देती रहेगी। प्रेरणा बन गया उनका जीवन स्वर्गीय श्री प्रकाशचंद गुप्ता का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, परिश्रम और परिवार के प्रति समर्पण हो तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। संघर्षों से शुरू हुआ उनका सफर सम्मान, उपलब्धियों और पारिवारिक खुशियों के साथ पूर्ण हुआ। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।

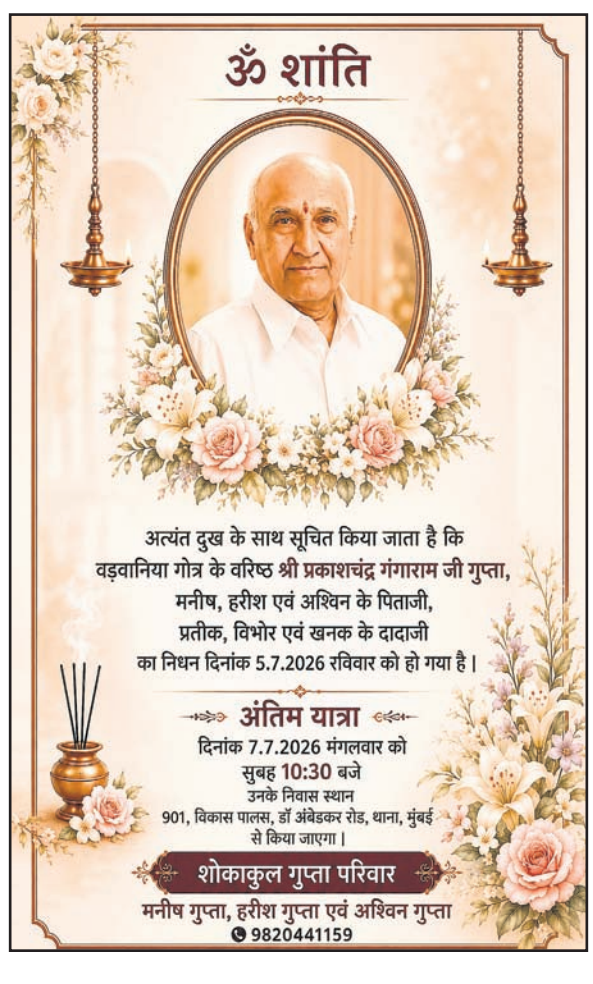

तिरछी नज़र से

जब B.Tech की डिग्री भी 'ग्रेजुएट' कहलाने के लिए कम पड़ जाए!

प्रभातदत्त झा

मैं आपकी तरह ही एक आम मध्यमवर्गीय परिवार का सदस्य हूँ. मेरा नाम अनुज है। मैं B.Tech करके 2025 में पास हुआ। मुझे नौकरी की कोशिश में 11 महीने हो गए। 500 से ज़्यादा रिज्यूमे भेजे। 20 इंटरव्यू दिए। 3 ऑफर मिले, पर सैलरी इतनी कि उसमें पेट्रोल और कैंटीन का खर्च नहीं निकलता।

मेरे पिता ने मेरी डिग्री के लिए 20 लाख रुपए लोन लिया था। अब उस लोन की EMI 18 हजार है। और मुझे मिल रही है-12 हजार की नौकरी। मतलब मैं हर महीने अपनी नौकरी से 6 हजार अपने लोन में लगा रहा हूँ - और यह गणित सुनकर देश का कोई भी अर्थशास्त्री रोएगा, क्योंकि इससे तो कम सिद्धांतों में उलझना है।

नौकरी के लिए क्या चाहिए? उनका कहना है - कोई 'स्किल' चाहिए। 4 साल कॉलेज में हमने क्या पढ़ा? थ्योरी, न्यूटन के नियम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वह कोडिंग जो 2015 में भी पुरानी थी। जब मैंने इंटरव्यू में बताया- 'मुझे यह आता है,' तो उन्होंने कहा- 'यह आउटडेटेड है, हमें AI और ML चाहिए।' मैंने कहा - 'वह क्या है?' उन्होंने मुस्कुराकर बताया 'जिसने आपकी डिग्री बेकार कर दी।'

दोस्त सुमित ने MBA किया। उसके 25 लाख लगे। अब वह 'बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव' है - जिसका काम कॉल सेंटर में लोगों को ठगना है। उसे हर दिन 100 कॉल करनी हैं। सैलरी 20 हजार। EMI 22 हजार। वह घर से पैसे माँगता है-और उसे 'नौकरीपेशा' कहते हैं। असल में वह अपनी डिग्री की लागत वसूलने में 12 साल लगाएगा - तब तक उसकी शादी होगी, बच्चा होगा, और वह अपने बच्चे को एडमिशन के चक्कर में फिर कोचिंग में डाल देगा।

यही तो हमारी युवा पीढ़ी की कहानी है - हम जितना पढ़ते हैं, उतना पीछे होते जाते हैं। हमारे पिता 10वीं पास थे, पर उनके पास घर था। हम 12वीं में 90% लाते हैं, पर किराए के मकान में रहते हैं। सरकार कहती है - 'शिक्षित बनो।' हम बने, तो सरकार ने हमसे पूछा 'अब जॉब तुम खुद ढूँढो, हम तो बस कॉलेज बनाते हैं।'

और सबसे बड़ी विडंबना - कॉलेज में हमें जो सिखाया जाता है, वह इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता। जो पूछा जाता है, वह कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। और जो हम खुद सीखते हैं, उसके लिए हमें पैसे देने होते हैं - ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट फीस। यानी एक बार डिग्री के लिए दिए, दूसरी बार स्किल के लिए दिए, तीसरी बार नौकरी पाने के लिए दिए। और नौकरी मिली भी तो उसमें से तीनों EMI निकालनी हैं।

आज मैं 25 का हूँ। मेरे पास 22 साल की 'फॉर्मल एजुकेशन' है, 4 लाख के ऑनलाइन कोर्स हैं, 3 इंटर्नशिप हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं, पर जेब में 50 रुपए हैं। और माँ कहती है 'बेटा, तोहरी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ?' मैं कहता हूँ - 'फायदा यह हुआ कि मुझे एहसास हो गया कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है।'

कल एक शादी में गया। लोगों ने पूछा - 'क्या करते हो?' मैंने कहा- 'नौकरी की तलाश में हूँ।' उन्होंने सहानुभूति दी - मानो किसी रोगी को सांत्वना दे रहे हों। मैंने सोचा-मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, जो इस देश में बीमारी से भी बदतर है - क्योंकि बीमारी का इलाज है, पर बेरोज़गारी का नहीं।

सच कहूँ तो हमारी डिग्री ने हमें कुछ नहीं दिया, सिवाय एक 'प्रमाणपत्र' के कि हम 4 साल तक कॉलेज में बैठकर बोर हुए। और अब जब हम असली दुनिया में आते हैं, तो पता चलता है - यहाँ डिग्री नहीं, कनेक्शन चलते हैं। जिसके बाबूजी जानते हैं, वह कलेक्टर है; जिसके नहीं, वह संग्रहकर्ता है - सवाल पूछता है कि 'क्या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है?'

मुझे तो अब लगता है - 'न्यू इंडिया' में 'न्यू जॉब' का मतलब 'नई बेरोज़गारी' है। और हम इस बेरोज़गारी को 'स्टार्टअप' या 'फ्रीलांसिंग' का नाम देकर खुद को 'सेल्फ-एम्प्लॉयड' कहते हैं- क्योंकि 'बेरोज़गार' सुनने में बहुत बुरा लगता है। पर दोनों की जेब एक जैसी खाली है- बस एक नाम में फ़र्क है।

डिजिटल करेंसी और कैशलेस इकॉनमी

क्या हम बिना नोटों के संसार के लिए तैयार हैं?

शशांक झा

आज से ठीक एक दशक पहले अगर कोई आपसे कहता कि आपको अपनी जेब में एक भी रुपया (नोट या सिक्का) रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी पूरी दिनचर्या–सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक-महज एक स्क्रीन स्वाइप या QR कोड स्कैन से चल जाएगी, तो शायद आप हंस देते। लेकिन आज यह भारत और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सच्चाई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक बड़े तकनीकी संक्रमण (Transition) से गुजर रही है। लिक्विड कैश (नकद) की जगह अब बाइट्स और कोड्स ने ले ली है। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ हमारी सहूलियत तक सीमित है, या यह वैश्विक आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से री-प्रोग्राम कर रहा है? आइए, इस वित्तीय क्रांति की परतों को टटोलते हैं।

बदलाव की रफ्तार: आंकड़ों की जुबानी

कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ते कदमों को समझने के लिए किसी जटिल आर्थिक थ्योरी की जरूरत नहीं है, बस आंकड़ों पर एक नजर डालना ही काफी है।

- **UPI का दबदबा:** अकेले भारत में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (PI) हर महीने अरबों रुपये के लेन-देन को संभाल रहा है। हालिया वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, डिजिटल ट्रांजैक्शन की सालाना वृद्धि दर 40% से अधिक बनी हुई है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** स्वीडन जैसी अर्थव्यवस्थाएं पहले ही 'लगभग 100त्न कैशलेस' होने के करीब पहुंच चुकी हैं, जहां कुल जीडीपी का 1त्न से भी कम हिस्सा भौतिक नकदी में रह गया है।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** दुनिया के 90त्न से अधिक केंद्रीय बैंक (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का 'ई-रुपया' भी शामिल है) अपनी डिजिटल मुद्रा के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या इसे लॉन्च कर चुके हैं।

विशेषज्ञों की राय: वरदान या अदृश्य जाल?

इस डिजिटल लहर पर दुनिया भर के अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। इसके फायदे जितने चमकीले हैं, इसके पीछे छिपे जोखिम भी उतने ही गंभीर हैं।

'डिजिटल करेंसी न केवल लेन-देन की लागत को कम करती है, बल्कि यह समानांतर अर्थव्यवस्था (ब्लैक मनी) पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब हर पैसे का डिजिटल फुटप्रिंट होगा, तो टैक्स चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी बेहद मुश्किल हो जाएगी।' - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नीति विश्लेषक

इसके विपरीत, कुछ विशेषज्ञ एक अलग चिंता जताते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पूरी तरह से कैशलेस होने से समाज का वह वर्ग हाशिए पर जा सकता है जो तकनीकी रूप से साक्षर नहीं है।

'कैशलेस इकॉनमी एक दोधारी तलवार है। जहां यह पारदर्शिता लाती है, वहीं यह नागरिकों की वित्तीय गोपनीयता (Privacy) को भी खत्म करती है। अगर पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया, तो सरकार या बैंक एक क्लिक से किसी भी व्यक्ति का वित्तीय एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं।'

चुनौतियाँ: जो इस रास्ते को पथरीला बनाती हैं

चमकते हुए डिजिटल डैशबोर्ड के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है:

- **साइबर सुरक्षा (Cyber Security):** आए दिन होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और डेटा लीक इस व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी हैं। एक आम आदमी का डिजिटल वॉलेट सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
- **डिजिटल डिवाइड (Digital Divide):** शहरों में तो हर रेहड़ी-पटरी वाला QR कोड लिए खड़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली और इंटरनेट की अनिश्चितता डिजिटल इकोनॉमी के रास्ते का रोड़ा है।
- **मनोवैज्ञानिक खर्च (Psychological Spending):** मनोवैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के संयुक्त अध्ययन बताते हैं कि जब हम हाथ से भौतिक नोट गिनकर खर्च करते हैं, तो हमें 'खर्च का अहसास' (Pain of Paying) होता है। इसके विपरीत, सिर्फ स्क्रीन पर नंबर स्वाइप करने से लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च (Overspending) करने लगे हैं, जो व्यक्तिगत कर्ज को बढ़ावा दे रहा है।

भविष्य का मार्ग: संतुलन ही समाधान है

तो, क्या नकद पूरी तरह गायब हो जाएगा? इसका जवाब है–शायद नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। एक आदर्श अर्थव्यवस्था वह नहीं है जो जबरन पारंपरिक तरीकों को बंद कर दे, बल्कि वह है जो एक 'लेस-कैश' (Less-Cash) सोसाइटी का निर्माण करे, न कि पूरी तरह 'कैश-लेस' की जिद पकड़े। डिजिटल करेंसी को बैकअप के तौर पर भौतिक नकदी का सहारा मिलना जरूरी है ताकि किसी भी तकनीकी ब्लैकआउट या वित्तीय संकट के समय अर्थव्यवस्था ठप न हो।

निष्कर्ष : डिजिटल करेंसी और कैशलेस ट्रांजैक्शन महज एक ट्रेंड या वायरल टॉपिक नहीं हैं; यह मानव सभ्यता के विकास का अगला तार्किक कदम है। वस्तु विनिमय (Barter System) से सोने के सिक्कों, सिक्कों से कागज के नोटों, और नोटों से प्लास्टिक कार्ड्स तक का सफर अब स्मार्टफोन के स्क्रीन में सिमट गया है। विजेता वही देश और समाज होगा, जो मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियों और वित्तीय साक्षरता के साथ इस बदलाव को गले लगाएगा। आपकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन आपका डिजिटल वॉलेट सुरक्षित और समझदारी से भरा होना चाहिए।

सहायक ब्रांच मैनेजर, इंडियन बैंक
(आर्थिक और बैंकिंग मामलों के एक्सपर्ट)
श्यामनगर,सतना मध्यप्रदेश

इस क्रांति के तीन मुख्य स्तंभ

इस वायरल और स्थायी आर्थिक बदलाव को तीन मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है:

स्तंभ	-	फिनटेक ऐप्स (UPI/Wallets)
मुख्य विशेषता	-	त्वरित और सुलभ
आर्थिक प्रभाव	-	खुदरा व्यापार में तेजी और नकदी प्रबंधन के खर्च में कमी।
स्तंभ	-	CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी)
मुख्य विशेषता	-	सरकारी संप्रभुता और सुरक्षा
आर्थिक प्रभाव	-	बैंकों पर निर्भरता कम करना और क्रॉस-बॉर्डर (अंतर्राष्ट्रीय) पेमेंट को सस्ता बनाना।
स्तंभ	-	क्रिप्टोकरेंसी (Decentralized)
मुख्य विशेषता	-	बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के
आर्थिक प्रभाव	-	उच्च जोखिम और अस्थिरता, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक का नवाचार।

बरसात का मौसम है, पर बरतें पूरी सावधानी: जरा सी लापरवाही बन सकती है भारी नुकसान की वजह

नूपुर शर्मा

खिड़कों के बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की पहली बूंदें जितना सुकून देती हैं, उतना ही खतरा भी अपने साथ लेकर आती हैं। हर साल मानसून के दौरान लाखों घरों और दुकानों को सीलन, जलभराव और शॉर्ट-सर्किट जैसी घटनाओं से नुकसान होता है – और हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश नुकसान सिर्फ थोड़ी सी सतर्कता बरतकर पूरी तरह टाले जा सकते थे। सवाल यह नहीं कि बारिश आएगी या नहीं, सवाल यह है कि आप उसके लिए कितने तैयार हैं।

छत और नालियां: सबसे पहली जांच

मानसून से पहले छत, दीवारों और पानी निकासी व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण जरूरी है। छत पर जमी काई, टूटी टाइलें या बारीक दरारें शुरुआत में मामूली लगती हैं, पर लगातार पानी के संपर्क में रहने से यही दरारें कंक्रीट के भीतर सरिया तक पानी पहुंचा देती हैं, जिससे संरचना कमजोर होती है। नालियों में फंसी पत्तियां और कचरा पानी की निकासी रोक देते हैं, और यहां रुका हुआ पानी सीलन व फफूंद की जड़ बनता है।

बिजली से जुड़ी सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी :

बारिश के मौसम में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा और सबसे घातक होती हैं। ढीले तार, खुले स्विच-बोर्ड और पुरानी वायरिंग नमी के संपर्क में आते ही खतरा बन जाते हैं। मानसून शुरू होने से पहले किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से पूरे परिसर की वायरिंग जंचवा लेना बुद्धिमानी है। इनवर्टर, स्टेबलाइजर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को ऊंचाई पर और नमी से दूर रखें।

कीमती सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा*

निचले इलाकों में स्थित घरों और दुकानों के लिए यह सलाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है – जरूरी दस्तावेज, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कीमती सामान हमेशा जमीन से ऊंचाई पर रखें। वाटरप्रूफ बॉक्स या मजबूत प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल एक छोटा निवेश है, जो बड़े नुकसान से बचा सकता है। वाहनों को भी जलभराव वाले स्थानों से दूर, ऊंचाई पर पार्क करें।

पेड़ और भवन की नींव पर नजर

कमजोर या सूखी शाखाएं तेज हवा में टूटकर मकान, वाहन या बिजली की लाइनों पर गिर सकती हैं – इनकी समय पर कटाई कराएं। साथ ही भवन के चारों ओर पानी जमा न होने दें, क्योंकि लगातार नमी नींव की मजबूती को धीरे-धीरे कमजोर करती है, भले ही यह असर तुरंत नजर न आए।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अतिरिक्त सतर्कता

दुकानों और कार्यालयों में अग्निशमन यंत्र, जल निकासी व्यवस्था और बिजली सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच जरूरी है। जहां संभव हो, भवन और व्यावसायिक संपत्ति का बीमा भी करा लेना चाहिए – यह ऐसा सुरक्षा कवच है जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक झटके को काफी हद तक कम कर देता है।

मानसून प्रकृति का वह उपहार है जो धरती को हरा-भरा और जीवन को तरोताजा करता है, बशर्ते हम उसका स्वागत तैयारी के साथ करें। दरवाजे की एक कील ठोंकने, एक तार को दुरुस्त कराने, एक नाली को साफ कराने जैसे छोटे-छोटे कदम ही असल में वह मजबूत नींव रचते हैं जिस पर परिवार का सुकून और संपत्ति की सुरक्षा दोनों टिकी होती हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए – क्योंकि बारिश का आनंद तभी पूरा है जब मन में कोई फिक्र न हो।

– बिलासपुर, छत्तीसगढ़

जीएसटी : 9 साल, 2.5 लाख करोड़ पार

आम आदमी की जेब और राज्यों का खजाना, कैसे बदला?

रायपुर के किराना व्यापारी संजय अग्रवाल की दुकान पर पहले 'वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स' की अलग-अलग बहीखाते होती थीं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद उनकी उलझन तो कम हुई, लेकिन ऑनलाइन रिटर्न (GSTR-1, 3B) भरने की नई चुनौती भी आई। यह कहानी सिर्फ संजय की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय कारोबारियों और उपभोक्ताओं की है। देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और आंकड़े बताते हैं कि यह सफर रिकॉर्ड राजस्व संग्रह से भरा तो रहा, पर आम आदमी तक इसकी मीठास अब भी पूरी तरह नहीं पहुंची है।

आम आदमी और छोटे कारोबारी को क्या फायदा? : जीएसटी का सबसे बड़ा वादा था 'टैक्स पर टैक्स' (Cascading Effect) खत्म होना और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होना। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 9 सालों में 100 से अधिक वस्तुओं को 28% के टॉप स्लैब से निकालकर 18% या 5% के स्लैब में रखा गया है।

उदाहरण के तौर पर: फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर (28% से घटकर 18%) एक रू. 50,000 की एसी पर आपको करीब रू. 5,000 की सीधी बचत हो गई है। रेस्टोरेंट में खाना (पहले सर्विस टैक्स+VAT मिलाकर 20.5% लगता था, अब 5% बिना ITC वाले) - महीने में रू 10,000 खर्च करने वाले परिवार को करीब रू 1,500 की मासिक बचत।

हालांकि, छोटे कारोबारियों (MSMEs) के लिए तीन अलग-अलग रिटर्न (GSTR-1, 3B, 9) और महीने की 10वीं, 20वीं, 30वीं की समय-सीमा अब भी एक उलझन भरा जाल है। रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी रमेश साहू कहते हैं, 'जीएसटी से कर तो सरल हुआ, पर कंप्लायंस का बोझ और मैनपावर खर्च दोगुना हो गया।

छत्तीसगढ़ की स्थिति : अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय आंकड़े न देखकर छत्तीसगढ़ पर नज़र डालें, तो राज्य ने इस साल जून (2026) तक करीब रू 3,200 करोड़ का मासिक GST संग्रह किया है, जो पिछले साल जून की तुलना में 12.5% की बढ़ोतरी दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के व्यापार मंडल (CGTMA) के अनुसार, लौह-अयस्क, सीमेंट और FMCG उत्पादों ने इस संग्रह में सबसे बड़ा योगदान दिया है। राज्य अब देश के टॉप-10 GST राज्यों में अपनी जगह बनाने के करीब है।

अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत की क्या राय है? : केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद मोहन कहते हैं: 'जीएसटी भारत के कर इतिहास की सबसे बड़ी संस्थागत उपलब्धि है। रू 60,000 करोड़ (2017) से रू 2.5 लाख करोड़ (2026) तक की यात्रा अभूतपूर्व है। लेकिन अगले 9 सालों की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम 3-स्लैब संरचना को कितना सरल कर पाते हैं।' वहीं, FICCI के टैक्स कमेटी के प्रमुख श्री सुधीर मेहता ने जारी बयान में कहा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (फास्टैग लिंक, ई-वे बिल) ने कारोबार को पारदर्शी बनाया है, फिर भी स्लैब की जटिलताओं को कम करने की जरूरत है।

क्या चुनौतियाँ बाकी हैं? : सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, जीएसटी के 'नौ साल' में कई विवाद भी रहे हैं: राज्यों की क्षतिपूर्ति (Compensation Cess) जून 2022 में समाप्त हो गई। इसके बाद से कई राज्यों (विशेषकर पिछड़े और औद्योगिक राज्य) को राजस्व घाटा हो रहा है। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर इसे 'केंद्र की एकतरफा कर प्रथा' करार दिया।

न्याय की राह को सुगम बनाती हाई कोर्ट समर्पित बस सेवा : एक अनिवार्य आवश्यकता

न्यायालय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और छत्तीसगढ़ और उच्च न्यायालय इसका केंद्र है। बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय शहर के बसावट से दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जैसा कि सभी जानते हैं कि यहां हजारों की संख्या में अधिवक्ता न्यायिक कर्मचारियों और पक्षकार पहुंचते हैं ,ऐसे में न्यायालय की सुरक्षा समयबद्धता और सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधाजनक सिटी बस सेवा अब केवल सुविधा नहीं बल्कि समय की मांग बन चुकी है यह केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक निवेश है जिससे न्यायपालिका की गरिमा और कार्य क्षमता दोनों में सुधार होगा

अन्य राज्यों में सफल प्रयोग:- दिल्ली मे वर्ष 2000- 2003 में एवं केरल में 2005 में कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए विशेष सटल सेवाएं उपलब्ध हैं इन सेवाओं के कारण वाहन निजी वाहनों का रोड पर दबाव 40% तक काम हुआ है कई राज्यों में राज्य परिवहन निगम के साथ अनुबंध कर फ्यूल सेफ्टी और राजनीति दरों पर संचालन का मॉडल अपनाया है जिससे सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ता है।

बोदरी का सफर:- पिछले कुछ वर्षों से बिलासपुर से बोदरी मार्ग पर यातायात का दबाव तेजी से बड़ा है परिवहन विभाग एव पुलिस रिकॉर्ड और ट्रैफिक सर्वे के आधार पर बोदरी मार्ग के यातायात की स्थिति कुछ इस प्रकार है एक अनुमान के मुताबिक

बिलासपुर रायपुर हाईवे NH 30 पर बोदरी के पास प्रतिदिन 15000 से 20000 के बीच वाहन गुजरते हैं इसमें शामिल है

न्यायिक आवाजाही:- 3000 से 4000 वहां कर और बाइक केवल उच्च न्यायालय के अधिवक्ता स्टाफ और पत्रकारों एवं सरकारी अधिकारियों के होते हैं।

भारी वाहन:- रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से प्रतिदिन 4000 से अधिक भारी वाहन ट्रक ट्रेलर गुजरते हैं जो छोटे वाहनों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

हाई कोर्ट मार्ग पर यातायात का सबसे अधिक दबाव दो समय पर होता है

1. सुबह 9:30 से 11:30 जब कोर्ट का स्टाफ और अधिवक्ता आते हैं
2. शाम 4:30 से 6:30 जब कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होती है

इन घंटो में यातायात की गति 40% कम हो जाती है औसतन इस मार्ग पर प्रति माह 10 से 15 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं जिसमें दो पहिया वाहन सवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

पार्किंग स्थिति:- उच्च न्यायालय परिसर में पार्किंग की क्षमता लगभग 1500 से 2000 वाहनों की है लेकिन वर्तमान में यहां आने वाले वाहनों की संख्या अक्सर इस क्षमता को पार कर जाती है बस सुविधा होने पर वाहनों का जमावड़ा 60त्न तक काम हो सकता है।

प्रस्तावित बस सेवा के बहुआयामी लाभ:-

1. आर्थिक बचत और ईंधन सुरक्षा
2. सुरक्षा और स्वास्थ्य
3. पर्यावरण योगदान
4. कार्य क्षमता में सुधार।

निष्कर्ष :- आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बिलासपुर रायपुर मार्ग पर बोदरी के समीप प्रतिदिन 15000 से अधिक वाहनों का दबाव रहता है इससे एक बड़ी संख्या उन दो पहिया वाहनों की है। जिसमें उच्च न्यायालय के कर्मचारी और जूनियर अधिवक्ता जान जोखिम में डालकर हाईवे पर यात्रा करते हैं बाहरी वाहनों की बढ़ती दबाव और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए समर्पित बस सेवा न केवल सुविधा बल्कि जीवन सुरक्षा का भी विषय हैं।

डॉ. निधि गुप्ता
एडवोकेट, एम.लिब.
(न्यायिक मामलों की विशेषज्ञ । आम आदमी और मध्यम वर्ग की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से प्रभावी विश्लेषण)

भूस्खलन से रेल सेवा बाधित, कौन-कौन सी ट्रेनें हुईं रद्द

मुंबई। मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली रेल सेवाएं सोमवार तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गईं। मध्य रेलवे के अनुसार, करजत-लोनावला के बीच भोर घाट सेक्शन में दो जगह भूस्खलन होने से रेलवे की तीनों लाइनें प्रभावित हुई हैं। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, रीशेड्यूल और कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर जांचने की अपील की है।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि पहला भूस्खलन ठाकुरवाड़ी के पास हुआ, जबकि दूसरा हादसा खंडाला और मंकी हिल के बीच मध्य लाइन पर तड़के करीब 3:05 बजे हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे मुंबई-पुणे मार्ग पर रेल परिचालन रोकना पड़ा। रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक से मलबा हटाने और रेल सेवाएं बहाल करने में जुटी हैं।

भूस्खलन से कौन-कौन सी रेल लाइनें प्रभावित हुईं?

करजत और लोनावला के बीच स्थित भोर घाट सेक्शन पश्चिमी घाट का सबसे चुनौतीपूर्ण रेल मार्ग माना जाता है। इस सेक्शन में मुंबई की ओर जाने वाली अप लाइन, पुणे की ओर जाने वाली डाउन लाइन और एक मध्य लाइन है। रेलवे के अनुसार, दोनों स्थानों पर हुए भूस्खलन का असर तीनों लाइनों पर पड़ा है। इसी वजह से मुंबई और पुणे के बीच ट्रेनों का संचालन पूरी तरह प्रभावित हुआ। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों का संचालन रोक दिया है और मरम्मत कार्य जारी है।

किन ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?

रेलवे ने छह जुलाई के लिए कुल 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें सीएसएमटी-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, प्रगति एक्सप्रेस, सिंहगढ़ एक्सप्रेस और धुले एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा कई लंबी दूरी की ट्रेनों को दूसरे मार्गों से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते तक सीमित किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है।

यात्रियों को क्या सलाह दी गई?

- ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा।
- रेलवे की टीमें लगातार बहाली का काम कर रही हैं।
- भारी बारिश के कारण हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
- यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर जांचें।
- केवल रेलवे की आधिकारिक सूचना और अपडेट पर ही भरोसा करें।
- सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही मुंबई-पुणे रेल सेवाएं सामान्य होंगी।

यात्रियों के लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की?

रेलवे ने कहा है कि ट्रैक से मलबा हटाने और रेल सेवाएं जल्द सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (022-22694040), ठाणे (9321336747), लोनावला (8356854238) और दादर (9136452387) से यात्री अपनी ट्रेन की स्थिति और यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे क्यों हुआ बंद?

भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई-पुणे हाईवे सोमवार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल मुंबई और पुणे के बीच यात्रा न करें। एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक सेक्शन के बीच कंक्रीट का एक पिलर सड़क पर गिर गया, जबकि खोपोली-कुसगांव मिसिंग लिंक पर टनल-2 के पास भूस्खलन होने के बाद सुबह करीब चार बजे से यातायात डायवर्ट कर दिया गया।

वहीं पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर कई जगह जलभराव के कारण यातायात रोक दिया गया है। मावल और ताम्हिणी घाट में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि लोहगढ़ किले के पास पाटन गांव में भूस्खलन के कारण एक परिवार के फंसे होने की सूचना पर बचाव अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) और हाईवे ट्रैफिक पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों को केवल बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन की ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।

फिर सुर्खियों में तमिलनाडु लोकभवन

विजय सरकार में वन मंत्री के गंभीर आरोप

चेन्नई। विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने रविवार को तमिलनाडु में ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अलग कानून बनाने की अपनी मांग दोहराई। पार्टी ने कहा कि इस दिशा में विधायी स्तर पर प्रयास जारी हैं और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

ऑनर किलिंग पर सख्त कानून की वकालत

पत्रकारों से बातचीत में सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने कहा कि VCK का स्पष्ट और अडिग रुख है कि ऑनर किलिंग जैसी जघन्य घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे अपराधों को किसी भी स्थिति में न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी तरह का संरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, 'विधानसभा में अपने पहले ही भाषण के दौरान मैंने ऑनर किलिंग रोकने के लिए एक अलग और समर्पित कानून बनाने की मांग उठाई थी। VCK ने पहले भी इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए हैं।'

'जल्द बनेगा समर्पित कानून'

वन्नी अरासु ने भरोसा जताते हुए कहा, 'बहुत जल्द आप ऑनर किलिंग के खिलाफ एक समर्पित कानून बनते देखेंगे। जब ऐसा होगा, तब आप भी इस पहल की सराहना करेंगे।'

गवर्नर पर संविधान की अनदेखी का आरोप

तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने के जवाब में मंत्री ने कहा कि उनकी गतिविधियां संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गवर्नर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के समानांतर प्रशासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान की भावना के खिलाफ है।

'मुख्यमंत्री और कैबिनेट का सम्मान करना चाहिए'

मंत्री ने कहा, 'गवर्नर को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का सम्मान करना चाहिए। इसके बजाय वे समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से सीधे उनके पास शिकायतें और याचिकाएं देने की अपील कर रहे हैं। यह संवैधानिक परंपराओं और नियमों के विपरीत है।'

पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, इन सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे मतगणना भी कराई जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई तय की गई है। 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद ने कब दिया इस्तीफा?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस में बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिली है। इसकी शुरुआत विधानसभा से हुई और राज्यसभा से होते हुए लोकसभा तक पहुंची। पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो, सबसे पहल 8 जून को पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद 10 जून को सुष्मिता देव ने निजी कारणों से इस्तीफा

सौंपा फिर इसके एक दिन बाद 11 जून को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी पद का त्याग किया था। इनके कार्यकाल की बात करें, तो शुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक, सुष्मिता देव का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था।

गुजरात के मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा

चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह सीट भाजपा के आठ बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद 2 जून को खाली हुई थी। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना और पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया सीटों पर भी उपचुनाव

चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत जारी की है। आयोग के सचिव बिनोद कुमार ने चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किया। मंझलपुर उपचुनाव देश में हो रहे तीन विधानसभा उपचुनावों में शामिल है।

असम में कारोबार होगा आसान जमीन बिक्री के नियम बदलेंगे

- किन अहम विधेयकों को मिली मंजूरी?

गुवाहाटी। असम कैबिनेट ने रविवार को सात अहम विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार में आसानी) और MSME इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने वाले विधेयक प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इन सभी विधेयकों को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस के लिए एकीकृत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और अमूल के नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा।

किस कानून में संशोधन का प्रस्ताव?

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि मंजूर किए गए सात विधेयकों में असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 भी शामिल है। इस संशोधन के तहत धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास की जमीन केवल उन्हीं लोगों को बेची जा सकेगी, जिनके परिवार बरपेटा, बटाद्रवा और माजुली में पिछली तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को विधानसभा पहले ही पारित कर चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने पर केंद्र सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। अब उन सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित विधेयक दोबारा लाया जाएगा।

कारोबार शुरू करना कैसे होगा आसान?

कैबिनेट ने असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के कारोबार शुरू करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी, जिससे उद्यमियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

किसे मिलेगी बड़ी राहत?

मंत्रिपरिषद ने असम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ (स्थापना एवं संचालन में सुविधा) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण न फैलाने वाले क्षेत्रों में स्थापित होने वाली स्वस्थ इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक सरकारी मंजूरी के बिना ही संचालन शुरू करने की अनुमति होगी।

पर्यटन क्षेत्र में कैसे होंगे बदलाव?

कैबिनेट ने असम पर्यटन (विकास एवं पंजीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026

को भी मंजूरी दी। यह विधेयक होमस्टे, होटल और अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि औपनिवेशिक दौर का सराय अधिनियम समाप्त कर दिया जाएगा और उसके आवश्यक प्रावधान नए कानून में शामिल कर दिए जाएंगे।

जन विश्वास और सैटेलाइट सिटी पर फैसला

बैठक में असम जन विश्वास विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा भूमि पुनर्वर्गीकरण से जुड़े कुछ प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उन अटकलों पर विराम लगेगा, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सैटेलाइट सिटी परियोजना निजी कंपनियों को सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा, 'कई लोग कह रहे थे कि सरकार सैटेलाइट सिटी के विकास के नाम पर अडानी और अंबानी को जमीन देने जा रही है। अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस परियोजना का विकास सरकार स्वयं करेगी।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट समूह राज्य में निवेश करते हैं तो इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

डायल-112 के जरिए मिलेगा एकीकृत इमरजेंसी सिस्टम

कैबिनेट ने एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को एक ही तकनीक आधारित 24म7 प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। नागरिक केवल 112 डायल करके इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि डेरगांव स्थित लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में नया इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाया जाएगा। वहीं, असम पुलिस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम (डायल-112) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सी-डैक (C-DAC) की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले से ऐसी व्यवस्था लागू है और अब असम भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

2026 का 'लोकजतन सम्मान' वरिष्ठ संपादक राजेन्द्र शर्मा को

- 24 जुलाई को भोपाल में होगा आयोजन

भोपाल। इस वर्ष के 'लोकजतन सम्मान' से वरिष्ठ सम्पादक राजेन्द्र शर्मा (नई दिल्ली) को अभिनंदित किया जाएगा। राजेंद्र शर्मा लगभग आधी सदी से पत्रकारिता में हैं। 1979 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उन्होंने अपने आपको परिवर्तनकामी प्रतिबद्ध पत्रकारिता के प्रति समर्पित कर दिया था। जिस 'लोकलहर' से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उसके संस्थापक संपादक हरकिशन सिंह सुरजीत, उनके बाद सीताराम येचुरी के पश्चात अब वे लोकलहर के सम्पादक हैं। इसके अलावा वे सहमत, मुक्तनाद तथा अन्य संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों के संपादक भी रहे हैं। उनके अपने संपादन में 30 से अधिक किताबों का प्रकाशन हुआ है। उनके

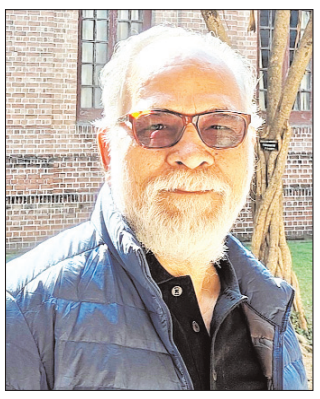

अपने लेखों के संकलन 'बहस अनंता', 'भूलने के विरुद्ध' तथा 'असत्य के प्रयोग' भी प्रकाशित हो चुके हैं, 'संस्कृति क्षेत्रे रणक्षेत्रे' प्रकाशनाधीन है। वे देशबंधु, राष्ट्रीय सहारा, जनवाणी, न्यूज़क्लिक जैसे कई समाचार माध्यमों के नियमित स्तंभकार हैं। पिछले कुछ समय से वे 'लोकजतन' में भी नियमित स्तंभ लिख रहे हैं। वे ऐसे पत्रकार-संपादक हैं, जो जटिल राजनीतिक विषयों पर सरल, सहज और चुस्त लेखन के अलावा राजनैतिक रिपोर्टिंग में व्यंग विधा का निबाह भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं।

यह सम्मान लोकजतन के संस्थापक-संपादक शैलेन्द्र शैली (24 जुलाई 1957- 07 अगस्त 2001) के जन्मदिन 24 जुलाई को दिया जाता है। इस सम्मान से ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता के आज के दुःसमय में भी सच बोलने और लिखने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस सम्मान से अभी तक डॉ. राम विद्रोही (ग्वालियर), कमल शुक्ला (बस्तर-रायपुर), लज्जा शंकर हरदेनिया (भोपाल), अनुराग द्वारी (भोपाल), राकेश अचल (ग्वालियर), पलाश सुरजन (भोपाल), शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर (बस्तर) आदि प्रमुख पत्रकारों को अभिनंदित किया जा चुका है।

52 पुरुष व 10 महिलाएं, रिजॉर्ट में पार्टी और अश्लीलता

- हर युवती को दिए 10 हजार; नैनीताल देह व्यापार का खुलासा

नैनीताल। नैनीताल के रामनगर के सांवल्दे स्थित एक्रोन रिजॉर्ट में शनिवार देर रात पुलिस ने देह व्यापार, शराब पार्टी और अश्लील गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 52 पुरुष और एक नाबालिग समेत 10 महिलाओं को पकड़ा है। इस दौरान रिजॉर्ट का महाप्रबंधक भाग गया। पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है। 52 लोगों के साथ ही रिजॉर्ट के जीएम के खिलाफ पॉक्सो, देह व्यापार समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

मुख्य आरोपी मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र के मुल्ताननगर निवासी उमेंद्र है। उसके साथ करीम नगर निवासी मेहराजुद्दीन भी पार्टी में शामिल था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उमेंद्र का मेरठ, बुलंदशहर सहित अन्य जगहों में कीटनाशक और कृषि उपकरणों से जुड़ा कारोबार है।

पुलिस के मुताबिक उसने कई प्रदेशों और विदेशों से युवतियों को पार्टी के लिए रिसॉर्ट में बुलाया था। मेरठ से उसने आनलाइन बुकिंग कराई थी। पूछताछ में उमेंद्र ने बताया कि उसकी बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भी कंपनी है जो कृषि से संबंधित उपकरण बनाती है। वह कंपनी से जुड़े लोगों को नैनीताल में मनोरंजन के उद्देश्य से लेकर गया था।

उसने दस दिन पहले रामनगर आकर एकरॉन रिसार्ट में दो लाख 20 हजार रुपये भी जमा कराए थे। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उमेंद्र नैनीताल में गलत गतिविधियों में पकड़ा गया है। मेरठ पुलिस से नैनीताल पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया।

इस्लामी दुनिया में दो फाड़... खामेनेई के जनाजे में नहीं पहुंचे 3 कट्टर मुस्लिम देश

नई दिल्ली। यह एक ऐसा दृश्य था, जिसकी ओर पूरी मुस्लिम उम्मा की निगाहें टिकी थीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडल पहुंचे. भारत के केंद्रीय मंत्री पहुंचे. चीन ने अपना विशेष दूत भेजा, रूस की ओर से वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे, तुर्की के उपराष्ट्रपति तेहरान पहुंचे, पाकिस्तान का तो पूरा कुनबा ही वहां था. मध्य एशिया के कई देशों ने भी शिरकत की. लेकिन इस भीड़ में तीन नामों की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी. ये तीन देश थे- संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और कुवैत.

ये तीनों देश न केवल मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं. विशुद्ध इस्लामिक देश होने के बावजूद इन 3 देशों ने आखिर मुस्लिम दुनिया के एक बड़े चेहरे को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा? लेकिन क्यों? वो भी तब जब दुनिया के कई देश तेहरान में मौजूद थे,

ये वो सवाल है जिसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की राजनीति, खाड़ी में मुस्लिम देशों के बीच की प्रतिद्वंद्विता और आपसी टकराव की कहानी छिपी है.

तीन कट्टर मुस्लिम देशों ने खामेनेई को नहीं दी श्रद्धांजलि

GCC की स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी. इसके कुल 6 सदस्य देश हैं. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान. इसकी स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम उम्मा समेत पूरी दुनिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम करना था. यहां यह भी जानना जरूरी है कि बहरीन को छोड़कर GCC के सभी 5 देश सुन्नी बहुल हैं, जब ईरान शिया बहुल

इस्लामिक राष्ट्र है. इसलिए भी इनके बीच प्रतियोगिता चलती रहती है.

बहरीन की कहानी थोड़ी अलग है. यह देश है तो शिया बहुल लेकिन यहां शासन सुन्नी अल खलीफा परिवार के पास है. इसलिए बहरीन का ईरान से तनाव रहता है. बहरीन की सुन्नी राजशाही लंबे समय से ईरान पर देश के शिया समुदाय को प्रभावित करने का आरोप लगाती रही है.

वहीं UAE और ईरान के बीच अबू मूसा तथा टुंब द्वीपों को लेकर पुराना क्षेत्रीय विवाद मौजूद है. कुवैत के संबंध अपेक्षाकृत संतुलित रहे हैं, लेकिन उसने भी हमेशा ईरान के साथ एक सावधानीपूर्ण दूरी बनाए रखी है.

लंबे समय तक ईरान और GCC के बीच संबंध अविश्वास, प्रतिस्पर्धा और धार्मिक वैचारिक टकराव से प्रभावित रहे. ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है, जबकि खाड़ी देशों को अक्सर लगता रहा है कि तेहरान अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अरब दुनिया में प्रभाव बढ़ाना चाहता है.

हाल के ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध के दौरान ईरान ने GCC के इन सभी 6 देशों पर अपने शाहेद ड्रोनों से तबाही मचा दी. तुलनात्मक रूप से ताकतवर माने जाने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर भी ईरान ने हमले किए. ईरान के इन हमलों के दौरान खाड़ी के देश असहाय और मजबूर बने रहे.

सबसे ज्यादा नुकसान UAE, कतर, कुवैत, बहरीन को हुआ. ईरान ने सऊदी में भी बम गिराकर उसकी औकात बता दी. ओमान को सीमित नुकसान हुआ.

UAE, बहरीन और कुवैत क्यों गायब रहे?

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में UAE, बहरीन और कुवैत की अनुपस्थिति महज एक प्रोटोकॉल संबंधी फैसला नहीं थी, बल्कि यह खाड़ी क्षेत्र की जटिल कूटनीति का संकेत भी थी. ऐसा करके UAE, बहरीन, कुवैत ने ईरान के हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है.

जंग में ईरान ने इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाया था. इससे इन देशों की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गईं. श्व की विदेश नीति अब 'सुरक्षा पहले' पर आधारित है. अबू धाबी ईरान को क्षेत्रीय खतरा मानता है और अपनी सुरक्षा के लिए इजरायल, अमेरिका के साथ सैन्य-आर्थिक गठबंधन मजबूत कर रहा है.

बहरीन लंबे समय से ईरान पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाता रहा है. बहरीन में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, इसलिए उसका झुकाव भी अमेरिका की ओर है.

कुवैत के संबंध अपेक्षाकृत संतुलित हैं, लेकिन वह भी ईरान के प्रति सतर्क नीति अपनाता है. इन तीनों देशों के लिए अमेरिका सुरक्षा का प्रमुख साझेदार है, इसलिए तेहरान में उच्च-स्तरीय उपस्थिति एक गलत राजनीतिक संदेश दे सकती थी.

ईरान ने इस अनुपस्थिति को 'अमेरिकी दबाव' से जोड़ा. तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका ने कई अरब देशों पर दबाव डाला. UAE, बहरीन और कुवैत ने इसे खारिज नहीं किया, लेकिन चुप्पी साध ली. अगर इन हमलों के बावजूद UAE अपना प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजता तो इससे संयुक्त अरब अमीरात की घरेलू राजनीति में गलत संदेश जाता. इससे ऐसा लगता कि. श्व ईरान के सामने झुक गया है, इसलिए ईरानी हमले झेलने के बावजूद ईरानी नेता को श्रद्धांजलि देने को विवश है. यहां बात सुन्नी और शिया विचारधाराओं के टकराव की भी बात थी.

स्वत्वाधिकारी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि.के लिए प्रकाशक सुभाष मिश्रा के लिए, मुद्रक नरेश मंगतानी द्वारा श्रीबालाजी प्रिंटर्स, 21 एच, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल म.प्र.से मुदित एवं एसआर-4-102, रुद्राक्ष पार्क फेस-1 बावड़ियां कलां, भोपाल, म.प्र.से प्रकाशित, प्रधान संपादक -सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक- भालचन्द्र जोशी, स्थानीय संपादक- अंशुमन खरे आरएनआई रजि. नं.RNI.NO.MPHIN/ 25/A3544 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।